तृतीय माला, खंड 47, अंक 8
Third Series, Vol. XLVII, No. 8

सोमवार, 15 नवम्बर, 1965/24 कार्तिक, 1887 (शक)
Monday, November 15, 1965/Kartika 24, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 47 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLVII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8—सोमवार, 15 नवम्बर, 1965/24 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 8—Monday, November 15, 1965/Kartika 24, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
210	पाकिस्तान आक्रमण से प्रभावित सीमान्त राज्यों को सहायता	Assistance to Border States Affected by Pak Aggression	627–629
211	चीन के वार्षिक समारोह में से पीकिंग में भारतीय कार्यदूत का उठकर चला जाना	Walk-out by the Indian Charge d'Affairs in Peking during China's Anniversary Celebrations	630–634
212	हिन्दुओं के भारत आने पर प्रतिबन्ध	Hindus debarred from coming to India	634–638
213	भारत-पाकिस्तान संघर्ष पर फिल्म	Film on Indo-Pak Conflict	638–640
214	आकाशवाणी के कार्यक्रम	A.I.R. Programmes	640–644

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
215	भारत के कब्जे में पाकिस्तानी क्षेत्र	Pak Areas under Indian Occupation	644
216	इण्डोनेशिया में भारतीय	Indians in Indonesia	644–645
217	मारिशस को स्वतंत्रता	Independence for Mauritius	645
218	अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन का स्थायी सचिवालय	Permanent Secretariat of Afro-Asian Solidarity Organisation	645–646
219	पाकिस्तान में हिन्दु	Hindus in Pakistan	646
220	20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में चीन द्वारा फिर सेना जमा करना	Remilitarization of 20 K.M. Demilitarised Zone by China	646–647
221	युद्ध-विराम का उल्लंघन	Cease-Fire Violations	647
222	मिग के कारखाने	MIG Factories	648
223	अणु अस्त्र	Nuclear Weapons	648

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
224	भारतीय नौ सेना के लिये पनडुब्बियां	Submarines for Indian Navy	649
225	सशस्त्र सेनाओं के लिये अपेक्षित फालतू पुर्जों में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Spare Parts for Armed Forces . . .	649–650
226	हिन्द महासागर में नौ सैनिक अड्डा	Naval Base in Indian Ocean	650
227	प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan	650
228	संयुक्त राष्ट्र सूचना कार्यालय	U.N. Office of Public Information	651
229	जवानों के परिवारों को सहायता	Relief to Families of Jawans .	651–652
230	अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी प्रचार	Pak Propaganda against India in Africa and Latin America .	652
231	आकाशवाणी के अधिकारियों का शत्रु देशों के साथ सम्पर्क	A.I.R. Officers' Contacts with Enemy Countries . . .	652–653
232	भारत-चीन विवाद में मध्यस्था	Mediation in Sino-Indian Dispute	653
233	कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त का कार्यालय	Office of Pak. Deputy High Commissioner in Calcutta .	653–654
234	पाकिस्तान-चीन संधि	Pak. China Treaty . .	654
236	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सिख लड़कियों तथा महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण	Forcible Capture of Sikh Girls and Women by Pak Army Personnel	654
237	पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयोग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of Officials of Indian High Commission, in Pakistan	654–655

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
525	सीमान्त सड़कें	Border Roads . . .	655–656
526	आकाशवाणी को पत्रिकाओं का मुद्रण	Printing of all India Radio Journals	656
527	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund . .	656–657
528	केरल में बेरोजगार लोगों का सर्वेक्षण	Survey of Unemployed Persons in Kerala . . .	657

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
529	केरल में डाक तथा तार कार्यालयों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण	Construction of P.&T. Offices and Staff Quarters in Kerala	657–658
530	केरल सर्किल में डाक-तार कर्मचारी	P. & T. Staff in Kerala Circle	658
531	विदेशी भाषाओं का साहित्य	Literature in Foreign Languages	658
532	उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग की इमारत	P. & T. Buildings in Orissa	659
533	डाक व तार निदेशालय, उड़ीसा	P. & T. Directorate, Orissa	659
534	भारत में संयुक्त अरब गणराज्य का चलचित्र समारोह	U.A.R. Film Festival in India	660
535	चीन में एक भारतीय राष्ट्रजन का अभिपीड़न	Persecution of an Indian National in China	660
536	नेफा में विमान दुर्घटनायें	Aircraft Accidents in NEFA	660–661
537	उड़ीसा में डाक सेवायें	Postal Services in Orissa	661
538	आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कलाकार	S.C. & S.T.A.I.R. Artists at New Delhi	662
539	उड़ीसा में टेलीफोन का राजस्व	Telephone, Revenue in Orissa	662
540	दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य देशनांक	Consumers Price Index Number for Delhi	662–663
541	परमाणु विज्ञान की प्रगति	Progress in Nuclear Science	663
542	नागा विद्रोहियों द्वारा गोलीबारी	Firing by Naga Hostiles	663
543	पूर्वी पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों को बर्मा से प्रव्रजन	Migration from Burma of Persons of East Pakistan Origin	664
544	लन्दन में भारतीय विद्यार्थी	Indian Students in London	664
545	पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान इमारतों को हुई क्षति	Damage to Buildings during Pak Aggression	664–665
546	सशस्त्र सेनाओं के वीरगति प्राप्त कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन	Pension to Dependents of Deceased Armed Forces Personnel	665

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
547	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income . .	665
548	भारी पानी का निर्यात	Export of Heavy Water .	666
549	टेलीप्रिंटर	Teleprinters . .	666
550	परमाणु विज्ञान सम्बन्धी आधारभूत अनुसन्धान	Fundamental Research in Nuclear Sciences . . .	667
551	वेली में प्रयोगशाला	Laboratory at Vell .	667
552	भारी पानी संयंत्र	Heavy Water Plant . . .	668
553	दिल्ली-नरेला-सोनीपत-बहादुरगढ़ सीधा टेलीफोन सम्बध	Delhi-Narela-Sonepat-Bahadurgarh Direct Telephone Link .	668
554	मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर	Atomic Power Station in M.P. .	668–669
555	संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भारतीय सशस्त्र सेना	Indian Armed Forces with U.N.	669
556	औद्योगिक विराम संधि	Industrial Truce	669
557	जवानों के परिवारों का कल्याण	Welfare of families of Jawans .	670
558	बांकुरा में बम विस्फोट	Bomb Explosion in Bankura .	670–671
559	भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference	671
560	दिल्ली में सैनिक बस्ती	Military Colony in Delhi .	672
561	कलपाक्कम में परमाणु बिजलीघर	Atomic Power Station at Kalpakkam.	672
562	खेतिहार मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Agricultural Labour	673
563	आकाशवाणी से समाचारों का प्रसार	News Broadcasts by A.I.R. .	673–674
564	पाकिस्तानी हमले के दौरान प्रचार कार्य के लिये आकाशावाणी के कलाकारों को इनाम	Reward For Propaganda Works during Pak Aggression to A.I.R. Artists	674
565	श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working and Non-working Journalists .	674
566	ई० एम० ई० वर्कशाप	E.M.E. Workshops . . .	674–675

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
567	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में समझौता वार्ता व्यवस्था	Negotiating Machinery in Defence Establishments . . .	675
568	पाकिस्तान द्वारा लाठीटीला क्षेत्र में गोलाबारी	Pak Firing on Latitilla Area .	675
569	शत्रु की कार्रवाई में मारे गये डाक तथा तार कर्मचारी	P.&T. Employees killed in Enemy Action . . .	676
570	चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन	Air Space Violation by China .	676
571	परमाणु बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की लागत	Cost of Power produced in Atomic Power Stations . .	676–677
572	गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास	Development of Goa as Naval Base	677
573	सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक	I.N.A. Memorial, Singapore	678
574	क्रास बार स्विज इक्विपमेंट	Cross Bar Switch Equipment .	678
575	खोई हुई वस्तुओं की क्षतिपूर्ति	Compensation for Lost Articles	679
576	मोटरगाड़ी परिवहन के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Motor Transport Workers	679
577	जनेवा में अवैतनिक कौंसिल	Honorary Consul in Geneva	679
578	प्रतिरक्षा योजना	Defence Plan .	680
579	अग्रिम क्षेत्रों में समाचारपत्र सम्वाद-दाता	Press Correspondents on Forward Areas	680
580	भारत का सैनिक सामान का नुकसान	Lo s of Military Equipment to ndi	681
581	पंजाब के डाकखानों में जमा रकम	Deposits in Post Offices in Punjab	681
582	जकर्ता में मारे गये छः जनरलों की अन्त्येष्टि	Funeral of Six Generals Killed in Jakarta	681
583	कारतुसों का निर्माण	Manufacture of Cartridges	682
584	कवि सम्मेलन	Symposium of Poets . .	682
585	अपक्षारीकरण (डीसेलिनाइजेशन) सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद	International Symposium on Desalinisation	682–683

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
586	भूपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Land for Ex-servicemen .	683
588	जिला मुख्यालयों में रेडियो स्टेशन	Radio Stations at District Head Quarters	683
590	हिन्दु मुस्लिम एकता	Hindu Muslim Unity .	683–685
591	भारतीय दूतावास तथा राजनयिक	Indian Embassies and Diplomats	685–686
592	सैनिकों के परिवारों का भरण पोषण	Maintenance of Families of Armed Forces . . .	686
593	हिन्दी में टेलीफोन डायरेक्टरी	Telephone Directory in Hindi .	686–687
594	आसाम पर जैट विमान जिसको पहचाना नहीं जा सका	Unidentified Jet Plane over Assam	687
595	डाक सेवायें	Postal Services	687
596	संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से बिना तार का संचार संपर्क	Wireless Link with UN Headquarters	687–688
597	रडार व्यवस्था	Radar System . .	688
598	जोधपुर का हवाई अड्डा और ट्रेनिंग कालिज	Jodhpur Airport and Training College	688
599	पंजाब में टेलीफोन केन्द्र तथा तारघर	Telephone Exchanges and Telephone Offices in Punjab .	689
600	टेलीफोन तार चोर	Telephone Wire Thieves . .	689
601	अग्रिम क्षेत्रों में आकाशवाणी के कलाकार	A.I.R. Artists in Forward Areas	690
602	संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैदेशिक कार्य मंत्री के भाषण	Speeches of Minister of External Affairs in U.N. General Assembly	690
603	केरल ग्रांधसाला संघम्	Kerala Grandhasale Sangham .	690–691
604	क्षेत्र-प्रचार अधिकारी	Field Publicity Officers	691
605	कोयला खानों के मजदूर	Labour for Coal Mines .	691–692
606	गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में नियुक्तियों के बारे में शिकायतें	Complaints about Appointments in Fertilizer Factory, Gorakhpur .	692–694
607	खानों का एकीकरण	Amalgamation of Mines .	694
608	पंजाब के औद्योगिक एकक	Industrial Unit in Punjab .	694
609	भारत द्वारा मान्य देश	States Recognised by India	695
610	ब्रिटेन के समाचार पत्रों के सम्वाददाता	British Press Correspondents	695

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
611	पर्वतीय डिवीजन	Mountain Division	695–696
612	पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग	Use of Abusive Language by Pakistan Foreign Minister .	696
613	समुद्री और औद्योगिक डीजल इंजन परियोजना	Marine and Industrial Diesel Engine Project . . .	696
614	सिक्किम के ऊपर अज्ञात विमान	Unidentified Plane over Sikkim .	697
615	रेडियो लायसेंस	Broadcast Receiver Licences .	697–698
616	हैदराबाद में वायु सेना अकादमी	Air Force Academy in Hyderabad	698
617	बीमाकृत पार्सलों का गुम हो जाना	Loss of Insured Parcels . .	698–699
618	विदेशों में फिल्म डिवीजन के कार्यालय	Offices of Film Division in Foreign Countries	699
619	सीमा क्षेत्रों में प्रचार	Border Publicity . . .	699–700
620	राज्यों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	State Labour Ministers' Conference	700–701
621	संयुक्त प्रबन्ध परिषदें	Joint Management Councils .	701
622	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी	Payment of arrears to Defence Personnel	701
623	बिना लाइसेंस रेडियो सेट	Pirate Radio Sets . . .	702
624	उड़ीसा में तकनीकी लोगों की बेरोजगारी	Unemployed Technical Persons in Orissa . . .	703
625	उड़ीसा में बेरोजगार स्त्रियां	Unemployed Women in Orissa .	703
626	आकाशवाणी के कटक केन्द्र के कलाकार	A.I.R. Artists at Cuttack . .	704
627	पाकिस्तान की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों के प्रति भारत के विरोधी पत्र	Indian Protests against Provocative Activities of Pakistan .	704
628	पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा बेलोनिया नगर में गोलीबारी	Firing by East Pakistan Rifles on Belonia Town . . .	705
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—		Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	
(1)	राजाबागान गोदीबाड़ा (डॉकयार्ड), कलकत्ता में बड़ी संख्या में मजदूरों की जबरी छुट्टी—	(i) Lay off of large number of workmen in Rajabagan Dockyard, Calcutta—	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	705
	श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur . .	705–707

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(2) सिक्किम सीमा के डोंग चुई ला स्थान पर चीनी आक्रमण—	(ii) Chinese aggression across Dongchui La on Skikim border—	
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	707
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan .	707–711
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table. .	711–712
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1965-66—	Demands for Supplementary Grants (Kerala) 1965-66—	
विवरण प्रस्तुत	Statement presented .	712
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-third Report	712
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report .	712
भारतीय राजकीय भेद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Indian Official Secrets (Amendment) Bill—Introduced . .	713
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	Motion re : International Situation—	
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swarn Singh . .	713–716
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani	717–719
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	Shrimati Renu Chakravarty	720–722
श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray .	722–724
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	724
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha	725
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	725–727
महाराजकुमार विजय आनन्द	Maharajkumar Vijaya Ananda . . .	727–728
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	728–730
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur . . .	730–732
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	732
नागा विद्रोहियों के साथ शान्तिवार्ता के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-An-Hour Discussion re : Peace Talks with Naga Rebels—	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua .	732–733
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	Shrimati Lakshmi Menon .	734

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 15 नवम्बर, 1965/24 कार्तिक, 1887 (शक)

Monday, November 15, 1965/Kartika 24, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित सीमान्त राज्यों को सहायता

+

*210. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री हेमराज :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित सीमांत राज्यों को क्षतिग्रस्त घरों को दोबारा बनाने के लिये तथा विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये राज्यवार कितना धन दिया गया है अथवा दिये जाने की संभावना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) : हाल के आक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास के लिये केन्द्रीय सरकार जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब और राजस्थान राज्य को वित्तीय सहायता दे रही है । राज्यसरकारों को कोई निश्चित आवंटन नहीं किया गया है लेकिन उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर निधि दी जा रही है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या यह सच है कि पंजाब और काश्मीर की अपेक्षा राजस्थान को कम सहायता दी जा रही है ; यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है ?

श्री त्यागी : दुर्भाग्य से ऐसा है लेकिन यह सब सम्बन्धित राज्य सरकार पर निर्भर करता है। वे व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो केवल जो वह खर्च करते हैं उसकी अदायगी कर देते हैं।

श्री भानु प्रकाश सिंह : क्या यह भी सच है कि उन व्यक्तियों का जिनके मकान घुसपैठियों ने गिरा दिये हैं, अनग्रहात् भुगतान किया गया है, यदि हां, तो अन्य राज्य में अन्य व्यक्तियों को भी ऐसे अनदान क्यों नहीं दिये गये हैं ?

श्री त्यागी : सामान्यत: भारत सरजार उन व्यक्तियों को, जिनके मकान आदि पाकिस्तान के हाल के आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं, अनुग्रहात् अनुदान देने को राजी हो गये है। इस प्रयोजन के लिये सभी व्यक्तियों के साथ, वे चाहे जम्मू तथा काश्मीर के रहने वाले हों, या राजस्थान अथवा पंजाब के, एकसा व्यवहार किया जायगा।

Shri Yashpal Singh : What is the provision for giving aid to agriculturists, whose crops have been damaged?

Shri Tyagi : Nothing has been fixed for crops but when agriculturists will go to their houses, they would be given some *ex-gratia* grant till the new crops.

Shri M. L. Dwivedi : Have the Government estimated about the expenditure involved on the repairing of houses damaged in the recent hostilities and the amount so far paid in Kashmir, Punjab and Rajasthan.

Shri Tyagi : So far only *ex-gratia* payments have been made for the repair of houses etc. Certain persons have come from such places which are not in the possession of Pakistan but whose houses were damaged by Pakistani bombing and to them persistence money has been given. It has been dcided that after they reach there it should be estimated as to how much money would he required for he repairs of their houses. After that they will be given money.

Shri M. L. Dwivedi : I had asked about property.

Shri Tyagi : Property will be estimated after going there.

श्री स० चं० सामन्त : इन राज्य सरकारों ने कितना धन मांगा था और उनको कितना धन दिया गया है ?

श्री त्यागी : अभी राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं के बारे में पूरे आंकड़े नहीं दे सकी है। हमने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि वे जो भी धन खर्च करेंगी, उसकी पूर्त्ति हम करेंगे।

श्री कपूर सिंह : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, क्या सरकार राज्य सरकार की बजाय जिला परिषदों को धन देने का काम सौंपेगी ?

श्री त्यागी : वास्तव में प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकारें इन परिवारों की सहायता और पुनर्वास के लिये स्वयं धन खर्च कर रही हैं और हम केवल उसका प्रतिदान कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे। सहायता दिये जाने के बारे में साम्प्रदायिक विचारों को दूर रखने के लिये क्या सम्बन्धित क्षेत्रों की जिला परिषदों को सीधे धन देने का काम सौंपा जायेगा ?

श्री० त्यागी : यह फैसला करना राज्य सरकार का काम है।

श्री प्र० के० देव : क्या सीमावर्ती राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में भी इस योजना को लागू किया जायगा क्योंकि इस युद्ध का अन्य क्षेत्रों पर भी असर हो सकता है ?

श्री त्यागी : ऐसी कोई मांग हमारे सामने नहीं आयी है।

Shri Hem Raj : So far the rough estimates received from Punjab Government are to the tune of a crores of rupees. They have also represented that the industrial units have been closed down and the unemployment has increased. Under these circumstances how much money has been given to Punjab by now ?

Shri Tyagi : Through Resettlement Directorate a sum of rupees two crores has been sanctioned for Punjab Government and more money will be sanctioned after making complete assessment. In the meantime the Punjab Government has already disbursed 36 lacs of rupees.

श्री नाथ पाई : पाकिस्तानी आक्रमण के बाद उनके पुनर्वास की बजाय क्या यह उचित नहीं होगा कि उनको (क) हथियार चलाने के लिये प्रशिक्षण दिया जाय और (ख) हथियार दिये जाएं ? क्या आप इस बारे में विचार कर रहे हैं ?

श्री त्यागी : जी, हां। सीमान्त क्षेत्रों में जनता को यथासंभव आत्म-रक्षा के लिये तैयार करने के लिये कुछ व्यवस्था की जा रही है।

श्री कपूर सिंह : क्या मंत्री महोदय का यह सुझाव है कि क्या नागरिक जनता सेना का सामना कर सकती है, चाहे उनके पास जैसे भी हथियार हों ?

श्री त्यागी : यह काम तो सेना का होगा।

श्रीमती अकम्मा देवी : पंजाब में खेमकरन और अन्य गांवों के शरणार्थी चाहते हैं कि उनको भूमि और रोजगार दिया जाए चाहे वह अस्थायी तौर पर ही दिया जाय और वो सहायता कार्यों के बजाय पुनर्वास चाहते हैं। क्या सरकार उनकी प्रार्थना पर गौर करेगी और इस पर तत्काल कार्यवाही करेगी ?

श्री त्यागी : जहां कहीं लोग विस्थापित हुए हैं और भूमि पाकिस्तान के कब्जे में है, हमें आशा है कि उस भूमि को शीघ्रही खाली कराना पड़ेगा और उन लोगों को वापस अपने घरों में जाने को कहा जायगा। यदि उनको वापसी में विलम्ब होता है तो कोई और व्यवस्था की जाएगी।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि युद्ध में कारखानों के बन्द होने से बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं कि ये कारखाने यथासंभव शीघ्र खुलें ताकि श्रमिको को फिर से रोजगार मिले ?

श्री त्यागी : उनके अधिक वुयादेश देने के लिये कदम उठाये गये हैं। इन कारखानों को दिये गये वुयादेशों के माल का डिलीवरी की अवधि बढ़ा दी गई है और दिये जा चुके वुयादेश की डिलीवरी विलम्ब को क्षमा कर दिया गया है और वुयादेश को रद्द नहीं किया जा रहा है और संभरण तथा निपटान महा-निदेशालय से पहले से वुयादेश देने का अनुरोध किया गया है। विलम्ब-शुल्क और नौभरण शुल्क माफ कर दिया गया है। कच्चे माल और तैयार माल के लाने ले जाने में शीघ्रता की गयी है और रिजर्व बैंक द्वारा उद्योग तथा व्यापार को उदारता से ऋण दिया जा रहा है।

चीन के वार्षिक समारोह में से पीकिंग स्थित भारतीय कार्यदूत का उठकर चला जाना

*211. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीकिंग में भारतीय मंत्री तथा कार्यदूत 30 सितम्बर, 1965 को चीन के वार्षिक समारोह के दौरान, काश्मीर तथा भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के बारे में चीन के प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में पीकिंग के 'ग्रेट हाल आफ़ दी पीपिल'' से उठकर चले गये थे, और

(ख) चीन के प्रधान मंत्री की इस टिप्पणी पर विरोध प्रकट करने के लिये तथा चीनी प्रचार का निराकरण करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालयमें राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने जो वक्तव्य दिये हैं और चीन को जो नोट भेजे हैं, उनमें काश्मीर तथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी आक्रमण के विषय में भारत पर लगाए गए चीन के आरोपों का कारगर ढंग से जवाब दे दिया है। इन वक्तव्यों तथा नोटों मे भारत-पाकिस्तान संघर्ष में चीन द्वारा दखल देने और संघर्ष का विस्तार कराने की कोशिश करने का पूरी तरह भंडाफोड़ कर दिया गया है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : चीन के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद न करने के सरकार के वास्तविकतावादी रुख की सराहना करते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर कार्यवाहक राजदूत की बजाय एक अधिकृत राजदूत को भेजने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सिंगापुर के उप-प्रधान मंत्री के जिन्होंने अभी हमारे प्रधान मंत्री से बात की है वक्तव्य को देखते हुए सरकार सिंगापुर की, जो भारतीय और चीनी संस्कृतियों का साझा केन्द्र है, सेवाएं इस्तेमाल करने के लिये क्या विशेष कदम उठाएगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है । सिंगापुर और चीन में कूटनीतिक संबंध नहीं है ।

श्री बासप्पा : पाकिस्तान के साथ चीन के गठजोड़ और सीमा-रेखा के अतिक्रमण और चीन के अल्टीमेटम को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे प्रतिनिधि को उस समारोह में जाने की इजाजत क्यों दी गयी और क्या भविष्य मे सरकार ऐसी बात नहीं होने देगी ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कूटनीतिक शिष्टता के अनुसार उनको जाना ही चाहिये लेकिन उनको अवसर देख कर वहां से उठ कर चले जाने की भी स्वतंत्रता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has the attention of the Government been drawn to the fact that Chinese have taken our soldiers in their custody and what special action has been taken for their release?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ये सब बातें इस प्रश्न से नहीं उठती हैं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि जब चीन काश्मीरी लोगों के लिये आत्म-निर्णय की मांग का पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है, हम तिब्बतियों के लिये आत्म-निर्णय की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सरकार को मालूम है कि यह पहला अवसर है जब भारतीय प्रतिनिधि को किसी समारोह में भारत और भारत सरकार की नीतियों के लिये अपशब्द सुनने पड़े हैं ? मैं जानना चाहती हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकारने ऐसे समारोहों में, जिनके बारे में यह मालूम है कि ऐसे अपशब्द कहे जायेंगे, भारतीय प्रतिनिधि द्वारा भाग न लिए जाने का दृष्टिकोण अपनाया है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं ।

Shri Bade : In view of attitude adopted by China so far and their aggression in Dongchu la, may I know why permanent instructions have not been issued to the Indian representative not to participate in any of their celebrations?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, हां ।

श्री रंगा : हम चीन से अपने राजनयिक सम्बन्ध क्यों नहीं तोड़ लेते ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रकार निर्णय नहीं हो सकता ।

श्री रंगा : वह कारण बतायें । **(अन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने हमारे राजनयिकों की चीन के समारोहों में भाग न लेने की एक बार नहीं बल्कि दो बार हिदायतें जारी की हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पीकिंग में भारतीय कार्यदूत ने दो बार जारी की गई भारत सरकार इन हिदायतों का उल्लंघन करके इस चीनी समारोह में भाग लिया और अपमानित हुए ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जब पीकिंग में हमारा प्रतिनिधित्व है, शिष्टाचार कहता है कि हमें भाग लेना चाहिये . . . .

एक माननीय सदस्य : यह कैसा शिष्टाचार है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह राजनयिक शिष्टाचार है और हमारे कार्यदूत इसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं थी कि वे ऐसा वक्तव्य देंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : बात दूसरी ही है । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे याद है यह कहा गया था कि यदि चीन के राजदूत से कोई निमंत्रण मिले तो हमें भाग नहीं ले जाना चाहिये लेकिन यदि किसी अन्य राजनयिक प्रतिनिधि की ओर से निमंत्रण मिले तो यह वांछनीय है कि हम भाग लें भले ही चीन को निमंत्रित किया गया हो । मुझे नहीं मालूम यदि यह ठीक बात है ।

श्री हेम बरुआ : आधे घंटे की चर्चा में यह बताया गया था । हमने अपनी बात के समर्थन में हिदायतें प्रस्तुत कर दी थीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : काहिरा में और पीकिंग में भी ।

श्री दिनेश सिंह : जिस उत्तर का आपने उल्लेख किया है वह चीनियों द्वारा आमंत्रित किये जाने पर अन्य देशों में भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा समारोहों में भाग लेने के बारे में था। यह प्रश्न तो चीन में हमारे प्रतिनिधियों द्वारा समारोहों में भाग लेने के बारे में है । दोनों में थोड़ा अन्तर है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पीकिंग में हमारे कार्यदूत ने बारबार भारत सरकार से प्रार्थना की है कि ऐसे भोजों में भाग न लेने के लिये उन्हें निश्चित आदेश दिये जाये तथा इसके बावजूद भारत सरकार ने ही ऐसे भोजों में भाग लेने और हर प्रकार का अनादर सहने के लिये उन्हें बाध्य किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार की यह नीति है तो सरकार नें अवश्य ही ऐसा कहा होगा ।

श्री दिनेश सिंह : हमारे प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को भेजी जाने वाली गोपनीय रिपोर्टों पर चर्चा करना मैं वांछनीय नहीं समझता हूं ।

श्री रंगा : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । न केवल काहिरा की घटना के बारे में बल्कि पीकिंग की घटना के बारे में भी हमें यह आश्वासन दिया गया था कि हिदायतें दी गई है । लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रतिनिधि ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से परामर्श किया और उसने उन्हें अपवाद रूप में भाग लेने की सलाह दी थी । यह बताया गया था । इसलिये ये हिदायतें गोपनीय नहीं हैं और सभा को इनकी पहले ही जानकारी दी जा चुकी है । उपमंत्री के तथाकथित गोपनीय हिदायतों की आड़ लेने पर मुझे आपत्ति है ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी मामले में सरकार ने हिदायतें दी हों या न दी हों निश्चित रुप से उत्तरदायी हैं और यदि माननीय सदस्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही गलत समझते हैं तो सरकार की आलोचना की जा सकती है। लेकिन इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि उसने राजदूत को क्या लिखा और उसका पाठ क्या था ? यदि वे कहते हैं कि यह नहीं बताया जा सकता तो मैं उन्हें बाध्य नही कर सकता ।

श्री रंगा : इससे पहले उन्होंने इन हिदायदों का उल्लेख किया था । मेरी समझ में नहीं आता कि हम उनका बिल्कुल उल्लेख क्यों न करें । गोपनीय बातों का उलेल्ख करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या चीन में हमारे प्रतिनिधि ने सरकार से प्रार्थना की थी कि ऐसे भोजों में भाग लेने के लिए उनसे नहीं कहना चाहिए। मेरे सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? मैं सदस्यों से पहले ही अनुरोध कर चुका हू कि वे सरकार और राजदूत के बीच पत्र-व्यवहार जानने पर जोर न दें । लेकिन सरकार जो भी करती है वह उसके लिए उत्तरदायी है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को छोड़कर कि सरकार और राजदूत के बीच क्या पत्र-व्यवहार हुआ, क्या हम इस बारे में तथ्य नहीं पूछ सकते कि क्या पीकिंग में हमारे राज-प्रतिनिधि--कार्यदूत अथवा अन्य कोई चीन सरकार के अशिष्ट व्यवहार से इतने खिन्न हुए हैं कि सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उन्हें ऐसे समारोहों में जहां हमारे देश का अनादर किया जाता है, भाग लेने से मुक्त कर दिया जाये ?

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान् यदि मैंने उप-मंत्री महोदय को ठीक सुना है तो उन्होंने किसी रिपोर्ट का उल्लेख किया था। क्या हम यह समझें, यह सभा यह समझे कि सरकार द्वारा भेजी गई हिदायतों अथवा रिपोर्ट अथवा सरकार और राजदूत के बीच पत्र-व्यवहार के गोपनीय होने की बात कही जा रही है ? यदि हिदायतों को गोपनीय माना जा रहा है तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इससे पहले काहिरा में किये गये अशिष्ट व्यवहार के मामले में हममें से जिन सदस्यों ने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की सूचना दी थी उन्हें हिदायतों की प्रति दी गई थी और मैं समझता हूँ कि उसकी प्रति अब भी हमारे पास है हम जानना चाहते हैं कि गोपनीय क्या है ?

श्री हेम बरुआ : माननीय उपमंत्री यह कहते हैं कि वहां पर हमारे राजकीय मिशन और हमारी सरकार के बीच जो भी पत्र व्यवहार हुआ वह गोपनीय है। मैं चीन के प्रधान मंत्री के सम्मान में काहिरा में दिये गये भोज में काहिरा में हमारे राजदूत के सम्मिलित होने के बारे में आधे घंटे की चर्चा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिदायतों की प्रतियां हमारे पास थी और हमने उनसे सरकार का अभिनन्दन किया था। तब सरकार ने उसके द्वारा काहिरा में हमारे राजदूत को भेजे गये केबलग्राम और इस विषय में जारी की गई हिदायते और काहिरा और नई दिल्ली के बीच पत्र-व्यवहार का विवरण दिया था। उस समय यह नहीं कहा गया था कि यह सब पत्र-व्यवहार गोपनीय है। इसलिए जब उनके अनुकूल बात होती है तो बता देते है और जब प्रतिकुल बात होती है तो उसे छिपा जाते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir, I do not want to comment on what communications took place between the Government and the ambassador. It appears that our Government have entrusted a part of the work relating to Chinese Affairs to Shri Dinesh Singh, a part to Shrimati Menon and some work to the Minister of External Affairs but the Prime Minister who should ensure proper coordination among them is nowhere, and the result is that different attitude is adopted on different occasions. Such a picture is presented before the people of India as if they want to destory China. The Government is divided in these four parts and is bringing its own ruin.

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार कुछ कहना चाहती है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री) : श्रीमान् जहा तक मुझे मालूम है पीकिंग स्थित हमारे प्रतिनिधि से हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है कि ऐसे सम रोहो में भाग लेने में उन्हें कोई विशेष कठिनाई होती है अथवा कोई ऐसी बात थी जिसके आधार पर ऐसा नियम बना दिया जाये कि ऐसे समारोहों मे उन्हे बिल्कुल भाग ही नहीं लेना चाहिए। सभी देशों में यह राजनयिक परिपाटी है कि किसी ऐसे विशेष देश में राजदूत, जिसके साथ उनके देश के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं, वे भी इन समारोहों मे जाते हैं और उपस्थित होते हैं तथा यदि उनके देश के विरुध्द कोई बात कही जाती है तो वे उठकर चले जाते हैं। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है जैसा कि उपमंत्री ने कहा निश्चित हिदायते है। लेकिन चीन के बारे में ऐसी कोई हितायतें नहीं है कि वे ऐसे समारोहों में भाग नहीं लेंगे। जो चीन द्वार आयोजित किया गया हो अथवा .....

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वे गोपनीय हैं ?

श्री हेम बरुआ : हिदायतें हैं और मैं उन्हें प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री लालबहादूर शास्त्री : यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य इसकी जांच करूंगा। जहां तक मुझे मालूम है, कोई स्पष्ट हिदायतें नहीं हैं।

श्री हेम बरुआ : अवश्य हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने अभी कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा। इस विशिष्ट मामले में जैसी प्रथा है, उन्होंने समारोह में भाग लिया और जब कुछ टिप्पणी की गई तो वे समारोह से उठकर चले आये।

श्री रंगा : इस दूतावास को बन्द क्यों नहीं कर देते ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं तो यह कहूंगा कि यह एक गलत बात होगी कि हम अपने प्रतिनिधि को ऐसे समारोह में भाग न लेने दें। आखिरकार उन्हें अन्य व्यक्तियों से कुछ सम्पर्क रखना पड़ता है और यह भी सम्पर्क रखने का एक साधन है। अतएव, ऐसा नियम बनाना उचित नही होगा कि वे ऐसे समारोहों में न जायें। **(अन्तर्बाधा)**

हिन्दुओं के भारत आने पर प्रतिबन्ध

+

*212. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री बागड़ी :

श्री मधु लिमये :

श्री रामसेवक यादव :

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के फरीदपुर तथा जैसोर जिले के लगभग 1000 हिन्दुओं को जिनमें स्त्रियां तथा बच्चे भी शामिल हैं, पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के सैनिकों ने पाकिस्तानी सीमा के निकट से उस समय वापस कर दिया जब वे भारत आने का प्रयत्न कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये हिन्दू प्रवजन प्रमाणपत्र लेकर भारत आ रहे थे जो उनको ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त द्वारा लगभग छः महीने पहले दिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उनके सुरक्षित भारत पहुंचने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग) : चूँकि पूर्व पाकिस्तान के साथ अभी संचार की सुविधाएं फिर से सुलभ नहीं हुई हैं, इसलिए इस विषय में आधिकारिक सूचना प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही, एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

श्री हिम्मतसिंहका : ऐसे मामले में पाकिस्तान सरकार के उदंड रवैये को ध्यान में रखते हुए क्या इसे रोकने के लिए सरकार का विचार कोई कदम उठाने का है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ये समाचार पत्रों की रिपोर्टें है जिनकी वास्तविकता का हम पता नहीं कर सके है न ही हमें राज्य सरकारों से कोई निश्चित जानकारी प्राप्त हुई है। जैसे ही उच्चायोग के ध्यान में कोई बात आयेगी निश्चय ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के विभाजन से अब तक 90 लाख हिन्दू भारत आ चुके हैं और साथ ही यह भी ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तानी सशस्त्र पुलिस अथा पाकिस्तानी सशस्त्र सेना द्वारा तंग किये जाने के कारण कभी कभी इन हिन्दुओं को सीमा पार करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्या पाकिस्तान से इन व्यक्तियों को बसाने के लिये कुछ राज्यक्षेत्र मांगने की सरकार की मंशा है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : On this issue the general thinking is how to rehabilitate those men properly. But when the minorities are oppressed there, they cross over here and it creates bitterness and spreads fanaticism and it weakens the very basis of a secular state. Whether the Government have considered the political aspect in the light of Nehru Liaqat Ali Pact? If this oppression continues it will be a ground for war like Kashmir. May I know whether Government will take such an action ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य द्वारा बताई गई ज्यादतियों के बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली है । मैं बता चुकी हूँ कि ढाका में हमारे उच्चायोग को भी उचित संचार सुविधा सुलभ नहीं है । दो या तीन दिन पहले ही संचार व्यवस्था पुन: चालू हुई है । जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

Shri Madhu Limaye : I had raised some other point. Prime Minister is there, he should reply. I had referred to Nehru Liaqat Ali Pact.

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : It is not quite proper to raise this issue as we are already engaged with Pakistan with lot of conflict and fighting. It is very difficult even to say we can prevent them from subjecting to any treatment of course, it is necessary to lodge a protest, apprise them of our views and we shall certainly do that but I have no comments to offer on the statement that it should be treated as a ground for war.

Shri Madhu Limaye : It cuts the roots of secular State and encourages Communalism.

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान में भारतीय मिशन का सामान्य रूप से कार्य करना असंभव हो गया है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार आगे क्या कदम उठाने का है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि हमें कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार के पास पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिये गये प्रव्रजन प्रमाणपत्रों का कोई रिकार्ड है और यदि उन्हें अब आने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या सरकार उन प्रमाणपत्रों की अवधि बढ़ाने की अनुमति देगी ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी हां, इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रमाणपत्रों की अवधि बढ़ाई जायेगी ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय ने इस प्रश्न की सूचना प्राप्त होने के बाद वहां पर हमारे प्रतिनिधि से पूछताछ की है ; यदि हां, तो क्या यह कथन कहां तक सच है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य ने मेरे पहले उत्तर को नहीं सुना। आसाम और पश्चिमी बंगाल की सरकारों तथा उच्चायोग के साथ भी बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं; लेकिन, जैसा मैंने बताया उच्चायुक्त हाल ही में हमसे सम्पर्क स्थापित कर सके क्योंकि संघर्ष के परिणामस्वरूप ये सुविधाओं उनसे छीन ली गई थी।

Shri Prakash Vir Shastri : A report had appeared in the newspapers on behalf of the Government of India three or four days ago that after the partition the percentage of Hindus in Pakistan numbering 1,90 lakhs at the time of partition has gone down considerably whereas the number of 'yavan'—Muslims in India has gone up from 3 crores to about 5 crores. May I know if the Government have inquired whether the percentage of Hindus in Pakistan has decreased as a result of their killing or due to conversion?

श्री ही० ना० मुखर्जी : श्रीमान्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने 'यवन' शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का विशेष आशय होता है, जिसमें विदेशियों के प्रति घोर घृणा का भाव सन्निहित है। मैं समझता हूं कि इस सभा में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

Shri Madhu Limaye : Sir, the word 'Yavan' refers to greeks i.e. the residents of Ayonia but all the muslims here in India or residing in Pakistan are 'Hindustani'.

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, 'यवन' शब्द जातीय परायेपन का द्योतक है और इसका आशय एक पाश्चात्य व्यक्ति है जो आर्य जाति का नहीं है, जबकि मुसलमान हमारे अपने भाई-बन्धु हैं। इसलिए उनको 'यवन' नहीं कहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इसपर आप विनिर्णय दें।

श्री बड़े : श्रीमान्, मेरी समझ के अनुसार 'यवन' कोई खराब शब्द नहीं है। एक गैर-हिन्दु को, जो मुस्लिम हो, 'यवन' कहते हैं। 'मलेच्छ' शब्द घृणास्पद है। उन्होंने उस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने तो 'यवन' कहा है। मराठी तथा संस्कृत में इस का प्रयोग होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री बड़े ने कहा है 'यवन' गैर-हिन्दु होते हैं। क्या इस में सिख भी आते है?

श्री बड़े : सिख हिन्दु ही हैं। हिन्दू कानून सिखों पर भी लागू होता है।

Mr. Speaker : Objection was taken on one word 'yavan' and a discussion started. I would have asked him not to use that word.

Shri Prakash Vir Shastri : If it is so, I withdraw that word.

Mr. Speaker : The suggestion by some Hon. Members that use of the word 'yavan' was not proper and the efforts to go into merits and demerits by five or six scholars and to trace its history and entire philosoply creates difficulty for me. Small things should not be given so much prominence.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : श्रीमान्, मैं प्रश्न समझ नहीं पाई। शायद उन्होंने यह कहा है कि धर्म परिवर्तन के कारण संख्या में कमी हो गई है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि कमी हो गई है और वह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है या उन्हें बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। इसके क्या कारण हैं?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : बहुत बड़ी संख्या में धर्म-परिवर्तन होने के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। एक दो ऐसे मामलों की सूचना हमें अवश्य मिली है। इस के अतिरिक्त हिन्दु धर्म से बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बनाये जाने का समाचार हमारे पास कोई नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, my question was.....

Mr. Speaker : You give a notice for half an hour's discussion.

Shri Prakash Vir Shastri : Very well, Sir.

श्री बसुमतारी : हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रजन, जो भारत में घुस आये थे, आसाम से भेजे गये हैं और पाकिस्तान ने उन्हें फिर वापिस भेज दिया है। इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है। उन घुसपैठियों के बारे में मुझे ध्यानाकर्षण सूचना दी गई थी, जो कि भारत में घुस आये हैं और उन्हें हम वापिस भेजना चाहते हैं और भेज रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री बसुमतारी : आज के समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है जैसा कि आसाम के एक मंत्री महोदय ने बताया है कि पाकिस्तान के हिन्दू तथा ईसाई अल्पसंख्यक वर्ग गोरी पहाड़ियों के रास्ते चोरी छिपे आसाम में आ गये हैं, क्या सरकार ने इस बात का प्रचार किया है कि भारत से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया है, जबकि सैकड़ों की संख्या में हिन्दू तथा ईसाई पाकिस्तान से भारत में आये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें केवल आसाम तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से जानकारी मिलती है। उन से हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली है। इसी लिये मैंने कहा है कि जानकारी प्राप्त करके सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न था कि इस का प्रचार क्यों नहीं किया गया।

Shri Rameshwaranand : Pakistan Government is not prepared to take back the infiltrators and Hindus are being pushed out of Pakistan or being killed there. It is clear from the newspaper reports. May I know what are Government's authentic sources of information, if they do not believe in newspaper reports ?

Mr. Speaker : She has said that State Governments supply information.

Shri Rameshwaranand : She has stated that there was no liasion with our High Commissioner there at present and that efforts would be made to get the information from State Governments. How could it be believed that they get correct information from them.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या निरन्तर किये जा रहे उस रेडियो प्रसारण की ओर सरकार का ध्यान गया है, जो कि कथित पूर्व बंगाल विप्लवी रेडियो स्टेशन से किया जा रहा है ? उस में कहा जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान के नागरिक कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर हिन्दू-मस्लिम झगड़े न हों। क्या यह बात सच है और क्या सरकार इस संगठन को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के बारे में सोच रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह ठीक है और हमने क्रान्तिकारी परिषद् के प्रसारण सुने हैं कि वह पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक झगड़ों को रोकने की कोशिश कर रही है। हम समाचार पत्रों की बात को मान्यता नहीं दे सकते। इसीलिये मैंने कहा है कि हमें ठीक जानकारी मिलनी चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know from the Prime Minister whether he is aware that Mahatma Gandhi had given an assurance about the protection of minority communities that we would resort to war if their lives cannot be saved otherwise?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : I do not remember. I have not seen.

Film on Indo-Pak Conflict

+

*213. **Shri Madhu Limaye :** **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Bagri : **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Dr. Ram Manohar Lohia :**

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to produce a film based on Pakistani attack;

(b) whether any such scheme has been formulated;

(c) if so, the progress made in this direction; and

(d) whether this film will be sent to foreign countries also?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Five films have been produced by the Films Division and six films are under production. In addition, the weekly newsreel "Indian News Review" has been carrying news items which have a direct or indirect bearing or Pakistan's aggression. Three films on subjects connected with the present Emergency have also been completed by the Films Division and three are under production.

(d) Selected films will also be sent to foreign countries.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether the Government would demonstrate in its new films that the present conflict is between two brothers, one of whom is under Ayub Khan's regime and whether this fact would also be depicted that although Hindus and Muslims embrace different religions, but they have same citizenship and that they belong to different states but their nation is one?

Shrimati Indira Gandhi : This idea is embodied in our films.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether these films will show that the past history of India of seven or eight hundred years depicts a conflict between foreign aggressors and Indian people.

I also want to know whether the films will depict the fact that this conflict is not between Hindus and Muslims and if the Country is to be strengthened the backward classes and the depressed minority communities among the muslims should be offered special opportunities for making progress, and that a secular state should be established?

Mr. Speaker : These things may also be taken into consideration.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इन फिल्मों को रिलीज़ करने में सरकार ने विलम्ब क्यों किया है और अन्तर्निहित प्रश्नों को दर्शाने वाले एक पूर्ण प्रलेखीय चलचित्र क्यों नहीं बनाया गया है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : एक फिल्म 'तब और अब' रिलीज़ हो चुकी है और देश के मुख्य सिनेमा घरों में दिखाई जा चुकी है। इस संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को 'भारतीय समाचार समीक्षा' में दिखाया गया है। और फिल्में बनाई जा रही हैं। यह ठीक है कि कुछ विलम्ब हुआ है और उस के लिये मैं क्षमा चाहती हूं। परन्तु इसमें पूरी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। कैमरामैनों के लिये युद्धक्षेत्र में जाकर चित्र लेना कठिन होता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पूर्ण प्रलेखीय चित्र के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह शीघ्र ही किसी भी दिन रिलीज़ कर दिया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : The Govt. have removed those captured Pakistan tanks which were made in America, from the scene on the request of American Government, and have not allowed the people to see them. I want to know whether this sort of thing is not there in the case of these films.

Shrimati Indira Gandhi : Tanks have been shown in the films and it is clear from them that they are of American make.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to know whether these facts would be shown in these films that Indian forces, had entered Mughalpura, a suburb of Lahore, as was mentioned in our Government reports from 7 to 10 September? Will this also be depicted in the films that the Indian forces had then damaged Lahore radio station and were to enter Lahore when it was considered on the 11th September that we should not capture Lahore so that we were not made to feed population of 20 lakh people?

Shrimati Indira Gandhi : Films are not concerned with this.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I want your help. If the films are not concerned with this, what is it then with which they are concerned?

Mr. Speaker : Most of the questions put by the Hon. Members are actually suggestions that such things should be included in the films. The Minister can only say that she has noted the suggestions for consideration and would see also what can be included in the films.

Dr. Ram Manohar Lohia : I want to know whether these films would be based on facts or they will just show artificial things by deleting certain facts and distorting certain facts and by adding certain other things?

Shrimati Indira Gandhi : If he sees films, he will himself know about them.

श्रीमती विमला देशमुख : क्या ये फिल्में देहातों में भी दिखाई जायेंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारी सभी फिल्में नगरों तथा देहाती क्षेत्रों में दिखाई जाती हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : बहुत से देशों में हमारे दृष्टिकोण को ठीक प्रकार समझा नहीं जाता। क्या मंत्री महोदय 'डोगराई की लड़ाई' जैसे चित्रों को विदेशों में भेजने का विचार कर रही हैं, ताकि हमारे दृष्टिकोण को वहां पर ठीक प्रकार से समझा जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : पहले इनको बन जाने दीजिए। उसके पश्चात् विदेशों में भेजने का काम कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या इन आरोपों के बारे में कि इन फिल्मों में सिखों के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है, माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित हुआ है ; और यदि हां, तो . . .

श्री रघुनाथ सिंह : नहीं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री कपूर सिंह : ये आरोप खुले आम लगाये गये हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : जी, नहीं।

श्री कपूर सिंह : क्या इस के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री रघुनाथ सिंह : यह उचित नहीं है। इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री कपूर सिंह : माननीय मित्र सभी चीज़ें निकलवाना चाहते हैं। यहां पर निकालने की कोई बात नहीं है। क्या इन आरोपों पर ध्यान दिया गया है और इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में इस आरोप में कोई सचाई नहीं है। मैंने पहले यह बात नहीं सुनी है। वास्तव में प्रधान मंत्री से लेकर सभी मंत्रियों तथा अन्य सभी लोगों ने देश के सिख जवानों के कार्य की पूरी पूरी प्रशंसा की है।

श्री कपूर सिंह : आप को पूरी जानकारी नहीं है।

A. I. R. Programmes

+

***214. Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri S. C. Samanata :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Parashar :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. N. Chaturvedi :**
Shri Suboodh Hansda :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of English Programmes were broadcast from the All India Radio during the recent Indo-Pak conflict;

(b) whether it is also a fact that the listeners of the programmes in Indian languages were not much benefited from the special programmes relayed; and

(c) whether it is also a fact that the broadcasts could not be made useful during the period of hostilities due to dearth of talent?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) No, Sir. In the context of the total number of hours of progrmmes broadcast by All India Radio and the time devoted to programmes in Indian languages, the number of English programmes broadcast from All India Radio during the Indo-Pakistan conflict was not large.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri : Apart from the negligence shown towards the important news during the emergency period, may I know whether the percentage ascertained in this connection is a ratio between the programmes broadcast in English and those in all the Indian languages put together or it has been reckoned in respect of each languages separately?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : इस सम्बन्ध में हमने एक विवरण तैयार किया है। देशान्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित 62 समाचार बुलेटिन होते हैं जिनमें से अंग्रेजी में केवल 9 हैं। जहां तक दिल्ली केन्द्र का सम्बन्ध है, 12 वार्ताएं अंग्रेजी में थी और 23 हिन्दी, उर्दू तथा अन्य विभिन्न भाषाओं में थीं।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that the main features are prepared in English and then translated into other languages, and if so, whether the translated features are also not relayed through on the Stations of All India Radio; and the Hindi features are broadcast by All Indian Radio only and are not relayed on other Hindi Stations like Lucknow, Patna and others?

Shrimati Indira Gandhi : Yes, Sir. The features were first written in English and then translated into Hindi. But a large number of such features was written in Hindi also. It was, no doubt, a fact that those who drafted them in English were very quick in submitting them and those who used to write them in Hindi were not in Delhi at that time. In spite of that we received cooperation from a large number of the talented persons and that was utilised also.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether it is a fact that the news regarding the death of shri Balwantray Mehta, the former Chief Minister of Gujarat, who was victim of the Pakistan aggression, was broadcast in English at the end of the news or if so, the reasons therefor?

Shrimati Indira Gandhi : I am not aware of it.

Shri M. L. Dwivedi : How for it is a fact that the Ministry of Information and Broadcasting had issued instructions or sent a circular to the Heads of Departments and All India Radio that the use of the language easily followed by the listeners in Bengali, Gujarati, Maharashtrian, Tamil, Telgu and Malayalam speaking state might be discontinued and such other words may be added therein which were liked by the people in Delhi?

Shrimati Indira Gandhi : No, Sir.

श्री स० चं० सामंत : संघर्ष के दौरान अंग्रेजी कार्यक्रमों के प्रयोग के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं समझती कि हमारे पास कोई शिकायत आई है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : प्रधान मंत्री महोदय का महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट पहले अंग्रेजी में और तत्पश्चात् हिन्दी में क्यों किया गया, जब कि हिन्दी में, जो कि राष्ट्रभाषा है, श्रोताओं की संख्या अंग्रेजी के श्रोताओं से कहीं अधिक है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ब्रॉडकास्ट की भाषा बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है।

श्री पें० वेंकेटासुब्ब्या : क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारत से बाहर रहने वाले लोग हमारे उद्देश्य को समझ सकें और सरकार एक प्रकार की भाषाई उलझन का शिकार न बने, सरकार यह महसूस करती है कि आकाशवाणी से इन कार्यक्रमों का अंग्रेजी में प्रसार करना आवश्यक है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम सभी भाषाओं के माध्यम से प्रसार करने में विश्वास रखते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार ने आकाशवाणी के सम्वाददाताओं को युद्ध संबंधी समाचार प्राप्त करने के लिये युद्ध स्थल पर भेजा था ? ऐसे कितने सम्वाददाता भेजे गये थे और उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं आंकड़ों का पता लगा सकता हूं। बहुत से सम्वाददाता वहां गये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि अल्प-कालीन किन्तु ऐतिहासिक सितम्बर-युद्ध के दौरान आकाशवाणी द्वारा दक्षिणपूर्व एशियाई देशों तथा अफ्रीकी देशों के लिये प्रसारित कार्यक्रम कमज़ोर थे तथा रेडियो पर अच्छी तरह सुनाई नहीं देते थे क्योंकि ट्रान्समीटर काफी शक्तिशाली नहीं थे, अतः पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ हद तक यह बात सच है। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, हमारे पास अभी तक काफी शक्तिशाली ट्रान्समीटर नहीं हैं और जब तक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित उन देशों नहीं हो जाते, तब तक हमारे कार्यक्रमों में ये त्रुटियां बनी रहेंगी।

Shri U. M. Trivedi : May I know whether it is a fact that during the last conflict such persons were also allowed to broadcast, who had cursed our Government of giving incorrect news that the number of the killed on our side was comparatively large than the number broadcast by our Govt. ?

Shrimati Indira Gandhi : There might be some case of that nature, but our policy is to give opportunity to every individual whosoever wants to speak. If somebody makes a wrong statement we can later on contradict it.

Shri Yashpal Singh : Whenever we have to cut jokes with a person, we say 'building castles in the air'. But unfortunately the Hawa Mahal Programme of All India Radio continued even during the period of recent conflict with Pakistan. I want to know when 'Hawa Mahal' this programme will be discontinued ?

Mr. Speaker : Prof. Ranga.

श्री रंगा : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था, किन्तु अब मैं इसे अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछूंगा। माननीय मंत्री महोदय ऐसा क्यों कह रही हैं कि आकाशवाणी से बोलते समय संभवत: कोई व्यक्ति ऐसी गलती कर बैठा हो ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में वास्तविक रूप से जांच करके यह मालूम करेगी कि ऐसी भयंकर गलती किसने की है और उस व्यक्ति को उपयुक्त चेतावनी देगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आकाशवाणी के किसी कर्मचारी ने ऐसा नहीं किया है। बाहर के किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया था।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई है। जहां तक हमारी जानकारी है, आकाशवाणी में यह प्रथा है कि उन्हें लाइव ब्राडकास्टों के अतिरिक्त, जो उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं, जिन पर हमें पूर्ण विश्वास हो, अन्य सभी वार्ताओं के पाठ के सम्बन्ध में पूर्व सूचना देनी पड़ती है, तो ऐसे संकट कालीन समय में जब कि देश भारत-पाक संघर्ष से गुजर रहा था, मंत्री महोदय यह कैसे कहती हैं कि केवल एक मामले में झूठी बातें कही गई थी और हमारे देश के विरुद्ध अवमानजनक आरोप लगाय गये थे। मंत्री महोदय केवल इस तर्क की आड़ में कैसे बच निकलती है कि वह एक आमंत्रित वार्ताकार था, जिसे संकट-कालीन स्थिति में देश पर कीचड़ उछालने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने कुछ अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया है।

श्री रंगा : वह व्यक्त कौन था ?

एक माननीय सदस्य : वह फ्रैंक मौरेस थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हो सकता है कि वह मिस्टर मौरेस हों, किन्तु मुझे याद नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि हमें किसी को भी बोलने की पूरी आजादी नहीं देनी चाहिये, किन्तु मैं निश्चित रूप से यह समझती हूं कि चर्चा के दौरान यदि कोई बात उठायी जाती है और उस बात का अन्य तर्कों द्वारा खण्डन कर दिया जाता है तो यह कानाफूसी की अपेक्षा कहीं अच्छी है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं क आकाशवाणी द्वारा प्रायोजित लाइव ब्राडकास्टों के सम्बन्ध में की जाने वाली चर्चा के लिए वार्ता के पाठ की पूर्व काट-छांट आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि ऐसी चर्चा में खुले आम भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा तर्कों का खन्डन किया जाता है। लेकिन किसी अन्य समय पर ऐसी किसी वार्ता के लिये, जो कि आम चर्चा से सम्बन्धित न हो, सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को वक्तव्य दे कर चले जाने की अनुमति दिया जाना स्वत: उसके लिए अत्यधिक खतरनाक तथा शरारतपूर्ण पद्धति है--क्योंकि ऐसे वक्तव्य का बाद में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभावी रूप से खण्डन किया जाना कठिन भी हो जाता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस तर्क का खण्डन किया गया था और तत्पश्चात् हम और अधिक सावधान हो गये।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ी विचित्र बात लगती है कि ऐसे संकट काल में हम स्वत: अपने रेडियो से ऐसी चर्चाओं की अनुमति दें--जब कि दुश्मन उससे लाभ उठा सकता है। जब वास्तव में लिपि पहले दी गई है, तो आकाशवाणी में कार्य करने वाले हमारे कर्मचारियों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे उसे देख लेते कि उसमें क्या लिखा है (**अन्तर्बाधायें**) क्या लिपि पहले नहीं दी गई थी ?

श्री हेम बरुआ : हमें इस वार्ता को सुनने का अवसर मिला था और वह देशभक्ति की भावनाओं से ओत-प्रोत थी...(**अन्तर्बाधायें**)।

Shri Madhu Limaye : Sir, I request that question Nos. 215 and 238 may be taken up as they are very important.

Mr. Speaker : I cannot take them now after the question hour unless the hon. Minister is himself willing to do so.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Pak. Areas under Indian occupation

***215. Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Yogendra Jha :**
Shri S. C. Samanta : **Shri T. Ram :**
Shri Gokulananda Mohanty : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government for the administration of the Pakistan areas occupied by the Indian Forces; and

(b) the arrangements being made to look after the goods and property seized in these areas?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) and (b). Territory of Pakistan occupied by Indian forces continues to remain in Army control. No civil administration as such has been set up as the areas are generally free of civil population. No civil arrangements are accordingly yet deemed necessary.

इण्डोनेशिया में भारतीय

***216. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मरंडी : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री उटिया : **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डोनेशिया में रहने वाले भारतीयों के लिये परिस्थिति में सुधार हो गया है और क्या उनकी जान माल सुरक्षित है;

(ख) क्या यह सच है कि इन्डोनेशिया में रहने वाले सभी भारतीयों की आस्तियों पर अधिकार करने के लिए इण्डोनेशिया सरकार ने प्रारम्भिक कदम उठाया था; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है तथा इण्डोनेशिया में भारतीयों के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाय गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां। हाल में इन्डोनेशिया में भारतीयों के विरुद्ध किसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) इन्डोनेशिया सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके जरिये भारतीय राष्ट्रिकों की तमाम फर्में, अचल संपत्ति और सिक्योरिटियां सरकार के अधीक्षण में रख दी गई है।

(ग) भारत सरकार ने इन्डोनेशिया की सरकार से अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इन्डोनेशिया में भारतीयों की तथा उनकी संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन मांगा था।

मारिशस को स्वतंत्रता

*217. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में मारिशस को स्वतंत्रता मिलने वाली है; और

(ख) मारिशस के साथ हमारे सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, 1966 में।

(ख) पोर्ट लुई में भारत के प्रतिनिधि के रूप में एक कमिश्नर रहता है, और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में मारिशस के साथ हमारे पहले ही से निकट संबंध हैं। एक-दूसरों के यहां आ-जाकर और अपने आर्थिक तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग करके इन संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन का स्थायी सचिवालय

*218. **श्री मरंडी :**
श्री उटिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के अनुरोध पर सितम्बर, 1965 में अफ्रीकी-एशियाई एकता संगठन के स्थायी सचिवालय की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या चीन ने बैठक में काश्मीर की जनता के लिए आत्म-निर्णय की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बैठक में भाग लेने वाले अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चीन की प्रार्थना पर काश्मीर संबंधी बातचीत करने के लिए किसी विशेष बैठक की आयोजना नहीं किया गया हालांकि यह सवाल 28 सितम्बर, 1965 को आयोजित की गई नियमित बैठकों में से एक बैठक की कार्यसूची पर था।

(ख) जी हां।

(ग) एकता संगठन में, जो कि एक गैर-सरकारी संस्था है, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं है। चीनी प्रतिनिधि जब पाकिस्तान के झूठे दावे का समर्थन करने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं तो सरकार उनकी इन कार्रवाइयों की भर्त्सना करती है।

(घ) अन्य सदस्यों ने चीनी वक्तव्य के मसौदे का समर्थन नहीं किया। काश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से तय करने के बारे में संगठन के महासचिव ने पहले जो वक्तव्य जारी किया था, उसका समर्थन किया गया।

Hindus in Pakistan

*219. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Gulshan :
Shri Buta Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. C. Borooah :
Shri P. L. Barupal :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Brij Raj Singh :
Shri Gokaran Prasad :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the reports published in newspapers that Hindus are being persecuted in Pakistan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action being taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). In view of extremely restricted communications between Pakistan and India, it has not been possible to verify newspaper reports on the subject. Efforts are however being made to obtain authentic information.

20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में चीन द्वारा फिर सेना जमा करना

*220. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने लद्दाख में 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में वस्तुत: फिर सेना जमा कर ली है;

(ख) क्या यह कोलम्बो प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है; और

(ग) क्या कोलम्बो राष्ट्रों को इस बारे में सूचना दे दी गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) 21 सितंबर, 1965 को भारत सरकार ने दिल्ली-स्थित कोलम्बो देशों के प्रतिनिधियों को एक जबानी नोट (नोट वर्बल) दिया जिसमें उनका ध्यान भारत की उत्तरी सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति की ओर दिलाया गया जो कि चीन की जानबूझकर और अकारण की गई आक्रमक कार्रवाइयों से उत्पन्न हुई है। उसमें यह भी बताया गया कि चीन ने लद्दाख में 20 किलोमीटर क्षेत्र में फिर से सेना लाकर कोलम्बो प्रस्तावों की सिफारिश 2 (क) का स्पष्ट उलंघन किया था।

युद्ध-विराम का उल्लंघन

*221. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध-विराम को प्रभावी बनाने के लिए हाल में नियुक्त किये गये संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों को अब तक युद्ध-विराम के उल्लंघन की कितनी घटनाओं की सूचना दी है;

(ख) कितनी घटनाओं के लिए (1) भारतीय, और (2) पाकिस्तानी सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रेक्षकों ने पाकिस्तान की उत्तेजनात्मक तथा शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की उपेक्षा करके, जिनमें युद्ध-विराम रेखा पार करके सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई घुसपैठ भी शामिल है, इन उल्लंघनों के लिए अधिकांशत: भारत को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री(श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) 10 नवम्बर, 1965 तक प्राप्त हुई, रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम के 652 उल्लंघनों की यू० एन० आई० पी० ओ० पी० को, और 614 की यू०एन० एम० ओ० जी० आई० पी० की रिपोर्ट कर दी गई है। पाकिस्तान द्वारा रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों की संख्या अभी ज्ञात नहीं हो पाई।

(ख) से (घ) : हमारे द्वारा यू० एन० आई० पी० ओ० एम० / यू० एन० एम० ओ० जी० आई० पी० को की गई शिकायतों के निर्णय, अभी हमें नहीं बताए गए। तदपि, यू० ए० महासचिवने भारत और पाकिस्तान के दर्मियान, युद्ध विराम पालन के संबंध में, कुछ रिपोर्ट जारी की हैं। यह रिपोर्टें इस अर्थ में व्यापक नहीं है, कि वह कुछ ही घटनाओं से संबंधित हैं, और प्रक्षकों को रिपोर्ट की गई, सभी घटनाओं से संबंधित नहीं हैं। यद्यपि, यू० एन० प्रेक्षकों की जांच पड़ताल और उन द्वारा की गई, कार्यवाही में, त्रुटियां हैं, यू० एन० प्रेक्षकों पर उस व्यवहार का आरोप नहीं लगाया जा सकता, जो सदस्य महोदय ने सुझाव में कहा है। यू० एन० प्रेक्षकों को अपना कार्य सफलतापूर्वक करने में, उनके प्रयत्नों में सरकार की सहायता जारी है।

मिग के कारखाने

*222. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दे० द० पुरो :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री बासप्पा :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरूआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के मिग कारखानों की स्थापना में अक्तूबर, 1965 के अन्त तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) पहला विमान कब तक बन जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) निर्माण की पहली प्रावस्था, अर्थात् नासिक में, विकसित संयोजनों से विमानों के निर्माण के लिए, असैनिक निर्माण कार्य का प्रोग्राम सम्पूर्ण होने वाला है, और इस प्रावस्था के लिए आवश्यक, सभी भवन, इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाने प्रत्याशित हैं। नासिक, कोरापुट और हैदराबाद के असैनिक कार्य समग्रत: सन्तोषजनक-पूर्वक प्रगतिशील हैं। विस्तृत प्रायोजना-विन्यास (प्रायोजना कार्य पद्धति रिपोर्टों) की तैयारी प्रौढ अवस्था तक पहुंच चुकी है, और अगले वर्ष के अन्त तक उस के सम्पूर्ण हो जाने की आशा है। तकनीशनों का प्रशिक्षण और प्रलेखनों का अनुवाद कार्य सोवियत विशेषज्ञों की सहायता से प्रगतिशील है।

(ख) बृहत् संयोजनों से पहला विमान 1966 के दौरान में उत्पादित किया जाएगा। तदनु, उप-संयोजनों विस्तरणों, तथा खाम पदार्थों से विमानों का निर्माण हस्तगत किया जाएगा। आशा है खाम पदार्थों से तैयार किया हुआ पहला विमान 1969 आरंभ में विमुक्त कर दिया जाएगा।

अणु अस्त्र

*223. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या अनु-शक्ति वाले बड़े राष्ट्रों ने अणु अस्त्रों के जमा किये जखीरों को नष्ट करने और आगे उनका निर्माण रोकने में कोई प्रगति की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : लंबी बातचीत के बावजूद, परमाणु-शक्ति वाले देशों में परमाणु-अस्त्रों का उत्पादन बंद करने और उनके मौजूदा भंडारों को घटाने के बारे में समझौता नहीं हो सका है।

भारतीय नौ सेना के लिये पनडुब्बियां

*224. श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम बरूआ :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री टे० सुब्रम्हण्यम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रा० बरूआ :
श्री बासप्पा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिये आधुनिक पनडुब्बियां प्राप्त करने में सफलता मिली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Self-Sufficiency in spare parts for armed forces

*225. **Shri Kishan Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri M. R. Krishna :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether cooperation of private sector has been sought in regard to the manufacturing of spare parts and other components of aircrafts and other armaments required for our Armed Forces; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) Yes, Sir.

(b) A number of orders for components and spare parts are being placed specially after the Chinese aggression in 1962. This is being done to the extent of the assessed civil capacity to meet our requirements mainly with a view to fill in the gaps between the requirements and the available capacity in Defence Production Establishments and relieving the capacity of the Defence Production units for more important and specialised work of a complex nature. It is our aim to have the manufacture of armament components, AGS spares, aircraft ground equipment etc. of the requisite standard catered to by the private sector to the largest extent possible.

हिन्द महासागर में नौ सैनिक अड्डा

*226. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे समाचार मिले हैं कि इन्डोनेशिया सरकार हिन्द महासागर के क्षेत्र में एक नौ सैनिक अड्डा बना रही है;

(ख) क्या चीन इस परियोजना में इन्डोनेशिया की सक्रिय सहायता कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो प्राप्त समाचारों का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : सरकार को किसी ऐसी रिपोर्ट का ज्ञान नहीं है, कि इन्डोनेशिया चीन की सहायता से, हिन्द महासागर में, कोई नौसैनिक अड्डा बनाने जा रहा है।

Defence Plan

*227. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the progress so far made in the execution of country's Defence Plan;

(b) the year-wise break up of this Five Year Plan, the targets for each year and the achievements during the last two years; and

(c) whether the targets of the Plan are likely to be achieved according to the schedule?

The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan) : (a) to (c). The implementation of the plan is, by and large, satisfactory. The recruitment and training programme has been fully implemented. The programme of modernisation of the equipment and expanding and improving the production base has made some progress. Establishing new lines of production and new production units take time. Every effort is being made to implement the plan in these fields also but the progress is somewhat behind schedule. The plan is kept constantly under review in the light of the changing international situation and alignments. Consequent on the ban imposed by certain countries regarding military supplies, alternative measures where the execution of the earlier conceived measures is not possible, are being thought of. It is not feasible in public interest to give more details.

संयुक्त राष्ट्र सूचना कार्यालय

*228. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र सूचना कार्यालय ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के प्रति विशेष व्यवहार किया तथा प्रचार के लिए उनको अपनी सुविधाएं प्रदान की थीं;

(ख) क्या उनके प्रेस सम्मेलन के रिकार्डों को पुनः प्रसारित किया गया जो कि असाधारण बात है;

(ग) क्या हमारी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान के साथ किये गये असामान्य पक्षपात के विरुद्ध कोई विरोध पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) : पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 29 सितंबर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र संवाददाताओं की एक प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना कार्यालय ने इस प्रेस कान्फ्रेंस के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की थी। प्रेस कान्फ्रेंस की रिकार्डिंग ब्राडकास्ट तो नहीं की गई थी किंतु आंतरिक संचार लाइनों पर उसे फिर बजाया गया था और ये लाइनें संवाददाताओं के लिए सुलभ रहती हैं। ये सुविधाएं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए सुलभ हैं और संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना कार्यालय ने इस मामले में पाकिस्तान के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं दिखाया था।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

जवानों के परिवारों को सहायता

*229. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री बासप्पा :**

श्री जसवन्त मेहता : **श्री रा० बरूआ :**

श्री कृष्णपाल सिंह : **श्री राम हरख यादव :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के परिवारों को तत्काल सहायता और प्रतिकर देने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान प्राण देने वाले जवानों के कुटुम्ब केन्द्रीय सरकार से निम्न आर्थिक सहायताओं के अधिकारी हैं :—

(1) एक फौरी अनुग्रह पूर्वक अनुदान।

(2) मृत के पद पर निर्भर, एक यकमुश्त कुटुम्ब उपदान।

(3) दो मास के लिए कुटुम्ब नियतन, यदि उस समय दिया जा रहा हो, या विशेष कुटुम्ब पेन्शन, और अगर देय हो, तो बच्चा भत्ता, दोनों में से जो अधिक हो।

(4) और, दो मास के लिए, एक विशेष भत्ता जो विशेष कुटुम्ब भत्ते, और बच्चा भत्ते के, बराबर होगा, अगर वह देय हो।

(5) तदोपरान्त विशेष कुटुम्ब पेन्शन और बच्चा भत्ता, अगर देय हो।

ऐसे कुटुम्ब कुछ राज्य सरकारों से अनुग्रहपूर्वक अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु इस संबंध में, सम्पूर्ण सूचना प्राप्य नहीं है। यह सूचना प्राप्त की जा रही है, और यथासमय, सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

ऐसे कुटुम्बों को, जवानों की मृत्यु के कारण, मुआवजे के तौर पर कुछ देय नहीं है।

अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका में भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी प्रचार

*230. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री वृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी तथा लैटिन अमरीकी देशों में हाल में पाकिस्तान ने भारत विरुद्ध प्रचार बढा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विरोध में प्रचार करने के लिये भारत क्या कदम उठा रहा है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पाकिस्तान हमेशा भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। अफ्रीकी और लातीनी अमरीका के देशों में हाल ही में पाकिस्तान के बढते हुए प्रचार के विषय में कोई विशेष तथ्य हमारे ध्यान में नहीं आए हैं।

(ख) विदेश-स्थित हमारे मिशन भारत के विरुद्ध किए जाने वाले पाकिस्तानी प्रचार पर निगाह रखते हैं और हर मौके पर उसका प्रतिकार करते हैं। हमारे मिशन प्रमुखों ने संबद्ध सरकारों के अध्यक्षों तथा विदेश कार्यालयों को व्यक्तिगत रूप से हमारा दृष्टिकोण समझा दिया है। भारत के दृष्टिकोण को समझाने के लिए भारत का एक सद्भावना शिष्टमंडल आजकल पूर्व अफ्रीका की यात्रा कर रहा है। इस प्रकार के शिष्टमंडल अफ्रीका के अन्य भागों की यात्रा करने वाले हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सदस्य लातीनी अमरीका के कई देशों की यात्रा कर आए हैं।

आकाशवाणी के अधिकारियों का शत्रु देशों के साथ संपर्क

*231. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि आकाशवाणी के कुछ अधिकारियों का चीन तथा पाकिस्तान जैसे अमित्र देशों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क है;

(ख) क्या सरकार को आकाशवाणी के उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं जो पाकिस्तान जाया करते हैं; और

(ग) क्या सरकार को ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि आकाशवाणी के कर्मचारियों ने अगस्त-सितम्बर, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान भारत-विरोधी विचार व समाचार देने का षड़यन्त्र किया था?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। आकाशवाणी के कुछ अधिकारियों का चीन तथा पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क होने के बारे में कुछ शिकायतें सरकार को मिली थीं, परन्तु, जांच करने पर ये आरोप निराधार पाए गए। दो मामलों में, जांच अभी जारी है।

(ख) और (ग) : जी, नहीं।

भारत-चीन विवाद में मध्यस्थता

* 232. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० रानेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कुछ मित्र देशों ने भारत और चीन के विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) इस वर्ष अक्तूबर के दौरान राष्ट्रपति डा० राधाकृष्ण की रूमानिया की यात्रा के समय ऐसी परिकल्पना थी कि रूमानिया सरकार चीन और भारत में मध्यस्थता की रुचि रखती है। परन्तु राष्ट्रपति की रूमानिया के राष्ट्रपति के साथ बात-चीत में रूमानिया ने मध्यस्थता के किसी सुझाव की पेशकश नहीं की।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त का कार्यालय

* 233. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैदेशिक-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा कलकत्ता में पाकिस्तानी उप-उच्चायोग के कार्यालय के बन्द किये जाने की पूर्ववर्ती कार्यवाही के रूप में उप-उच्चायोग ने भारतीय कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी हैं और कुछ किराये के भवनों को भी खाली कर दिया है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने ढाका में भारतीय उप-उच्चायोग को भी इसके बदले में बन्द किये जाने के लिए कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) खबर है कि कलकत्ता में पाकिस्तान के उप हाई कमिशन ने अपने तमाम भारतीय कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। सरकार को इस बात का पता नहीं है कि उप हाई कमिशन ने किन्हीं किराए के मकानों को छोड़ दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pak-China Treaty

*324. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Jagdev Singh Siddhanti:**
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Krishnapal Singh :
Shri Brij Raj Singh : Shri D. C. Sharma :
Shri Gokaran Prasad : Shri mati Maimoona Sultan:
Shri S. N. Chaturvedi : Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Parkash Vir Shastri :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has recently concluded a treaty with China after the cease-fire;

(b) whether it is also a fact that according to that treaty, China has been allowed to use the airports in East Pakistan to wage war against India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) The Government of India has no such information.

(b) and (c). Do not arise.

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सिख लड़कियों तथा महिलाओं का बलपूर्वक अपहरण

*236. **श्री कपूर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में फाजिल्का सैक्टर से पांच दर्जन से अधिक सिख नवयुवतियों तथा महिलाओं का पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बलपूर्वक अपहरण करके पाकिस्तान ले जायें जाने का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पंजाब सरकार द्वारा की गई जांच के अनुसार झागर और पुस्कूचिस्ती ग्रामों से जो कि फाजिल्का सैक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित हैं, बहुत से परिवार 6 सितम्बर से जिस दिन पाकिस्तानी सेना ने इन ग्रामों पर आक्रमण किया था, लापता हैं। पंजाब सरकार द्वारा यह जानने के लिए कि क्या यह लोग मारे गए है या पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिए गए हैं या भारत में किसी दूसरे स्थान पर चले गये हैं, जांच की जा रही है।

Maltreatment of Officials of Indian High Commission in Pakistan

*237 **Shri Bade :**
Shri Yashpal Singh :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of protests lodged with the Government of Pakistan alongwith their respective dates during 1st January to 31st October, 1965 against the maltreatment of officials of the Indian High Commission in Karachi by the Pakistani authorities; and

(b) the contents of the replies thereto received from the Pakistan Government

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) and (b). The High Commission of India lodged three protests with the Government of Pakistan on 25th June, 28th September and 29th October, 1965. The Ministry of External Affairs lodged two protests with the Pakistan High Commission in New Delhi on 4th and 15th October, 1965.

2. The Government of Pakistan have not given a final reply to the protest dated 25th June against the harassment and humiliation of a High Commission official by Pakistan Customs authorities. They orally promised to look into the matter.

3. The protests dated 28th September and 4th October against the outrageous violations of the diplomatic rights and immunities and the indignities to which the Indian High Commission was subjected have been labelled by the Government of Pakistan as being unfounded. In an attempt to cover up the actions of the Pakistan authorities against the Indian Missions in Pakistan, the Government of Pakistan have made unfounded counter-allegations in the shape of petty grievances and complaints against the treatment received by the Pakistan High Commission in India.

4. No replies have been received to the Ministry of External Affairs protest Note dated October 15 against the ill-treatment of the Counseller of the Indian High Commission residing at Islamabad and to the Indian High Commission's protest Note dated October 29 against the harassment to which the officers and staff of the High Commission are being subjected by the Pakistan authorities.

सीमान्त सड़कें

525. श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमान्त सड़कों के निर्माण में लगे हुए सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध कितने विशेष मुकदमे दायर किये गये है;

(ख) इन मामलों में कितने अधिकारी अन्तग्रस्त हैं और उनके पद क्या है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है, और क्या इन अभियोगों में कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो गया है अथवा छोड़ दिया गया है; और

(घ) इन मामलों में सामान्य सैनिक प्रक्रिया, अर्थात्, विभागीय जांच, कोर्ट आफ इन्क्वायरी, समरी आफ एवीडेंस तथा कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया न अपनायें जाने के क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) अब तक एस० पी० इ० ने 9 मामले फाईल किए हैं।

(ख) इन मामलों में 12 निम्न सैनिक और असैनिक अफसर अन्तर्गस्त है —

(1) ले० कर्नल	2
(2) मेजर	6
(3) आर्डनेन्स आफसर (असैनिक) . . .	1
(4) एग्जीक्यूटिव इंजीनियर	1
(5) सहायक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर . . .	2

(ग) मामले अभी इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए विशेष न्यायाधीशों के न्यायालयों में चल रहे हे।

(घ) अधिकारपूर्ण कानूनी राय में यह मामले कोर्ट मार्शल द्वारा नहीं चलाए जा सकते, बल्कि केवल भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीशों द्वारा।

Printing of All India Radio Journals

526. Shri Madhu Limaye :

Shri Bagri :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2055 on the 13th September, 1965 and state :

(a) whether the enquiry conducted into the violation of the terms of printing of the All India Radio journals has since been completed;

(b) if so, the main conclusions arrived at; and

(c) the action being taken thereon?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) The enquiry is still in progress.

(b) and (c). Do not arise at this stage.

राष्ट्रीय रक्षा कोष

527. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 5 अगस्त, 1965 से भिन्न भिन्न विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के लोगों की ओर से राष्ट्रीय, रक्षा कोष में कितना धन प्राप्त हुआ है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : चालू तरीके के अनुसार, राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए विदेशों में अनुदान हमारे दूतावासों द्वारा प्राप्त किए जाने दरकार हैं, और वे दूतावास उन अनुदानों का आकलन अपने खातों में करा देते हैं और ये हिसाब महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व द्वारा

यथोचित समय पर प्राप्त एवम् समायोजित हो जाते हैं । व्यक्तिगत दाताओं के विवरण प्राप्त नहीं होते । कभी कभी, विदेशों में रहने वाले व्यक्ति उल्लिखित कोष के लिए अपने अनुदान देशभर में फैले हुए विविध चन्दा इकट्ठा करने वाले अभिकरणों को सीधे ही भेज देते हैं। ऐसी भेजी जाने वाली रकमें हमारे दूतावासों के खातों में दर्ज नहीं होती । ऐसे सब दाताओं की राष्ट्रीयता की जानकारी नहीं होती । इन कारणों से, हमारे सब दूतावासों तथा भारत में स्थित सब चन्दा इकट्ठा करने वाले केन्द्रों से बहुत विस्तारपूर्वक पूछ-ताछ करने के बिना, प्रश्न में वांछित जानकारी देना सम्भव नहीं । उन दूतावासों तथा केन्द्रों को भी दाताओं से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछ-ताछ करनी पड़ सकती है । ये सब पूछ-ताछ व्यवहार्य नहीं समझी जाती ।

केरल में बेरोजगार लोगों का सर्वेक्षण

528. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य अर्थविभाग तथा रोजगार निदेशालय द्वारा केरल में बेरोजगार लोगों का संर्वेक्षण करवाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ होगी ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये किन-किन जिलों को चुना गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण 16 सितम्बर, 1965 को आरम्भ हुआ था और अभी काम चल रहा है ।

(ग) इसके अधीन राज्य के सभी 9 जिलों का सर्वेक्षण किया जाएगा ।

केरल में डाक तथा तार कार्यालयों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण

529. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के महत्वपूर्ण नगरों में डाक व तार कार्यालयों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये अधिग्रहीत स्थान कई वर्षों से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवाने के लिये प्रत्येक सर्किल के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सम्बध्द एक इंजीनियर तथा एक आर्किटेक्ट नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) : स्थानों को उपयोग में लाने के कदम उठाये जा रहे हैं । कुछेक स्थान कुछ समय से खाली पड़े हैं क्योंकि जमीन भावी आवश्यकताओं के लिए जमीन प्राप्त कर लेने की नीति के अनुसार प्राप्त कर ली जाती है चूंकि आवश्यकता के समय तुरंत जमीन प्राप्त करना कठिन होता है । विशेष रूप से ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि डाक-तार कार्यालयों को जनता की सुविधा और कम खर्चे के लिए केन्द्रस्थ स्थानों पर रखना पड़ता है ।

निर्माण कार्यक्रम साधनों के उपलब्ध होने और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर आधारित रहता है । निर्माण कार्य शुरू करने से पहले डिज़ाइन व प्राक्कलन तैयार करने और टेंडर आदि मंगाने में भी समय लग जाता है ।

आपत्कालीन स्थिति के कारण 1962 और 1964 में अपनाये गए कम खर्चीले उपायों के कारण भी निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब हुआ है ।

(ग) कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यभार पर निर्भर करती है और जब अतिरिक्त काम होता है तो अतिरिक्त इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि नियुक्त किये जाते हैं ।

केरल सर्किल में डाक-तार कर्मचारी

530. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग के केरल सर्किल में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि मंजूर रिक्त स्थानों को भरने में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां; कुछ हद तक ।

(ख) पदों पर नियुक्तियां करने में कुछ हद तक देरी हो जाती है ।

(ग) बहुत से मामलों में उक्त पद हाल ही में मंजूर किये गए थे और चुने गये उम्मीदवारों को निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है । इतना ही नहीं नियुक्ति के लिए जिन उम्मीदवारों को चुना जाता है उनमें से सभी नहीं आते और आगे और भर्ती करनी पड़ती है । रिक्त स्थानों को भरने के लिए डाक-तार महाअध्यक्ष, त्रिवेन्द्रम से शीघ्र ही भर्ती करने की प्रार्थना की जा रही है ।

Literature in Foreign Languages

531. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the foreign languages, apart from the English language, in which literature explaining the Indian case *vis-a-vis* the recent Pakistani attack was published and distributed in foreign countries;

(b) the details of the literature thus published; and

(c) the steps taken so far for the publication and distribution of such literature in the Russian, German, French, Spanish, Italian, Arabic, Persian and Japanese languages?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) to (c) : Material was published in the following foreign languages besides English.

French, Arabic, Spanish, German, Italian, Dutch, Flemish, Portuguese, Serb-Croatian, Swahili, Persian, Nepalese, Tibetan, Burmese, Thai, Malay, Japanese and Bahasa Indonesia.

Bulletins are being regularly issued by Indian Missions abroad in these languages. In addition, a number of pamphlets and booklets on the Pakistani aggression have been translated into important foreign languages. Specific details of the pamphlets recently translated into foreign languages are being collected and a statement to this effect will be placed on the Table of the House.

उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग की इमारतें

532. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकखाने की इमारतों के निर्माण के लिए बालासार (उड़ीसा) नगर के मध्य में आठ अथवा दस वर्ष पूर्व लगभग दो एकड़ भूमि खरीदी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जमीन 24 सितम्बर, 1960 को खरीदी गई थी ।

(ख) डाक-तार विभाग को अपने दफतरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए जमीन की आवश्यकता है और आवश्यकता के समय जमीन प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । अतः नीति यही है कि आगे की आवश्यकताओं के लिए जमीन की कोशिश की जाए और उसे प्राप्त किया जाए ।

जमीन प्राप्त करने के बाद डिज़ाइन आदि तैयार किये जाते हैं और टेंडर मांगे जाते हैं । इसमें कुछ समय (लगभग दो वर्ष) लग जाता है । साथ ही निर्माण का कार्यक्रम साधन उपलब्ध होने और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर आधारित रहता है ।

आपत्कालीन स्थिति के कारण 1962 और 1964 में अपनाये गए कम खर्चीले उपायों के कारण भी विलम्ब हुआ है ।

राज्य के लोक निर्माण विभाग से निर्माण-कार्य चालू करने के लिए कहा गया है ।

डाक व तार निदेशालय, उड़ीसा

533. **श्री गोकुलानन्द महन्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में डाक तथा तार निदेशालय के अधीन इस समय काम करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी उसी राज्य के निवासी हैं; और

(ग) क्या इन पदों के लिए नियुक्ति सीधे की जाती है अथवा पदोन्नति के द्वारा तथा यदि पदोन्नति के द्वारा की जाती है तो पदोन्नति करने के मुख्य आधार क्या हैं;

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) श्रेणी I . . 8

श्रेणी II . . 29

(ख) श्रेणी I . . . कोई नहीं

श्रेणी II . . . 11

(ग) (i) श्रेणी I के पदों पर कुछ तो सीधी नियुक्ति की जाती है और कुछ अखिल भारतीय स्तर पर श्रेणी II के अधिकारियों की, केवल चुनाव के आधार पर, पदोन्नति करके की जाती है ।

(ii) डाक तथा तार परियात सेवा श्रेणी ii के पदों पर नियुक्ति अखिल भारतीय स्तर पर श्रेणी III के योग्य कर्मचारियों की, केवल चुनाव के आधार पर, पदोन्नति करके की जाती है । जहां तक तार इंजीनियरी तथा बेतार सेवा श्रेणी 11 के पदों पर नियुक्ति का प्रश्न है, वह निर्धारित विभागीय परीक्षा में योग्यता पाने वाले श्रेणी III के कर्मचारियों के चुनाव के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर पदोन्नति करके की जाती है ।

भारत में संयुक्त अरब गणराज्य का चलचित्र समारोह

534. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने भारत में संयुक्त अरब गणराज्य के एक चलचित्र समारोह का आयोजन किया है,

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर होगा, और

(ग) इस समारोह में कौन कौन भाग लेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) नई दिल्ली में 3–12–65 से 8–12–65 तक और बम्बई में 10–12–65 से 16–12–65 तक ।

(ग) संयुक्त अरब गणराज्य फ़िल्म क्षेत्र सम्बन्धित लोगों का एक शिष्टमण्डल भेजेगा ।

चीन में एक भारतीय राष्ट्रजन का अभिपीड़न

535. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के शंघाई न्यायालय में एक भारतीय राष्ट्रजन, श्री एम० एल० दास को, एक घृणित अपराध के आरोप में फंसा कर दीर्घकाल के कठोर कारावास का दण्ड दुर्भावना के कारण दिया गया है, और उसे समुचित कानूनी सहायता नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उक्त राष्ट्रजन की क्या सहायता की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : चीनी पुलिस अधिकारियों ने 29 अक्तूबर, 1963 को श्री एम० एल० दास को गिरफ़्तार कर लिया था, जो शंघाई में रहते थे, और पीकिंग-स्थित भारतीय राजदूतावास के बार बार विरोध करने के बावजूद, चीनी पुलिस अधिकारियों ने श्री एम० एल० दास के खिलाफ़ लगाए गए आरोपों का पूरा ब्यौरा भारत सरकार को नहीं बताया है । अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, भारतीय राजदूतावास द्वारा श्री एम० एल० दास को कोंसली संरक्षण देने की अनुमति देने से इन्कार करने के विरुद्ध भारत सरकार ने चीन सरकार को कई विरोध-पत्र भेजे हैं । चीनी अधिकारियों से इजाज़त मिलने पर, भारतीय राजदूतावास के कर्मचारी जेल में श्री एम० एल० दास से मिलने भी आते रहे हैं । इस मामले में भारत सरकार ने चीन सरकार को जो सबसे ताज़ा विरोध-पत्र भेजा है उसकी एक प्रति तथा उत्तराधीन चीनी नोट की एक प्रति सदन की मेज़ पर रख दी गई है **[पुस्तकालय में रखी गइ । देखिये संख्या एल० टी० 5143/65 ।]**

नेफा में विमान दुर्घटनायें

536. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में पिछले पांच महीनों में कितनी विमान दुर्घटनायें हुई; और

(ख) दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 15 जून, 1965 से अब तक उत्तर पूर्वी सीमा पर भारतीय वायु सेना के विमान की एक दुर्घटना हुई है ।

(ख) दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी स्थापित कर दी गई है । पूर्ण विस्तार तभी मालूम हो पाएंगे, जब कोर्ट आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होगी ।

उड़ीसा में डाक सेवायें

537. **श्री धलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1965 के अन्त तक उड़ीसा के कितने गांवों में डाक सेवाओं की व्यवस्था थीं; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) : स्वयं पहली पंच वर्षीय योजना के अन्त तक उड़ीसा के सभी आबादी वाले गांवों में या तो डाकघर के नियमित कर्मचारियों के द्वारा या विशेष मजदूरों के द्वारा डाक वितरण की सुविधा उपलब्ध थी । 31 अक्तूबर, 1965 को वितरण सेवा कितनी बार उपलब्ध थी उसकी स्थिति नीचे दी गई है ।

वितरण सेवा कितनी बार उपलब्ध थी	उन गांवों की संख्या जिनमें 31 अक्तूबर, 1965 को सेवा उपलब्ध थी ।
दैनिक	20,193
सप्ताह में तीन बार	18,726
सप्ताह में दो बार	7,050
साप्ताहिक	497
एक सप्ताह से अधिक समय के बाद	कुछ नहीं

जहां तक डाकघर खोल कर डाक सेवाओं के विस्तार का सम्बन्ध है, 31 अक्तूबर, 1965 को 16 प्रधान डाकघर, 377 विभागीय उप डाकघर, 37 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर तथा 4255 शाखा डाकघर थें ।

आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कलाकार

538. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 सितम्बर, 1965 को आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कितने नियमित कलाकार (स्टाफ़ आर्टिस्ट) तथा कर्मचारी थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
स्टाफ़ आर्टिस्ट	2	1
नियमित कर्मचारी	36	1
कुल .	38	2

उड़ीसा में टेलीफोन का राजस्व

539. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय टेलीफोन राजस्व की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) सरकार ने उसकी वसूली के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) 1 जुलाई, 1965 को 31 दिसम्बर, 1964 तक जारी किये गए बिलों की 9.61 लाख रुपये की रक़म बकाया थी ।

(ख) निपटान करने की दृष्टि से दोषी उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और जहां आवश्यक हो कानूनी कारवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं । निजी तथा सरकारी, दोनों ही प्रकार के दोषी उपभोक्ताओं के टेलीफोन काटने की कार्यवाई भी की गई है ।

दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य देशनांक

540. **श्री श्रीनारायण दास :**

यशपाल सिंह :

श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 22 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2666 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य देशनांक सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर अंतिम रूप से कब तक विचार कर लिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ग) इस सम्बन्ध में बहुत शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

Progress in Nuclear Science

541. Dr. Ram Manohar Lohia :

Shri Kishen Pattnayak :

Shri Ram Sevak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that China exploded its first atom bomb with Uranium-237 and not with plutonium;

(b) whether it illustrates the technical progress China has made in this field;

(c) the progress made by India in nuclear science and technology as compared to that of China; and

(d) whether Government have the knowledge of setting up a 'Gasses Diffusion Plant' and the estimated cost thereof ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) It is common knowledge that China used Uranium-235 for testing her first atomic device.

(b) and (c). Question of comparison between them does not arise,as India's programme is directed wholly to the use of atomic energy for peaceful purposes, while China has directed her programme towards military ends.

(d) There is enough expertise in the Atomic Energy Establishment to develop and build such a plant, if the Government of India decided to do so.

नागा विद्रोहियों द्वारा गोलीबारी

542. श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने सितम्बर-अक्तूबर, 1965 में हमारी सुरक्षा सेनाओं पर कितनी बार गोली चलाई; और

(ख) नागा विद्रोहियों ने क्या नुकसान पहुंचाया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सितंबर-अक्तूबर, 1965 के दौरान उपद्रवी नागाओं ने तीन बार हमारी सुरक्षा सेनाओं पर ऐसे क्षेत्रों में गोली चलाई जो लड़ाई बंद रखने के क्षेत्र के बाहर आते हैं ।

(ख) इस अवधि में उपद्रवी नागाओं के हाथों संपत्ति को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची

पूर्वी पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों का बर्मा से प्रव्रजन

543. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** **श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा में बसे हुए पूर्वी पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में रंगून स्थित भारतीय दूतावास को भारत प्रव्रजन करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, रंगून-स्थित भारतीय राजदूतावास को ऐसे बहुत से लोगों से प्रार्थना-पत्र मिले हैं ।

(ख) उन्हें भारत आने की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और यह सहायता उन्हें उनकी पात्रता के अनुरूप दी जाती है ।

लन्दन में भारतीय विद्यार्थी

544. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लन्दन में भारतीय विद्यार्थियों के विरुद्ध कटु भावनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि ऐसा बताया जाता है कि लन्दन तथा केंम्ब्रिज विश्व-विद्यालयों के पी० एच० डी० के विद्यार्थियों को किंग्स क्रास रेलवे स्टेशन पर मारा पीटा गया; और

(ख) क्या यह सच है कि जब पुलिस को बताया गया तो उसने कोई कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय छात्रों पर हमला होने के कुछ मामले तो हुए हैं, लेकिन यह कहना ठीक न होगा कि लंदन में भारतीय छात्रों के विरुद्ध कटु भावना बढ़ रही हैं ।

(ख) जी नहीं । इसके विपरीत जिस क्षेत्र में हमले हुए थे, वहां गश्त लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिसमैन तैनात कर दिए गए हैं ।

Damage to Buildings during Pak Aggression

545. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. N. Chaturvedi :**

Shri S. C. Samanta : **Shri Parashar :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any damage was caused to Government residential and other buildings as a result of bombing and other action taken in the recent Pak. aggression;

(b) if so, the details thereof;

(c) the estimated damage to buildings, residential buildings and other works under his Minsitry; and

(d) the measures taken for repairing the damaged buildings ?

The Minister of Defence (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) and (b) . Yes. Some damage to Government buildings was caused in the bombing of airfields like Halwara and adampur and in Cantonments like Ambala. Precise details are not readily available.

(c) and (d) : Repairs to the damaged buildings have already been taken up. No detailed estimates are readily available.

सशस्त्र सेनाओं के वीरगति प्राप्त कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन

546. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वीर गति प्राप्त सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के आश्रितों को पेंशन का प्रथम भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : पाकिस्तान के विरूद्ध संक्रियाओं में मारे गए, सशस्त्र सेनाओं के कुटुम्ब, और आश्रित, हाल के आदेशों के अन्तर्गत, एक यकमुश्त उपदान ; दो महीनों के लिए विशेष कुटुम्ब भत्ता/कुटुम्ब नियतन ; और उसके पश्चात् विशेष कुटुम्ब पेन्शनी पंचाटों अथवा (अविवाहित अफसरों की हालत में) आश्रित पेन्शन के अधिकारी हैं । अफसरों की हालत में विशेष कुटुम्ब पेन्शन की अन्तिम अदायगी, और अफसरों से नीचे, इन्क्वायरी होने तक पंचाट, जो दोनों हालतों में विशेष कुटम्ब पेन्शन के बराबर होंगे, अन्तिम पेन्शन की स्वीकृति में विलम्ब होने पर दिए जा सकते हैं। अधिकतर हालतों में देय अदायगिएं कर दी गई हैं । शेष मामलों में, जो तुलनात्मक दष्टि से संख्या में बहुत कम हैं, दावेदारों से कुछ सूचना प्रतीक्षित है । तथापि इन मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा रहा है ।

Per Capita Income

547. **Shri D. N. Tiwary** : Will the **Prime Minister** be pleased to state

(a) whether Government are aware that daily *per capita* income in many parts of the country is even less than 25 paise ;

(b) if so, the names of such areas; and

(c) whether any special efforts are being made to raise the *per capita* income in those areas ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) As the Central Statistical Organisation of the Government of India compile only estimates of the total national income and all India estimates of *per capita* income, it is not possible to say whether the daily *per capita* income in any part of the country is less than 25 paise. The Central Statistical Organisation does not at present prepare such estimates on a State or a regional basis.

(b) Does not arise.

(c) Developmental measures are being taken under the various five year plans to secure increasingly balanced regional development all over the country.

Export of Heavy water

548. Shri Bagri :

Shri Madhu Limaye :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the heavy water produced in India is exported to other countries ;

(b) if so, the names of the countries to which it has been exported so far; and

(c) whether Government have laid down the condition that the importing countries will make use of this water only for peaceful purposes ?

The Prime Minister and Minister of Atomic energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) and (b) : Ten tonnes of heavy water produced at Nangal have been leased to Belgium for a period of three years. We do not have enough for sale, as much more than what we produce will be required for the Rajasthan and Madras Atomic Power Stations. Hence it is proposed to build a second plant with a minimum capacity of 200 tons of heavy water per annum.

(c) The lease agreement with Belgium specifically stipulates that the heavy water leased shall be used only as initial inventory requirement for the Vulcain reactor for purpose of conducting research into the peaceful uses of atomic energy. A copy of the Agreement is available in the Library of the House.

Teleprinters

549. Shri Bagri :

Shri Madhu Limaye :

Shri Ram Sevak Yadav :

Shri Yashpal Singh :

Shri Bhanu Prakash Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for teleprinters in India is increasing day by day;

(b) if so, the steps being taken by Government to meet the demand; and

(c) the total number of applications for the supply of teleprinters which are pending at present in the Deptt. or the Hindustan Teleprinters Ltd. ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvtai) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have sanctioned a project for expanding the installed capacity of the Hindustan Teleprinters Ltd., Madras, from 1,300 units in single shift to 8,500 units per annum in double shift in stages. The factory is doubling its production during 1965-66 and, thereafter, will be stepping up production steadily to achieve the targeted production of 8,500 units per annum by 1970-71.

(c) As on the 1st November, 1965 orders for 2,583 unit teleprinters were pending with the Hindustan Teleprinters Ltd., which includes the demand of the Posts & Telegraphs Department.

परमाणु विज्ञान सम्बन्धी आधारभूत अनुसन्धान

550. श्री बासप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं में प्रयोगशालाओं में परमाणु विज्ञान विषयक आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं को जो इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रही हैं काफी मात्रा में सहायक अनुदानों के अलावा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए गये हैं :—

(i) तमाम विश्वविद्यालयों और महत्वपूर्ण संस्थाओं में सम्बद्ध विषयों के अंडर-ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेज़्युएट विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना;

(ii) न्यूक्लीय विज्ञान की विभिन्न प्रणालियों के अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये प्रवर तथा अवर अनुसंधान शिक्षावृत्तियां देना;

(iii) विशेष अनुसंधान प्रायोजनाओं के लिए सहायक अनुदान देना;

(iv) परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे द्वारा निर्मित विशेष इलैक्ट्रानिक उपकरण देना;

(v) न्यूक्लीय भौतिक शास्त्र, इलैक्ट्रानिक्स और न्यूक्लीय रसायन शास्त्र में विश्व-विद्यालयों के अध्यापकों के लिए नवीकर पाठ्यक्रम;

(vi) रेडियो-आइसोटोपों का प्रयोग करने के लिए पाठयक्रमों का संगठन और इलैक्ट्रोनिक उपकरणों का प्रचालन करना;

(vii) ट्राम्बे संस्थान में रिएक्टरों और दूसरे विशेष उपकरणों का विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रयोग करने की सुविधाएं देना;

(viii) ट्राम्बे से प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में डेप्यूटेशन पर भेजना ।

न्यूक्लीय अनुसंधान तथा विभिन्न विज्ञानिक श्रेणियों में उच्च अनुसंधान के लिये परमाणु ऊर्जा के विकास से मिली सहायता के प्रयोग से, जो अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है, इनमें से एक देश के दक्षिण और दूसरा उत्तरी क्षेत्र में होगा । इन केन्द्रों में ऐसी सुविधायें, जैसे रिएक्टर या त्वरक या एक सब-क्रिटिकल असेम्बली, जो कि विश्वविद्यालय नहीं दे सकते, होंगी ।

वेली में प्रयोगशाला

551. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** थुम्बा के पास वेली की प्रयोगशाला के बारे में 16 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयोगशाला को मिलाने वाली सड़कों के लिये भूमि अर्जित करने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : भूमि का बड़ा भाग वेली हिल से मिलने वाली सड़क बनाने के लिये अणुशक्ति वि ाग को दे दिया गया है । आशा है शेष भूमि भी शीघ्र ही इस विभाग को दे दी जायेगी । आशा है वेली हिल को मिलाने वाली सड़क मार्च, 1966 तक तैयार हो जायेगी ।

भारी पानी संयंत्र

552. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी पानी निर्माण संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र किस स्थान पर लगाया जाएगा; और

(ग) उसकी क्षमता क्या होगी और उस पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ग) : 200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले भारी पानी संयंत्र की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस प्रायोजना पर 21 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ख) संयंत्र के स्थापित करने के स्थान का निर्णय योजना के स्वीकार हो जाने के बाद किया जायेगा ।

दिल्ली-नरेला-सोनीपत-बहादुरगढ़ सीधा टेलीफोन सम्बन्ध

553. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को नरेला, सोनीपत तथा बहादुरगढ़ के साथ सीधे टेलीफोन द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इसे अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख) : नरेला और बहादुरगढ़ को दिल्ली से सीधे डायल करने की प्रणाली से जोड़ने का प्रस्ताव है । सोनीपत के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । नरेला और बहादुरगढ़ की योजनाओं को इन स्थानों पर स्वचल केन्द्रों के चालू होने के बाद 1966 के दौरान क्रियान्वित करने की आशा है ।

मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली घर

554. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उस राज्य में एक परमाणु बिजली घर स्थापित किये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

धान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) : मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी समय परमाणु ऊर्जा विभाग को राज्य में परमाणु विद्युत स्टेशन की स्थापना के बारे में नहीं कहा है, लेकिन राज्य से किसी विशेष क्षेत्र में इसकी स्थापना के आर्थिक आधार के बारे में पूछ ताछ की गई थी । विभाग को पता चला कि राज्य सरकार मोरेना क्षेत्र में, जहां बिजली की महत्वपूर्ण मांग न थी और न ही निकट भाविष्य में बढ़ने की आशा थी, एक परमाणु विद्युत स्टेशन स्थापित करने का विचार कर रही थी । यदि परमाणु बिजली स्टेशनों की क्षमता काफी अधिक हो तो वे प्रतियोगी दर पर बिजली पैदा कर सकते हैं, इसलिये राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि इस क्षेत्र में परमाणु बिजली स्टेशन स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न होगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पास भारतीय सशस्त्र सेना

555. श्री यशपाल सिंह :

श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सशस्त्र सेनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के दलों के साथ अभी तक विदेशों में काम कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश की आवश्यकताओं देखते हुए उनको वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । उन्हें लौटा लेना आवश्यक नहीं समझा गया ।

औद्योगिक विरामसन्धि

556. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण आपातकाल की अवधि में अब तक औद्योगिक विराम संधि का पूर्ण पालन होता रहा है,

(ख) यदि हां, तो किन बातों के कारण ऐसा सम्भव हुआ, और

(ग) यदि नहीं, तो असन्तोष के मुख्य कारण क्या थे और उन्हें कैसे दूर किया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवया) : (क) जी, हां, कुल मिला कर ।

(ख) मालिक और मजदूर दोनों औद्योगिक शान्ति बनाए रखने और देश के रक्षा प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक थे ।

(ग) जो चन्द एक उल्लंघन हुए वे आर्थिक कारणों से हुए या उनका सम्बन्ध गैर-औद्योगिक मामलों से था । इस प्रकार के प्रत्येक मामले का विश्लेषण किया गया और अशांति का कारण दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गई ।

जवानों के परिवारोका कल्याण

557. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक अधिकारियों तथा छात्रसेना दल के कर्मचारियों को हाल ही में हुए पाकिस्तानी हमले के कारण हताहत सैनिकों के परिवारों तथा संबंधियों के पास जाने के लिए कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को विभिन्न भरती क्षेत्रों में लगाया गया है तथा उनको परामर्श दिया गया हैं कि वे सैनिकों, नाविकों तथा वैमानिकों के बोर्डों के सहयोग से काम करें; और

(ग) युद्ध में हताहत सैनिकों के परिवारों को इस उद्देश्य से क्या विशेष सुविधायें उपलब्ध की गई है कि उनको समय-समय पर सरकार द्वारा दी गई रियायतें शीघ्रतापूर्वक प्राप्त हो सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) कल्याण अफसर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा दी गई वेतन, पेन्शनों, उपदान सहायता अनुदानों संबंधी हकदारियों तथा अन्य सुविधाओं और रियायतों से अवगत हैं, और वह हर एक संबंधित कुटुम्ब को उनके अधिकारों से अवगत कराएंगे, और उनकी अदायगी में उनकी सहायता करेंगे ।

शीघ्र अदायगियों के लिए निम्न विशेष उपाय भी किए गए हैं :—

(1) अफसरों से निम्न स्तर के मारे गए अथवा संक्रिया में लापता, सेवाओं के सेविवर्ग के संबंध में जहां आवश्यक हो तार द्वारा मनी आर्डर से, सरकारी खर्च पर, पेन्शनी हकदारियों और रियायतों का भेजना ।

(2) एसी हालत में, जिस मास का कुटुम्ब नियतन हो, उसे उस मासकी 20 तक पेशगी भेजना ।

(3) अविवाहित सेवा अफसर के पद वेतन के 45 प्रतिशत के बराबर विशेष कुटुम्ब भत्ते की (अगर अफसर लापता हो, तो अधिकाधिक तीन मास के लिए, और संक्रिया मे मारा गया हो, तो दो मास के लिए) असैनिक अधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना, कि आश्रितों का पोषण मुख्यत: अफसर द्वारा होता था, बल्कि संबंधित व्यक्तियों से आश्रय संबंधी प्रमाण के आधार पर ही, उनके आश्रितो को अदायगी ।

बांकुरा में बम विस्फोट

558. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री प्र० के० देव :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री सोलंकी :**

श्री कपूर सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के सुपतारी गांव में 29 सितम्बर, 1965 को एक विस्फोट होने के फलस्वरूप 9 व्यक्ति मारे गये थ जिनमें एक स्त्री तथा तीन बच्चे भी शामिल थे;

(ख) क्या इस विस्फोट से बहुत बडा क्षेत्र हिल गया था और बहुत से मकानों को क्षति हुई थी;

(ग) क्या ग्रामीणों के इस वक्तव्य की, कि 7 बज सबेरे आकाश से एक बम मकानों के समूह पर गिरा था और फट गया था, जांच करली गई है;

(घ) क्या कलकत्ता में सनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा क्या उनके विशेषज्ञों ने जांच की है; और

(ङ.) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सुरितारी गांव में 29–9–65 को एक विस्फोट के कारण 7 व्यक्ति मारे गए थे, जिनमें एक स्त्री और दो बच्चे थे, और 4 व्यक्ति घायल हुए थे ।

(ख) छींटों के कारण दो मकानों को थोड़ा सा नुकसान हुआ था ।

(ग) पदार्थ, संभवत: 2 या 3 इंच मार्टर गोला, पास के क्षेत्र से एक ग्रामीण को मिला था, और जब वह उसे तोड़ने का यत्न करने लगा, तो वह फट पड़ा था । इसे अन्तरिक्ष से नहीं गिराया गया था ।

(घ) तथा (ङ) : सैनिक तथा पोलीस अधिकारियोंने मामले की छान-बिन की है । उनका विचार है कि विस्फोट का कारण एक मार्टर गोला था, जिसे कहीं से उठा लाया गया था । किसी प्रकार के तोड़ फोड़ कार्य का सन्देह नहीं है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

559. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती बिमला देवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 30 और 31 अक्तूबर, 1965 को भारतीय श्रम संम्मेलन की बैठकें हुई थी;

(ख) किन मुख्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा क्या सिफारिशें की गईं;

(ग) क्या सम्मेलन में केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड के उस सुझाव पर विचार किया गया था, जिसमें तीसरे बच्चे के जन्म के बाद महिलाकर्मचारियों को प्रसूति-लाभों को प्रतिबन्धित करने का अनुरोध किया गया था; और

(घ) क्या सम्मेलन में इस प्रश्न पर भी विचार किया गया कि सरकारी उपक्रमों ने अत्यावश्यक सुरक्षा तथा कल्याण के उपायों के सम्बन्ध में सांविधिक उपबन्धों का कहां तक पालन किया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवया) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ): सम्मेलन में अधिकाश समय वर्तमान संकट से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए लगाया और एक प्रस्ताव पास किया जिसकी प्रति सभा की मेज़ पर रख दी गई है **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5144/65]** सम्मेलन के सामने रखी गई बेरोज़गार बीमा योजना पर भी संक्षिप्त विचार हुआ परन्तु इस पर विचार-विमर्श स्थायी श्रम समिति के आगामी अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया ।

(ग) और (घ) : में निर्दिष्ट विषयों सहित सम्मेलन के सम्मुख रखे गए अन्य विषयों पर विचार-विमर्श भी स्थायी श्रम समिति के आगामी अधिवेशन के लिए स्थगित कर दिया गया ।

Military Colony in Delhi

560. Shri Ram Sevak Yadav : **Shri Yashpal Singh :**

Shri Madhu Limaye : **Shri Bhanu Prakash Singh :**

Shri Bagri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a military colony in Delhi for the families of the Jawans who have laid down their lives in the cause of the defence of the country;

(b) if so, whether Government propose to give them loans for constructing houses; and

(c) if so, details of the scheme ?

The Minister of Defence(Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No, Sir. There is no such scheme under consideration of Government.

(b) and (c) : Do not arise

कलपाक्कम में परिमाणु बिजलीघर

561. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री मुथिया :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के निकट कलपाक्कम में परमाण बिजलीघर की स्थापना के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए क्या प्रारम्भिक कार्य आरम्भ किये गये हैं;

(ख) कितनी लागत के उपकरणों का आयात करना पड़ेगा;

(ग) क्या इस बिजलीघर में काम करने वाले भावी तकनीकी कमचारियों को देश में तथा विदेशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री(श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) अभी तक पावर रिऐक्टरों को लगाने लिये के उपयुक्त स्थान के चुनाव से सम्बन्ध जांच कार्य जिसमें जल सर्वेक्षण और भूच्छेद कार्य शामिल हैं, हाथ में लिए गये हैं ।

(ख) आयात किये जाने वाले उपकरणों अनुमानित लागत लगभग 15 करोड़ रूपये है । इसमें भाड़ा शामिल है, परन्तु भारत में उपकरण बनाने के लिए कच्चे माल के आयात पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है ।

(ग) तथा (घ) : इस स्टशन के प्रचालन तथा देखभाल के लिये लगभग 200 तकनीकी कर्मचारिवों की आवश्यकता होगी । इनमें अधिकतर कर्मचारियों को भारत में ट्रेनिंग दी जायगी ।

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

562. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या श्रम और **रोजगार** मंत्री 13 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने खेतिहर मजदूरों के लिए पहले से निर्धारित न्यूनतम मूजरी में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे जो पुनरीक्षण तथा संशोधन किया गया है उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा चलाये जा रहे आदर्श कृषि फार्मों में काम करनें वाले खतिहर मजदूरों के लिए कितनी न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है; और

(घ) यह मजूरी किस आधार पर निर्धारित की गई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री श्री० डी० संजीवैय्या : (क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्तान, उत्तर प्रदेश ओर त्रिपुरा की सरकारों ने न्यूनतम मजुरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मज़दूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया है । एक विवरण, जिसमें मज़दूरी की पहले निर्धारित की गई दरें और संशोधन के बाद की दरें दी गई हैं, सभा की मेज़ पर रख दिया गया है ।

(ग) और (घ) : एक विवरण, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आदर्श कृषि फार्मों में नियुक्त खेतिहर मज़दूरों के लिए निर्धारित मज़दूरी की न्यूनतम दरें दर्शाई गई हैं, सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5145/65।] जहां तक राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाने वाले आदर्श कृषि फार्मों का ताल्लुक है, राज्यों ने सामान्यतः इन फार्मों में खेतिहर मज़दूरों के लिए कोई अलग दरें निर्धारित नहीं की हैं, परन्तु अन्य खेतिहर मज़दूरों के लिए निर्धारित दरें इन फार्मों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए लागू करवाई हैं ।

News Broadcasts by A.I.R.

563. **Shri Madhu Limaye :**

Shri Bagri :

Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether she has received any complaint that the news about the Indo-Pakistan hostilities in September, 1965 were being broadcast very late by the All India Radio, while the people came to know about them earlier through the B.B.C., Peking Radio and foreign radio stations;

(b) whether she has received this complaint also that the same news was repeated three to four times through the news bulletins broadcast at different times; and

(c) if so, the action being taken to up-date the news bulletins broadcast by the A.I.R. and also make them more spicy ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) (a) No, Sir. However, on one or two occasions news was held up. This was because we had to wait for confirmation of the News from Defence Services.

(b) and (c). No, Sir, Repetition of Important news is essential especially in times of emergency as many people may miss certain bulletins.

पाकिस्तानी हमल के दौरान प्रचार कार्य के लिए आकाशवाणी के कलाकारों को इनाम

564. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी हमले के दौरान बहुत उत्तम प्रचार कार्य करने के लिए कुछ स्टाफ़ आर्टिस्टों को इनाम दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इनाम दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

565. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी तथा गैर श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवय्या) : (क) श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए अलग-अलग दो मजदूरी बोर्ड स्थापित किए गए हैं । दोनों ही बोर्डों ने अंतरिम सहायता की मंजुरी के लिए सिफारिशें की हैं, परन्तु उनकी अंतिम रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) बोर्डों ने महत्वपूर्ण मामले तय करने है और उन्हें सिफारिशें करने से पहले विभिन्न पक्षों के मतों पर विचार करना है । वे यथासम्भव शीघ्रता से काम कर रहे हैं ।

ई० एम० ई० वर्कशाप

566. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से ई० एम० ई० कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को हाल में ही नौकरी से पृथक होने के नोटिस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी अभी तक 'नोटिस' की अवधि में काम कर रहे हैं;

(ग) अब तक कितने कर्मचारी नौकरी से निकाल दिये गये हैं; और

(घ) कितने कर्मचारियों को तत्समान दूसरे पद दिये जा चुके हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय ई० एम० ई० वर्कशापों और विहीकल डिपो वर्कशापों से संबंधित सूचना प्राप्य है । इन वर्कशापों के 201 कर्मचारी नोटिस अवधि पर है । उन में से अभी एक को भी डिस्चार्ज नहीं किया गया । इन वर्कशापों के 381 फाल्तू कर्मचारियों को वैकल्पिक, सन्मान अथवा अर्धकुशल श्रेणियों में निम्न कार्यों पर लगाया गया है । अन्य यूनिटों, उदाहरणत: स्थानीय वर्कशापों, चल यूनिटों इत्यादि के संबंध में, विस्तार इकट्ठे किए जा रहे हैं और सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में समझौता वार्ता व्यवस्था

567. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए समझौता वार्ता व्यवस्था पुन: स्थापित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस मामले में शीघ्रतापूर्वक अन्तिम कार्यवाही करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : यह मामला सभी केन्द्रीय, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक परामर्श संगठन स्थापित करने की योजना से संबंधित है, और सरकार के विचाराधीन है। इस दौरान में, कुछ अर्न्तग्रस्त समस्याओं पर रक्षा कार्मिक संघ से जल्दी ही विचार करने का विचार है, जिसमें शामिल है सभी केन्द्रीय, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी परामर्श संगठन स्थापित करने तक के लिए, एक वार्तातन्त्र स्थापित करना ।

पाकिस्तान द्वारा लाठीटीला क्षेत्र में गोलाबारी

568. **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री हिम्मत सिंहका** :

श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री कजरोलकर** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लाठीटीला और डूमाबाड़ी क्षेत्रों में अभी तक पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं की गोलाबारी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे विरोध पत्रों का कोई उत्तर इस बीच मिला है; और

(ग) यदि नहीं, तो विना उत्तेजना की गई इस गोलाबारी का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने सितम्बर-अक्तूबर महीनों में लाठीटीला और डूमाबाड़ी क्षेत्र में गोली चलाना जारी रखा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हमारी सेनाओं ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई हैं, और जैसे और जभी आवश्यक समझे गए, अन्य उपाय भी किए जाएंगे ।

शत्रु की कार्रवाई में मारे गये डाक तथा तार कर्मचारी

569. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन डाक तथा तार कर्मचारियों को, जो अपना कार्य करते हुए शत्रु की कारवाई मारे गये हैं, विशेष पुरस्कार तथा अन्य सुविधायें देने के लिए किसी योजना पर विचार करके उसे अन्तिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) उन सरकारी कर्मचारियों को जो पाकिस्तान के विरुद्ध की गई कारवाई में दुश्मन की कारवाई से 5 अगस्त 1965 या उसके बाद मारे गये हैं सरकार द्वारा मंजूर की गई पेंशन की बढ़ी दरें डाक-तार कर्मचारियों को भी दी जाएंगी । केवल डाक-तार कर्मचारियों के लाभ के लिए किसी दूसरी योजना पर विचार नहीं किया गया है और न ऐसी कोई योजना बनाई गई है ।

(ख) सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये, संख्या एल० टी० 5146/65**।]

चीन द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन

570. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने में चीन द्वारा किये गये भारतीय वायुसीमा के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वायु सीमा का कितनी बार उल्लंघन किया गया है; और

(ग) इन उल्लंघनों को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Cost of Power produced in Atomic Power Stations

571. **Shri Kishen Pattnayak :**

Shri Madhu Limaye :

Shri Bagri :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the cost per kw hour of power to be produced in the new three Atomic Power Stations now being established in Bombay, Rajasthan and Madras;

(b) the cost per kw per hour of power which is being produced in these areas by means of water and coal ; and

(c) the steps being taken by the Department of Atomic Energy to reduce the cost of power being produced by means of atomic energy?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) The information is given below :—

Station	*Cost per KWh nuclear power*
Tarapur Atomic Power Station	3·01 paise
Rajasthan Atomic Power Station (I Unit) .	2.80 paise
Rajasthan Atomic Power Station(II Unit) . .	2·64 paise
Madras Atomic Power Station	2·64 paise

(b) The estimates of costs per KWh of thermal power, if thermal stations were to be set up in the Delhi-Punjab-Rajasthan and Madras regions, and the basis on which the estimates have been prepared are contained in Tables I & II which are attached. **[Placed in the Library, See No. LT-5147/65].** Details of the cost of power from the Neyveli thermal power generating schemes are also given in an attached Table III. The details of the cost KWh of hydro and thermal power, which has already been produced in the three areas, namely, Maharashtra, Rajasthan and Madras are being collected and will be placed on the table of the House.

(c) The Department has proposed the building of a proto-type power station (Project NUHMOC) with a view to carrying out studies *inter alia* in the economics of nuclear power generation, by using different coolants such as organic and steam. The Department will furthermore keep abreast with technological developments in other countries with a view to the adoption in this country of promising developments elsewhere.

गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास

572. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रतिरक्षा मंत्री 30 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 572 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ का नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास करने के सम्बन्ध में परामर्शदात्री फर्म के प्रतिवेदन की जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं। इस पर अभी विचार हो रहा है

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज का स्मारक

573. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक के पुनर्निमाण के बारे में 14 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विषय में सिंगापुर सरकार से आगे बातचीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने इस मामले में कोई उपक्रम नहीं किया है और इसके कारण वही हैं जो 14-4-1956 को लोकसभा के प्रश्न संख्या 1437 के उत्तर में दिए गए थे । परन्तु, अगर सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के लोग वहां की सरकार की अनुमति से इसकी कोई योजना तैयार करें तो उसमें भारत सरकार सहर्ष पूरा सहयोग और सहायता देगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्रास बार स्विच इक्विपमेंट

574. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सेझियान :
श्री बसुमतारी :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैल्जियम की बैल टेलीफोन कम्पनी द्वारा भारत को भेजे गये एक लाख रुपये के मूल्य के 'क्रास बार स्विच इक्विपमेंट' को कराची में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने ज़ब्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी प्राधिकारियों से इस माल को छुडाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां । किन्तु स्टीमशिप 'रवेनफेल्स' से उपस्कर उतार कर उसे जहाज तक निःशुल्क लाने का मूल्य (एफ० ओ० बी० वेल्यू) 18.9 लाख रुपये था, 1 लाख रुपय नहीं । इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि "सेलीवीज़" नाम के एक दूसरे जहाज से भी टेलीफोन उपस्कर कराची में उतार लिये गए हैं । उन्हें जहाज तक निःशुल्क लाने का मूल्य 4.2 लाख रुपय है ।

(ख) उक्त जहाज तटस्थ देशों के हैं और पाकिस्तान ने उन्हें भारतीय माल को उतार लिये जाने के बाद छोड़ दिया है । पाकिस्तान सरकार द्वारा ज़प्त किये गए माल की वापसी के लिए सरकार द्वारा राजनयिक व अन्य तरीकों से सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं ।

Compensation for Lost Articles

575. **Shri D. N. Tiwari :** Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 905 on the 19th April, 1965 and state :

(a) whether the people whose articles were lost in the Safdarjang Airport Post Office have been paid compensation;

(b) the result of the investigation; and

(c) the action taken against the persons concerned ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagwati) : (a) Fourteen claims in respect of Insured articles have been settled so far.

(b) Departmental and Police enquiries are still in progress.

(c) One official who is the suspect in this case, is under suspension. Disciplinary action will be taken after the departmental and police enquiries are concluded.

मोटरगाड़ी परिवहन के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

576. **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या श्रम और **रोजगार** मंत्री 13 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गाड़ी परिवहन के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवय्या) : कुछ राज्य सरकारों से उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

Honorary Consul in Geneva

577. **Dr. Ram Manohar Lohia :**

Shri Kishen Pattanayak :

Shri Ram Sevak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have appointed an Honorary Consul in Geneva recently;

(b) if so, whether this Consul is an Indian national or a foreign national; and

(c) if he is a foreign national, the reason for appointing a foreigner ?

The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh) : (a) No, Sir. There is a Consul General of India in Geneva, who is a member of the Indian Foreign Service.

(b) and (c). Do not arise.

Defence Plan

578. **Shri Ram Manohar Lohia :**

Shri Kishen Pattnayak :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the estimated total expenditure involved on the Five Year Defence Plan

(b) how much of it will be met from the internal resources and how much from the external resources; and

(c) whether any agreement has been concluded with the Governments of any foreign country and whether those Governments are discharging their obligations in time according to the respective agreements?

The Minister of Defence (Shri Yashwantrao B. Chavan) : (a) The estimated total expenditure on the Defence Plan was Rs. 5,000 crores.

(b) The foreign exchange expenditure involved is about 14 per cent. Even out of this expenditure, a substantial portion was to be met from out of our own resources. In the light of the recent supension of aid from US and UK the proportion to be met out of our resources may have to be higher.

(c) There were understanding under which US and UK had offered to supply military equipment. Following the Pakistani aggression, these Governments have suspended shipment of military material.

Press Correspondents on Forward Areas

579. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any arrangements were made for the Press correspondents to visit the forward areas at the time of Indo-Pak conflict;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Arrangements were made for Press correspondents to visit forward areas in small parties from the Srinagar, Jammu and Amritsar bases. Parties were conducted to the forward areas by the Defence authorities. Press facilities at the three bases were expanded. Press camps were organised and liaison was maintained with the State Governments and the Posts and Telegraphs Department. Pressmen were helped to get speedy air and railway bookings from Delhi to the Punjab and to Jammu and Kashmir. For foreign Pressmen permits as required under the Defence of India Rules, were arranged for transit through the prohibited areas of Ambala and Jullundur.

भारत का सैनिक सामान का नुकसान

580. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** **श्री जसवन्त मेहता :**

श्री दलजित सिंह : **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :**

क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारत के विमानों, टैंकों तथा अन्य हथियारों की हुई हानि का अनुमान लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस नुकसान को, विमान तथा हथियार प्राप्त करने अथवा बना कर, पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग): हाल के भारत पाक संघर्ष में अन्तरिक्ष युद्ध में हमारे 35 विमानों की हानि हुई, और 80 टंकों की। 48 टैंक बुरी तरह खराब हुए थे परन्तु वह मरम्मत योग्य हैं। क्षतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक पग उठाए गए हैं।

Deposits in Post Offices in Punjab

581. Shri Daljit Singh : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the total amount deposited in the Post Offices in Punjab under the Small Savings Scheme upto 1st October, 1965?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagwati) : The amount of gross deposits in respect of C.T.D. Savings Certificates and Defence Deposit Certificates from 1-1-65 to 31-8-65 made in Post offices in Punjab State is Rs. 7,35,45,505. Figures for September, 1965 are not available.

The amount of gross deposits in Post Office Savings Bank from 1-1-65 to 31-3-65 in the Post Offices in Punjab State is Rs. 8,64,37,314. Figures, for the period from 1-4-65 to 30-9-65 are being collected.

जकर्ता में मारे गये छः जनरलों की अन्त्येष्टि

582. **श्री काजरोलकर :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजदूत ने अन्य देशों के दूतों के साथ हाल में जकर्ता में मारे गये छः जनरलों के अन्त्येष्टि समारोह में भाग लिया था; और

(ख) क्या मारे गये जनरलों की स्मृति में जकर्ता में हमारे मिशन का झंडा झुकाया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारतीय राजदूत इन छः जनरलों की अन्त्येष्टि में शामिल नहीं हुए थे।

(ख) जी हां।

कारतूसों का निर्माण

583. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आयुध कारखानों ने अधिक अच्छे किस्म के 22 'टारगेट' वाले कारतूस बनाने में क्या प्रगति की है; और

(ख) ये कारतूस रायफल क्लबों के प्रयोग के लिये बाजार में कब तक मिलने लगेंगे ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सदस्य महोदय के मन में शायद, '22 कारतूस (प्रतियोगिता चान्दमारी बारूद) का ध्यान है । इस प्रकार के गोली बारूद के किसी प्रकार के विकास के लिए, आयुध कारखानों ने अभी कोई प्रायोजना तैयार नहीं की ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Symposium of Poets

584. Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Dhuleswar Meena :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a "Kavi Sammelan" (Symposium of poets) was held in Delhi on the 30th September and 1st October, 1965 for raising contributions for the National Defence Fund; and

(b) if so, whether Government propose to lay on the table of the House a statement of receipts and expenditure thereon?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : (a) and (b). A Kavi Sammelan was held at Sapru House, New Delhi on the 30th September, 1965 (and not the 1st October, 1965). A sum of Rs. 5,653 was presented to the Prime Minister at the Sammelan for the National Defence Fund. Final statement of receipts and expenditure pertaining to the Sammelan is still awaited from the organisers.

अपक्षारीकरण (डीसेलिनाइजेशन) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय परिसंवाद

585. **श्री रामसेवक यादव :**

श्री मधु लिमये :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में वाशिंग्टन में हुई अपक्षारीकरण सम्बन्धी परिसंवाद में परमाणु ऊर्जा के प्रयोग द्वारा अपक्षारीकरण की अमरीका और मेक्सिको की संयुक्त परियोजना की घोषणा की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत स्वयं अथवा अन्य देश के सहयोग से क्या कार्य कर रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां । अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ऐजन्सी भी इस प्रायोजना में सहयोगी है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग आजकल स्वतन्त्र रूप से इस विचार से अध्ययन कर रहा है :—

(i) पानी और विद्युत शक्ति की मात्रा, जोकि अपक्षारीकरण संयंत्र-परमाणु विद्युत स्टेशन में पैदा की जा सकेगी, को बढ़ाना; और

(ii) पानी तथा बिजली जो ऐसे दुकाजो संयंत्र में पैदा हो सकेगी की लागत का अनुमान लगाना ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

586. **श्री हेडा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना की है कि सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश में भूमि दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि पंजाब सरकार ने इस प्रकार की कोई प्रार्थना की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुख्यालयों में रेडियो स्टेशन

588. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावकारी रूप से युद्ध समाचार देने के लिये विद्यमान रेडियो स्टेशन पर्याप्त हैं,

(ख) क्या सभी महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों में शार्टवेव के रेडियो स्टेशन खोलने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर रेडियो स्टेशन खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं । कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सेकेन्ड ग्रेड शार्ट वेव से सुने जाते हैं ।

(ख) आन्तरिक सेवा के लिये शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सिफ़ारिशों के विरुद्ध है । फ़िर भी, चौथी पंचवर्षीय योजना में और मिडियम वेव ट्रांसमीटर लगाने की योजना है ताकि देश भर में कार्यक्रम सुने जा सकें ।

(ग) प्रस्तावित केन्द्रों/मिडियम वेव ट्रांसमीटर के केन्द्रों के स्थान योजना आयोग के परामर्श से अभी निश्चित किये जाने हैं ।

Hindu-Muslim Unity

590. **Shri Kishen Pattnayak** : Will the Minister of **Informa on** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any new measures have been adopted or any new schemes formulated by her Ministry with a view to strengthen the National Solidarity in the background of the Indo-Pak conflict; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). National solidarity has always been one of the main guidelines of the publicity policy of the Government of India. National unity and the wholehearted cooperation of all the sections of the people with the Government in the recent conflict with Pakistan have been self-evident. In the background of the Indo-Pakistan conflict there has been a sustained campaign aimed at focussing the public mind on the need for utmost unity and solidarity through all media of publicity, as briefly indicated below :

Directorate of Advertising and Visual Publicity : A campaign to strengthen national solidarity was undertaken through Press advertisements, posters, hoardings and cinema slides. Several slogans have been popularised through various media. These are: "One Great Country, One Great People; "We are All Indians, Let None Divide Us", "Jhanda Ooncha Rahe Hamara", "You are a Soldier too" and "Think, Speak and Act as One"

The Press advertising campaign is being undertaken with the cooperation of over 1100 newspapers and periodicals throughout the country who have kindly offered free space. Approximately 9,000 cinema slides have been (or are being) produced for exhibition for a period of six months in cinema houses.

All India Radio : While the regional stations of All India Radio chiefly cater to the cultural requirements of different categories of listeners of the regions, national unity is emphasised through centrally organised programmes at headquarters such as National programmes of music, talks, plays and features and by certain annual features such as Sangeet Sammelan, National Symposium of Poets, Sahitya Samaroh, Sardar Patel Memorial Lectures, etc. All stations of A.I.R. arrange different programmes addressed to different categories of listeners, with emphasis on lessons of history, national security and economic interdependence. Members of minority communities are provided opportunity to take part in AIR's programmes. Every year October 20 is observed as National Solidarity Day. This year features on Gandhiji, Pandit Nehru and Acharya Vinoba Bhave's concept of and contribution to national solidarity were broadcast. Similar features on the lives and sayings of Swami Sankaracharya, Sant Kabir and Shri Nehru are going to be broadcast.

Publications Division : A book entitled "When Freedom is Menaced" containing the Prime Minister's speeches which stress secularism and unity has been brought out in English, Hindi and Urdu. Other publications of importance are : "In the Face of Aggression", "Indian Muslims Speak", "The Harvest of Glory". The Division's journals carry appropriate material on the subject. It is proposed to bring out books of patriotic songs and poems in Hindi and Urdu. State Governments have been advised to bring out similar books in the respective regional languages.

Directorate of Field Publicity : National solidarity remains a constant theme. However, special emphasis was laid on this in all field publicity activities. The Prime Minister's broadcasts were fully utilised by all field units. Soon after the ceasefire, special campaigns were launched in the border areas for promoting integration of the border people emphasizing the economic aspects of national solidarity.

Press Information Bureau : The defence efforts of people from all walks of life were highlighted, particular stress being laid on the acts of bravery of minority communities. Pakistani propoganda directed to minority communities was effectively countered. Statements of Muslim leaders condemning Pakistan were publicised. These publicity campaigns are being continued emphasising that unity is essential not only in the face of the enemy attack, but also in fighting the battle for self-sufficiency at home.

Song and Drama Division : The Division has prepared a play called 'Koh-i-Noor ka Lutera' in the context of Chinese aggression and 110 performances of this play have been presented to date. In its composite programme HAM TUM AUR WOH started recently, National Solidarity has been greatly emphasised. Over eighty performances of the programnme have been given to date.

Films Division : Besides laying emphasis on Emotional Integration and National Unity in documentaries produced by the Films Division, coverage is being provided in weekly newsreels to items which have a bearing on this theme. The following two films have been produced :

1. Vice-President's Message.
2. Unity-call of the Hour.

The first one has been released to the public on 24-9-1965 and the second will be released shortly.

भारतीय दूतावास तथा राजनयिक

591. **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री पाराशर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बृजराज सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सरकार द्वारा बड़ी संख्या में रखे गये दूतावासों, और राजनयिकों के बावजूद भी भारत का पक्ष विश्व के सामने हमेशा सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(ख) दूतावासों के कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए मंत्रालय में क्या व्यवस्था है; और

(ग) क्या विदेशी सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध, जिसका कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है, कभी कोई कार्यवाही की जाती है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं। विदेश-स्थित हमारे सभी मिशन दुतरफ़ा संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भारत के विचार सशक्त और सुस्पष्ट रूप में रखते हैं। हमारे राजनयिकों ने सहिष्णुता, धैर्य और चतुराई के साथ कारगर रूप से काम किया है, और इसमें एक हद तक सफलता भी मिली है, जो जरूरी नहीं कि अखबारों में सुर्खियों में छपे-ही-छपे, और जिसे, प्रत्यक्ष कारणों से, पूर्ण रूप में प्रचारित भी नहीं किया जा सकता। हां, इतना बेशक

कहा जा सकता है कि उनपर जो बहुत-से काम डाले गए थे, उनके मुकाबले में, बहुत सीमित कर्मचारी होने के बावजूद, हमारे मिशनों ने उन निर्देशों के आधार पर बहुत अच्छी तरह से काम किया है जो उन्हें समय-समय पर दिल्ली से दिए जाते थे ।

(ख) विदेश मंत्रालय में प्रादेशिक प्रभाग हैं जो विदेश-स्थित भारतीय मिशनों से आने वाले सभी पत्रादि पर और विशेष रिपोर्टों पर सावधानी-पूर्वक विचार करते हैं और उसके बाद अपनी विदेश नीति के सिद्धातों के अनुरूप निर्णय लिए जाते हैं और निर्देश भेजे जाते हैं ।

(ग) मिशन प्रमुखों समेत, हर व्यक्ति के काम का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है । संबद्ध व्यक्ति की कमज़ोरियाँ और कमियां लिखित रूप में उसे बता दी जाती हैं, और जो अकुशल पाया जाता है उसके खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है ।

सैनिकों के परिवारों का भरण-पोषण

592. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दाजी :
श्री वारियर :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 10 तथा उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में मारे गये अथवा स्थायी रूप से अपंग हुए सैनिक अधिकारियों तथा जवानों के बच्चों को शिक्षा छात्रवृत्तियां, निशुल्क शिक्षा तथा अन्य रियायतें देने और उनके अन्य आश्रितों को भूमि देने के प्रश्न पर और आगे विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या अन्य रैंकों (जवानों) के वेतन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख): संक्रिया में मारे गए अथवा निर्योग्य हो गए सेवाओं के सेवीवर्ग के बच्चों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा, पहले से ही, विभिन्न शिक्षा सुविधाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, परन्तु शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस मामले में एक व्यापक योजना कार्यान्वित की जा रही है । राजस्थान में कृषि योग्य भूमि देकर, निर्योग्य हो गए सैनिकों और निर्योग्य हो गए तथा मारे गए सैनिकों के कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए राजस्थान सरकार के साथ सलाह-मशविरे के साथ एक योजना विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) : यह प्रश्न निरीक्षण-अधीन है ।

Telephone Directory in Hindi

593. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Hindi speaking states of Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Bihar have represented to the Ministry of Communications and the officers of the Regional Posts and Telegraphs Departments of these States requesting them to publish the telephone directory in Hindi; and

(b) if so, when it is likely to be published ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagvati) : (a) and (b) : Instructions have been issued for printing some percentage of the telephone directories of Rajasthan, U.P., Madhya Pradesh, Bihar and Delhi in Hindi. Efforts are being made to bring out these directories as early as possible.

आसाम पर जेट विमान जिसको पहचाना नहीं जा सका

594. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अक्तूबर, 1965 को आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में धुबरी के निकट एक जैट विमान 10 मिनट तक देखा गया जिसको पहचाना नहीं जा सका था और जो पूर्व-पाकिस्तान की ओर उड़ गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी जांच करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि वह विमान कहां से आया था तथा उसके वहां पर आने का उद्देश्य क्या था ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक सेवायें

595. श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री गोकरन प्रसाद :**
श्री बृजराज सिंह : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) साधारण पत्र,

(दो) एक्सप्रेस पत्र,

(तीन) मनीआर्डर,

(चार) तार पहुंचाने में 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् अब तक अधिकतम कितनी देरी हुई है, और

(ख) प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) और (ख) : सूचना उपलब्ध नहीं है, चूंकि इस प्रकार की सूचना के कोई रिकार्ड नहीं रखे गए हैं । चालू रिकार्ड से भी उक्त सूचना भारत भर से प्राप्त लगभग $7\frac{1}{2}$ लाख शिकायतों से उपलब्ध करना मुश्किल होगा ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से बिना तार का संचार-सम्पर्क

596. श्री हेडा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 6 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1547 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बीच सीधा बिना तार का संचार का सम्पर्क स्थापित हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके लिये कौन सी अन्तिम तिथि निश्चित की गयी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रडार व्यवस्था

597. **श्री दे० द० पुरी :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि पाकिस्तान की सीमा पर हमारी समुचित रडार व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो उसे सुव्यवस्थित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार युद्ध के समय मानवीय भूल से बचने के लिये एक स्वचालित खतरे की घंटी की व्यवस्था करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : यह मामला सरकार के विचाराधीन है । लोकहित में विस्तार प्रकट नहीं किए जा सकते ।

(ग) इस समय ऐसा कोई सुझाव नहीं है ।

Jodhpur Airport and Training College

598. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri D. D. Puri :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Jodhpur Airport and Air Force Training College have been badly damaged as a result of the bombing by Pakistan;

(b) whether it is a fact that Government are contemplating to shift that College to Hyderabad; and

(c) if so, the time by which this task will be completed ?

The Minister of Defence (Shri Yashwantrao B. Chavan) : (a) No Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The proposed permanent Air Force Academy which will replace the Air Force Flying College and a few other training institutions is expected to start functioning in 1968-69. However, it is proposed to shift the College to Begumpet under temporary arrangements even by August, 1966.

पंजाब में टेलीफोन केन्द्र तथा डाकघर

599. **श्री दलजीत सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में पंजाब राज्य में कितने और कहां-कहां तारघर तथा पब्लिक काल आफिस स्थापित किये जायेंगे; और

(ख) क्या विद्यमान टेलीफोन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाये जाने की संभावना है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) (i) 1965-66 में पंजाब राज्य में पांच तारघर स्थापित किये जाएंगे । उनके स्थान ये हैं :—

1. कहनुवान (खोल दिया गया)
2. सेक्टर-20 चंडीगढ़ (खोल दिया गया)
3. दुखनीवारन (खोल दिया गया)
4. चनौर (खोल दिया गया)
5. अनी

(ii) 1965-66 में पंजाब राज्य में चार दूरवर्ती सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किये जाएंगे। उनके स्थान ये हैं :—

1. कहनुवान (खोल दिया गया)
2. बालाचीर (खोल दिया गया)
3. समघभाई
4. अनी

(ख) जी हां । वास्तव में टेलीफोन केन्द्रों की कुछ क्षमताएं पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं ।

Telephone Wire Thieves

600. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recently uneaithed an inter-state gang of telephone wire thieves and arrested some of its members in New Delhi;

(b) whether any telegraph employee is also involved; and

(c) whether an enquiry has been instituted and if so, the result thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagwati) : (a) Two persons were arrested on 9-10-1965 while stealing telephone wires from a Distribution Point in Sewa Nagar area in New Delhi. They are reported to be connected also with certain other thefts at places outside Delhi-jurisdiction.

(b) Yes. One of the arrested persons was a mazdoor in the regular employ of the P. & T. Department.

(c) Investigation by the Police is still in progress.

A.I.R. Artistes in Forward Areas

601. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that teams of A.I.R. artistes have been sent to Lahore area and other places by her Ministry;

(b) if so, the places they visited; and

(c) the amount spent by them on their programmes there ?

The Minister of Information and Broadcasting (Smt. Indira Gandhi) : (a) to (c). Full information is being collected and will be laid on the table of the House. However, as far as we know, five artistes from Delhi and Jullunder were booked by the Srinagar Station for entertainment of troops in forward areas.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैदेशिक कार्य-मंत्री के भाषण

602. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिये गये उनके तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधि के भाषणों-को अमरीका द्वारा रेडियो तथा टेलीविज़न पर प्रसारित करके किये गये पक्षपातपूर्ण व्यवहार की ओर ध्यान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार को इस बारे में बताया गया है और उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अमरीका के रेडियो और टेलिविजन में विदेश मंत्री अथवा पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषणों को अधिक समय नहीं दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रतिनिधि के भाषणों की रिपोर्ट देने में उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के पक्ष में अथवा विदेश मंत्री के विरुद्ध जाहिरा तौर पर कोई पक्षपात नहीं दिखाया ।

(ख) अमरीका का रेडियो और टेलिविजन पूर्ण रूप से प्राइवेट नियत्रंण में है और इस मामले में अमरीका की सरकार से कोई शिकायत करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

केरल ग्रांधशाला संघम्

603. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **सूचना और प्रसार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल ग्रांधशाला संघम् ने प्रार्थना की है कि योजना के प्रचार का कार्य उसे सौंपा जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) केरल ग्रंथशाला संघम् से एक प्रस्ताव मिला है जिसमें उन्हों ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें अपने पुस्तकालय व सामाजिक केन्द्रों द्वारा योजना के प्रचार के लिए कुछ श्रव्य-दृश्य सामान तथा एक गाड़ी दी जाए ।

(ख) मन्त्रालय साधारणतः अधिक अनुदान नहीं देता । इस समय हमें अधिक से अधिक किफ़ायत करनी है इस लिए सामान या गाड़ी खरीदने के लिए सहायता देना संभव नहीं । फिर भी संघम् द्वारा संचालित महत्वपूर्ण पुस्तकालयों का योजना प्रचार के लिए पूरा पूरा उपयोग किया जाएगा ।

क्षेत्र-प्रचार अधिकारी

604. डा० महादेव प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 30 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष के दौरान प्रतिरक्षा की तैयारी के सम्बन्ध में क्षेत्र-प्रचार अधिकारियों ने क्या कार्य किया, और

(ख) उस पर कितना खर्च हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों ने अपने अधीन प्रचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर देश में रक्षा तैयारी में साहयता की । निम्नलिखित कार्यक्रम खास तौर से आयोजित किए गए :—

(1) भारत की रक्षा की तैयारी सम्बन्धी फ़िल्मों का प्रदर्शन । ऐसे अवसरों पर जो वार्त्ताएँ दी गईं, उन में राष्ट्रीय रक्षा के महत्व और रक्षा की तैयारी करने में लोगों के कर्त्तव्यों पर जोर दिया गया ।

(2) सार्वजनिक सभाएं आयोजित की गई, जिन में उक्त विषयों पर स्वयं क्षेत्रीय अधिकारियों, अन्य अधिकारियों और प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा वार्त्ताएं दी गई ।

(3) देश भर में विद्यार्थियों और जवानों पर विशेष ध्यान दिया गया और कालेजों एवं स्कूलों में और गैर-सरकारी और सरकारी संस्थानों के तत्वावधान में तथा ऐच्छिक संस्थाओं के सहयोग से बड़ी संख्या में कार्यक्रम आयोजित किए गये जिन में वार्त्ताओं एवं गोष्ठियों और उनके साथ फ़िल्म शो तथा अन्य कार्यक्रमों में रक्षा की तैयारी के महत्व पर प्रकाश डाला गया ।

(4) प्रचार साहित्य, पोस्टर, फ़ोल्डर, आदि के माध्यम से भी रक्षा की तैयारी के महत्व पर प्रकाश पर डाला गया ।

(5) युद्ध के मोर्चे से लगे क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारियों ने नागरिक अधिकारियों और जहां आवश्यक हुआ सैनिक अधिकारियों के साथ मिल कर काम किया और लोगों को नागरिक सुरक्षा के उपाओं और देश रक्षा के काम में नागरिक क्या कर सकते हैं, इस के बारे में बताया ।

(ख) कोई विशेष खर्च नहीं हुआ, क्योंकि ये सब काम वर्तमान क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों द्वारा ही किए गए ।

कोयला खानों के मजदूर

605. डा० महादेव प्रसाद : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में मजदूरों की भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता अथवा न करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : श्रम संस्थान, गोरखपुर के माध्यम से अकुशल कर्मचारियों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक और वित्त सम्बन्धी मौजूदा प्रबन्ध जारी रहेगा ।

गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में नियुक्तियों के बारे में शिकायतें

606. **श्री महादेव प्रसाद** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 16 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में हुई नियुक्तियों के बारे में उनसे की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में नियुक्तियों के बारे में श्रम और रोजगार मंत्री को जून, 1965 में दिए गये ज्ञापन में निम्नलिखित शिकायतें की गई थीं :—

(i) कारखाने का प्रशासनिक ढांचा बहुत ही बड़ा है। कारखानों का जनरल मैनेजर उत्तर प्रदेश का नहीं है। श्रेणी I और श्रेणी II सेवाओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बहुत कम है ।

(ii) श्रेणी III और IV के पदों पर अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा प्रतिशत में लोग लिए गए है ।

(iii) अन्य स्थानों पर भर्ती किए गए व्यक्ति गोरखपुर कारखाने में बदल दिए गए हैं ।

(iv) रोजगार के मामले में स्थानीय व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जा रही ।

(v) निर्वासित व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया गया ।

(ख) (i) यह सही नहीं है कि कारखाने का प्रशासनिक ढांचा बहुत बड़ा है। श्रेणी I और श्रेणी II के मंजूर पद तथा वास्तव में नियुक्त व्यक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :—

	मंजूर पद	नियुक्त व्यक्ति
श्रेणी I . .	44	37
श्रेणी II . .	93	63

ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि जनरल मैनेजर हमेशा उत्तर प्रदेश का होगा।

श्रेणी I और श्रेणी II के लिए उम्मीदवारों का चुनाव सर्वथा योग्यता के आधार पर किया जाता है। जनरल मैनेजर, उन द्वारा स्वयं नियुक्ति की गई चुनाव समिति के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह प्रशासनिक अधिकारी के लिए पी० सी० एस० अफसर की और सतर्कता अधिकारी के लिए पुलिस अधीक्षक की सेवाएं उधार के रूप में दें।

(ii) श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के बारे में स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्त के लिए प्राथमिकता दी गई है। यह निम्न विवरण से जाना जा सकता है :-

नियमित कर्मचारी

कर्मचारी की श्रेणी	नियुक्त कर्मचारी	उत्तर प्रदेश से				बाहर के
		पश्चिमी	पूर्वी	निर्वासित	कुल	
श्रेणी III . . .	345	39	200	2	241	104
ट्रेड अप्रेंटेसिज .	147	..	119	6	125	22
श्रेणी IV .	132	12	47	34	93	39
योग .	624	51	366	42	459	165

दिहाडी पर काम करने वाले कर्मचारी

निर्वासित व्यक्तियों की संख्या	निर्वासित न किए गए व्यक्तियों की संख्या			कुशल और अकुशल निर्वासित व्यक्तियों में वितरण		कुल योग
	पूर्वी उत्तर प्रदेश	अन्य	कुल	कुशल	अकुशल	
414	299	43	342	266	76	756

(iii) सिन्द्री फैक्टरी से कुछ फालतू कर्मचारी गोरखपुर फैक्टरी को स्थानांतरित किए गए हैं।

(iv) रोजगार दफ्तरों द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से लोहार और बढ़ई जैसे कुशल मजदूर भर्ती करने में कारखाने के प्रशासन के प्रयास सफल नहीं हुए है। उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश से सहायता के लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने रोजगार निदेशक से उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा अन्य जिलों से वांछित हैसियत के मज़दूर भर्ती करने में फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद करने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि यदि निदेशक कारखाने या उसके ठेकेदारों की आवश्यकता की पूर्ति न कर सके तो मैनेजमेंट अपनी आवश्यकता की पूर्ति दिल्ली और पंजाब से कर सकती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि तत्काल आवश्यकता के लिए बाहर से कुशल मज़दूर नियुक्त किए जा सकते हैं ताकि काम शरू होने में देरी न हो।

(v) निर्वासित परिवार 572 हैं। जनरल मैनेजर अब जिला अधिकारियों की सहायता से सभी निर्वासित परिवारों की एक सूची बनाने और उनके बेरोज़गार वयस्क सदस्यों को श्रेणी 'ए' और 'बी' में विभाजित करने की एक योजना बना रहे हैं। आश्वासन प्रत्येक निर्वासित

परिवार में से केवल एक सदस्य के रोजगार के बारे में था। इसलिए परिवार के मुखिया के विकल्प पर केवल एक सदस्य श्रेणी 'ए' में रखा जायेगा, अन्य सदस्य श्रेणी 'बी' में रखे जायेंगे। जनरल मैनेजर सभी व्यक्तियों को श्रेणी 'ए' में नियुक्त करने के लिए अपना विशेष दायित्व समझेंगे। वह श्रेणी 'बी' में से यथासम्भव व्यक्तियों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। श्रेणी 'ए' के व्यक्तियों को भी स्थायी रूप से खपा लेने के प्रयास किय जायेंगे। जनरल मैनेजर से इस बात की जांच करने के लिए कहा गया है आया कि स्थायी रूप से रखने के लिए श्रेणी 'ए' के व्यक्तियों को समुचित ढंग से लैस करने के लिए उत्तर प्रदेश के उद्योग और श्रम विभाग द्वारा व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा स ुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी प्रशिक्षण योजनाओं और जनरल मैनेजर द्वारा शुरू की जाने वाली योजना में समंजन करने के लिए सहमत हो गई है।

खानों का एकीकरण

607. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटियां :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री 6 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1590 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर खानों के अनिवार्य एकीकरण के प्रभाव का सरकार ने अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) बलवन्त राय मेहता समिति ने, जोकि बंगाल और बिहार की छोटी तथा अलाभकर कोयला-खानों में सर्वेक्षण करने और इन कोयला-खानों के कीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए स्थापित की गई थी, मजदूरों पर प्रस्तावित एकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया है।

(ख) समिति ने यह महसूस किया कि एकिकरण के कारण मजदूरों के कुल रोजगार में कोई विशेष परिवर्तन की आशा नहीं है; केवल क्लर्कों और कुछ अन्य कर्मचारियों की श्रेणी में कुछ कर्मचारी फालतू हो सकते हैं। सरकार ने सिद्धांततः कोयला-खानों के एकीकरण के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

पंजाब के औद्योगिक एकक

608. **श्री दे० द० पुरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के बहुत से औद्योगिक एकक पाकिस्तानी बमबारी के कारण नष्ट गये थे; और]

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक एककों को पूर्ववत् बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादूर शास्त्री) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत द्वारा मान्य देश

609. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत ने किन-किन देशों को मान्यता प्रदान की है;

(ख) भारत ने किन-किन देशों को मान्यता नहीं दी; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता तो प्रदान की है, किन्तु उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : भारत एक चीन गणराज्य को छोड़ कर बाकी सभी स्वतंत्र राज्यों को मान्यता देता है।

(ग) वित्त तथा कर्मचारियों की और अन्य कठिनाइयों के कारण जिन राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं, किन्तु जिन्हें भारत मान्यता देता है, उनके नाम है : मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो (ब्राज़ाविल), नाइजर, छाड, गबोन, इसराइल, माल्दीव द्वीपसमूह, निकारागुआ, एलसाल्वेडोर, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, कोस्टारिका, हाइटी, होन्डुरास, डोमीनिकल रिपब्लिक, आइसलैंड।

2. चूंकि रंगभेद और उपनिवेशवाद का विरोध करना भारत की नीति है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए गए थे; और अल्बानिया के रवैये के कारण उसके साथ हमारे राजनयिक संबंध इस समय स्थगित हैं।

ब्रिटेन के समाचारपत्रों के सम्वाददाता

610. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** : क्या सूचना और प्रसारण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बी० बी० सी० और ब्रिटेन के समाचार पत्रों के संवाददाताओं को समाचार प्राप्त करने के लिये अग्रिम क्षेत्रों में जाने की अधिक सुविधायें दी गई थीं, जब कि अन्य देशों के संवाददाताओं को तत्समान सुविधायें नहीं दी गई थी, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

पर्वतीय डिवीजन

611. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितनी पर्वतीय डिवीज़न बनाई गई हैं;

(ख) क्या मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अनुसूची के अनुसार भरती की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन पर्वतीय डिवीज़नों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : अब तक स्वीकृति दिए गए सभी पर्वतीय डिवीज़न खड़े कर लिए गए हैं। भर्ती जो किन्हीं डिवीज़न विशेषों के लिए नहीं बल्कि कोरों और रेजिमेंटों के लिए की जाती है, प्राय: अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार जारी है। सेवा से विमुक्ति तथा हताहतों के कारण क्षति, और समय समय पर नई स्वीकृत यूनिटों में रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधी, डिवीज़नों, और अन्य उन यूनिटों और विरचनाओं की आवश्यकताएं, कि जो डिवीज़नों के अंश नहीं होते, इस प्रकार भर्ती किए गए व्यक्तियों से जुटाई जाती हैं।

(घ) 1962 में आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् पर्वतीय क्षेत्रों से भर्ती कार्य को बढ़ावा देने के लिए पालमपुर, शिमला, श्रीनगर, जम्मू, अलमोंडा, लैंडसडाउन, शिलांग, सिलचर और जोर्हट के वर्तमान् केन्द्रों के अतिरिक्त हमीरपूर, तेजपुर और गौहाटी में तीन भर्ती कार्यालय खोले गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के अन्दरूनी भागों में भर्ती करने वाले दलों को भेज कर विशेष भर्ती कार्य भी सम्पन्न किए गए हैं, और इन क्षेत्रों से रंगरूट प्राप्त करने में किसी विशेष कठिनाइ की रिपोर्ट नहीं मिली ।

पाकिस्तान के विदेश मन्त्री द्वारा गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग

612. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 अक्तूबर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा भारत के विरुद्ध उत्तेजनात्मक गाली-गलौज पूर्ण भाषा का प्रयोग किये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें वह समस्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनयिक सीमाओं को लांघ गये बताये जाते हैं?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : 25 अक्तूबर, 1965 को पाकिस्तानके विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद की बैठक में अत्यंत अपमानजनक वक्तव्य दिया। 27 अक्तूबर 1965 को भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के प्रधान के नाम एक पत्र भेजा जिसमे उन्होंने यह बताया कि इस वक्तव्य के द्वारा सुरक्षा परिषद का घोर अपमान किया गया है, मंच का दुरुपयोग किया गया है और उससे भारतीय जनता का अपमान हुआ है। कार्रवाई का ज़ोरदार विरोध करते हुए, उन्होंने इसपर आश्चर्य प्रकट किया कि सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्र के प्रति इस प्रकार की अश्लील गालियां दिए जाने के लिए बैठक का दुरुपयोग किए जाने की इजाज़त दी।

इस पत्र की एक प्रति 5 नवंबर 1965 को सदन की मेज़ पर रख दी गई थी।

समुद्री और औद्योगिक डीजल इंजन परियोजना

613. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के मैसर्स मान के इंजीनियरों के दल ने समुद्री और औद्योगिक डीज़ल इंजन परियोजना के सम्बन्ध मे अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्किम के ऊपर अज्ञात विमान

614. **श्री काजरोलकर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 अक्तूबर, 1965 को सिक्कम के ऊपर भारतीय वायु सीमा मे एक अज्ञात विमान देखा गया था;

(ख) क्या यह चीनी विमान था, जो टोह लेने के लिए उड़ान कर रहा था; और

(ग) विमान कितनी देर तक भारतीय वायुसीमा में रहा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

रेडियो लाइसेंस

615. **श्री काजरोलकर** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बडे :

श्री युद्धवीर सिंह :

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो लाइसेंस जारी करने की नई प्रणाली नवम्बर, 1965 से लागू होगी;

(ख) यदि हां, तो नई प्रणाली का स्वरूप क्या है; और

(ग) पुरानी प्रणाली की तुलना में इसके क्या लाभ हैं ?

संचार विभाग में उप-मंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) लाइसेंस एक छोटी पुस्तक के रूप में जारी किया जाता है जो जारी होने वाले वर्ष और पांच बार नवीकरण के लिए काफी होगी। नवीकरण या तो प्रतिवर्ष कराया जा सकता है या एक ही बार में पांच वर्ष तक के लिए कराया जा सकता है।

(ii) एक बार में तीन वर्ष तक के लिए निजी लाइसेंसों का नवीकरण करानें पर लाइसेंस शुल्क में 3 रुपये की और पांच वर्ष तक के लिए नवीकरण कराने पर 9 रुपये की रियायत दी जाती है।

(iii) हर एक सेट का अपना लाइसेंस अलग से होगा। इससे दूसरे और उससे आगे के सेटों के रियायती शुल्क-दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(iv) लाइसेंस शुल्क और अधिभार विशेष रेडियो शुल्क टिकटों में अदा किया जाएगा जो लाइसेंस पुस्तक में चिपका दिये जाएंगे।

(v) लाइसेंस पुस्तक का नवीकरण उसी डाकघर में किया जाएगा जहां उसकी रजिस्ट्री हुई हो। पुराने डाकघर या जिस डाकघर में स्थानान्तरण कराना हो, वहां आवेदन पत्र देने पर रजिस्ट्री का स्थानान्तरण नि:शुल्क किया जाएगा। इसके द्वारा बहुत से बेकार के काम और लाइसेंस धारकों को होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।

(vi) वार्षिक 7.50 रुपये के एक ही शुल्क के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के रियायती लाइसेंसों को रखा गया है।

(vii) एक वर्ष से कम समय की अवधि के लिए नये लाइसेंस पर दिया जाने वाला शुल्क मौजूदा मासिक दरों की बजाय तिमाही दरों के आधार पर लिया जाएगा।

(ग) पुस्तक रूप में दिये गये लाइसेंस को उठाना-धरना और संभालना आसान है। डाकघर की खिड़की पर नवीकरण कराने में लगने वाला समय कम हो जाएगा चूंकि नवीकरण उसी पुस्तक में दर्ज कर दिया जाएगा। प्रति वर्ष आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उठाऊ सेटों को बाहर ले जाने के समय उन के साथ लाइसेंस भी ले जाया सकता है। एक बार में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए नवीकरण कराने की सुविधा के साथ ही शुल्क में भी रियायत दी गई है। लाइसेंस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरण होने और एक डाकघर से दूसरे डाकघर को स्थानान्तरण होने पर उसे स्वयं लाइसेंस में ही नोट किया जा सकता है। विशेष टिकटों के रूप में राजस्व की वसूली करने से डाकघर की लेखा क्रियाविधि भी सरल हो जाएगी, और लेखा-परीक्षा का लगभग सारा काम खत्म हो जाएगा। नई योजना के कारण खर्चे में वार्षिक बचत होगी जो अगले छः वर्ष में 35 लाख रुपये से अधिक होगी। साथ ही लाइसेंसों का नवीकरण न कराने पर उनका नवीकरण कराने के लिए की जाने वाली कार्रवाई आसान हो जाएगी।

हैदराबाद में वायुसेना अकादमी

616. **श्री काजरोलकर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दे० द० पुरी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में वायु सेना अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) प्रारम्भ में कितने कैडेट प्रशिक्षण के लिये भर्ती किये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अनावर्ती व्यय का अनुमान 12 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) अकादमी का उद्देश्य है, वर्तमान वायुसेना उड़ान कालिज, और वायुसेना की कुछ अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं का स्थान लेना, और विदेशी छात्रों समेत अधिकाधिक 350 छात्रों के लिए पर्याप्त होगी।

बीमाकृत पार्सलों का गुम हो जाना

617. **श्री कृष्णपाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 अक्तूबर, 1965 को या उसके आसपास की तिथि को आगरा में एक मजदूर के पास 10,000 रुपए की लागत के बीमाकृत पार्सलों का एक बंडल पकड़ा गया था; और

(ख) क्या कोई जांच की गई है; और

(ग) चोरी अथवा असावधानी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) वास्तव में एक डाक का थैला, जिसमें 459 रुपये के मूल्य की बीमा वस्तुएं रखी थीं, और जो डाक मोटर के ठेकेदार के ड्राइवर के पास से गुम हो गया था, 21 अक्तूबर, 1965 को एक फल के कमीशन एजेंट को मिला था। उसे डाकघर को ज्यों का त्यों लौटा दिया गया।

(ख) जी हां।

(ग) मेल मोटर के ठेकेदार से ड्राइवर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

विदेशों में फिल्म डिवीजन के कार्यालय

618. श्री दी० चं० शर्मा : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**

श्री यशपाल सिंह : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, ब्रिटेन, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में समाचार चित्रों (न्यूजरील) और वृत्त चित्रों के वितरण के लिये फिल्म डिवीजन का कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय समाचार चित्र और वृत्तचित्रों के वितरण के लिये कुछेक विदेशों में फ़िल्म विभाग के कार्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

सीमा क्षेत्रों में प्रचार

619. श्री प्र० चं० बरुआ :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **सूचना** और **प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमत क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी केन्द्रीय मागदर्शन तथा समन्वय समिति की हाल ही में कलकत्ता में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य मुख्य मत व्यक्त किये गये तथा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफ़ारिशें और विचार ये थे :—

(1) समिति ने सीमा-प्रचार-योजना पर काम करने में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं पर विशेष विचार किया और यह राय दी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार को देश रक्षा का अंग समझा जाए और कारगर ढंग से प्रचार करने के लिए, जो साधन आवश्यक हों, उनको शीघ्र जुटाया जाए।

(2) जो विशेष सिफ़ारिशें की गई थी वे ये थीं :—

(i) पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर, नागालैंड, नेफ़ा, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम, पश्चिमी बंगाल और बिहार के भागों में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जाएं।

(ii) उक्त क्षत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में सामुदायिक श्रवण सेट लगाए जाएं तथा उनकी उचित देख रेख की व्यवस्था की जाए।

(iii) क्षेत्रीय प्रचार के लिए गाड़ियां और सामान मुहैया करने को ऊंचा प्राथमिकता दी जाए।

(iv) जैनरेटर, टेप-रिकार्डर आदि सामान मंगाने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जाए।

(v) प्रचार कर्मचारियों और टेक्नीकी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और मार्गदर्शन का तुरन्त प्रबन्ध किया जाए।

(vi) फ़िल्म विभाग के बनाए हुए वृत्त-चित्र अधिक संख्या में दिय जाएं।

(vii) सीमा-क्षेत्रों के अधिकाधिक लोगों को दिखाने के लिए स्थानीय वातावरण के चित्र खास खास प्रादेशिक भाषाओं और बोलियों में बनाए जाएं।

(viii) संकटकालीन साहित्य और पोस्टर और अधिक तादाद में दिए जाएं।

(ix) सीमा क्षेत्रों में क्षेत्रीय यूनिटों के द्वारा चलती फ़िरती प्रदर्शनियां करने के लिए, प्रदर्शनीय तथा दूसरी सामग्री तैयार करके दी जाए।

(x) दूर के सीमावर्ती राज्यों से तेजी से संदेश लेने देने के लिए टेलीप्रिंटर लगाए जाएं।

(3) केन्द्रीय समिति ने एक उप समिति बना दी जो समय समय पर इसकी जांच करेगी और बताएगी कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों को कितना सामान चाहिए।

(4) पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों ने प्रचार कार्य के लिए अपनी जो जरुरतें बताई उन पर समिति ने विचार किया, और राज्य तथा केन्द्र की सम्बन्धित एजन्सियों से अनुरोध किया कि वे इन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें।

(5) समिति ने वर्तमान आपत्काल में किस प्रकार प्रचार किया जाए और किन बातों पर जोर दिया जाए, इस पर विचार किया और इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर निर्देश दिए।

(ग) सरकार मोटे तौर पर समिति की सिफ़ारिशों के अनुकूल है। इनकी तपसील पर विचार हो रहा है।

राज्यों के श्रम मन्त्रियों का सम्मेलन

620. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 अक्तूबर, 1965 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में आपातकाल के कारण औद्योगिक श्रमिकों को हुई कठिनाइयों के सम्बन्ध में विचार किया गया; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री डी० संजीवैया): (क) जी हां। इस मामले पर 29 अक्तूबर (न कि 28 अक्तूबर), 1965 के हुई राज्य के श्रम मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में विचार किया गया।

(ख) इन तथा अन्य विचार-विमर्शों के परिणाम-स्वरूप 30-31 अक्तूबर 1965 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा इस विषय पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5148/65।**]

संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

621. **श्री राम सहाय पाण्डे :**

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना को क्रियान्विति का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के निर्देश-पद क्या होंगे और उसके सदस्य कौन लोग होंगे; और

(ग) क्या समिति नियुक्त की जा चुकी है और क्या उसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बकाया राशि की अदायगी

622. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं के तीनों कक्षों, अर्थात् वायु सेना, नौ सेना तथा स्थल सेना के मुख्यालयों (पृथक पृथक्) के कुल कितने कर्मचारियों को, फिर से नौकरी पर लगाने के बाद न्यायालयों के निर्णय की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष पहले तक का बकाया वेतन नहीं दिया गया है; और

(ख) इसके क्या कारण है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : ऐसा कोई मामला नहीं है, कि किसी व्यक्ति को बहाल किया गया हो, और उसे न्यायालय के निर्णय तिथि से तीन वर्ष पूर्व का बकाया वेतन अदा न कर दिया गया हो। तदपि, चार मामलों में पूर्व का वेतन दिया जाना बाकी है, जिनमें कि, बरी होने की तिथिएं नवम्बर 1964 से जून 1965 के अन्दर अन्दर है। तीन व्यक्ति वायु सेना मुख्यालय में काम कर रहे हैं, और एक नौसेना मुख्यालय में।

न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप सेवा में बहाली के पश्चात् डयूटि से अनुपस्थिति अथवा सेवा से निलम्बन की अवधि के लिए पूरे वेतन और भत्तों की अदायगी के विषय में हर मामले का, उनके गुणों के अनुरूप निरीक्षण किया जाता है। शेष मामले निरीक्षणाधीन है, और उनके संबंध में शीघ्र निर्णय लेने तथा, अगर कोई हो तो पूर्व के वेतन और भत्तों की अदायगी करने की ओर यत्न किए जा रहे हैं।

बिना लाइसेंस रेडियो सेट

623. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 के अन्त तक डाक व तार विभाग ने (राज्यवार) बिना लाइसेंस कितने रेडियो सेटों का पता लगाया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 1965 के दौरान सितम्बर के अन्त तक डाक तार विभाग द्वारा पकड़े गए बिना लाइसेंस रेडियो सेटों की संख्या नीचे दी गई है :—

आन्ध्र	2,583
आसाम	2,358
बिहार	5,000
दिल्ली	5,201
गुजरात	11,022
केरल	2,320
मद्रास	10,305
मध्य प्रदेश	1,629
महाराष्ट्र	4,694
मैसूर	1,418
उड़ीसा	699
पंजाब (जम्मू तथा काश्मीर सहित)	5,858
राजस्थान	8,246
उत्तर प्रदेश	9,180
पश्चिमी बंगाल	2,257
कुल	72,770

(ख) पता लगाये गये मामलों में जब तक कि बकाया अधिभार अदा करके लाइसेंस नहीं ले लिये जाते विधिवत कार्रवाई की जाती है। 1965 के दौरान सितम्बर के अन्त तक पता लगाये गए जिन मामलों का निपटान किया जा चुका था उनकी संख्या 62,979 थी। काफी समय और काफी पहले नोटिस दिये जाने के बाद जिन मामलों का निपटान नहीं होता उनमें अदालती कार्रवाई की जाती है।

उड़ीसा में तकनीकी लोगों की बेरोजगारी

624. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में 31 अक्तूबर, 1965 को कितने तकनीकी व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अक्तूबर, 1965 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया) : तकनीकी व्यक्तियों से सम्बन्धित आंकड़े हर छमाही के बाद इकट्ठा किए जाते हैं। जनवरी-जून, 1965 से सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(क) 30 जून, 1965 को 4,923 तकनीकी व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज थे।

(ख) जनवरी से जून, 1965 के बीच 1,452 तकनीकी व्यक्तियों को काम दिलाने में सहायता की गई।

उड़ीसा में बेरोजगार स्त्रियां

625. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में 31 अक्तूबर, 1965 को कितनी स्त्रियां (स्नातक और गैर-स्नातक दोनों) के नाम उम्मीदवारों के रूप में दर्ज थे ; और

(ख) उनमें से कितनी स्त्रियों को अक्तूबर, 1965 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख) : जानकारी हर छमाही बाद इकट्ठा की जाती है। जनवरी–जून, 1965 से सम्बन्धित आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है :—

श्रेणी	चालू रजिस्टरों में दर्ज उम्मीदवारों की संख्या जैसी 30-6-65 को थी	जनवरी–जून, 1965 के बीच रोजगार पाने वालों की संख्या
स्नातक (जिनमें स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाली उम्मीदवार भी शामिल हैं)	25	10
मैट्रिक और हायर सेकण्डरी पास (जिनमें इन्टरमीडिएट्स भी शामिल हैं)	194	59
मैट्रिक से कम पढ़ी-लिखी (जिनमें अनपढ़ भी शामिल हैं)	1,744	666
	1,963	735

आकाशवाणी के कटक केन्द्र में कलाकार

626. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 1965 को आकाशवाणी के कटक (उड़ीसा) केन्द्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने नियमित कलाकार (स्टाफ़ आर्टिस्ट) तथा अन्य कर्मचारी थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित जातियां
स्टाफ़ आर्टिस्ट . . .	..	..
नियमित कर्मचारी	23	1
कुल	23	1

केन्द्र की कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है :--

स्टाफ आर्टिस्ट .	53
नियमित कर्मचारी . . .	110

पाकिस्तान की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों के प्रति भारत के विरोध पत्र

627. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22 अक्तूबर, 1965 को, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को दिये गये दो अलग-अलग टिप्पणों (नोटों) में क्रमश: पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान तथा त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान सीमाओं पर पाकिस्तान की आक्रामक कार्यवाहियों तथा उत्तेजनात्मक गोलाबारी के प्रति विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो विरोध-पत्रों में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) पाकिस्तान सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इन विरोध-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज़ पर रख दी गई हैं।

(ग) पाकिस्तान के हाई कमीशन ने अभी तक इन विरोध-पत्रों की पावती नहीं दी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5149/65।]**

पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा बेलोनिया नगर में गोलीबारी

628. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1965 को पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने त्रिपुरा के बेलोनिया नगर में गोलीबारी आरम्भ की थी;

(ख) उन्होंने कितनी गोली चलाई; और

(ग) क्या कोई व्यक्ति हताहत हुए ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(1) राजाबागान गोदी बाड़ा (डाकयार्ड) कलकत्ता में बड़ी संख्या में मजदूरों की जबरी छुट्टी

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"राजाबागान गोदी बाडा (डाकयार्ड), कलकत्ता में बड़ी संख्या में मजदूरों की जबरी छुट्टी और रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी की कुछ संस्थापनों को बन्द करने का सरकार का निश्चय।"

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : नदी भाप नौचालन कम्पनी एक अर्न्तदेशी जल परिवहन व्यवसाय घ है जो पूर्वी पाकिस्तान होकर पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच माल को ले जाता और परिवहन करता है और उसका राजाबागान डाकयार्ड उक्त कम्पनी के पोतों की मुख्यत: मरम्मत करने का केन्द्र है। कई वर्षों से कम्पनी की वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी और यदि भारत सरकार ने फरवरी, 1965 में कम्पनी में नियंत्रक चि लेने का निश्चय न किया होता तो उसका परिसमापन हो गया होता। कम्पनी का नियंत्रण ले लेने के बाद से निदेशकों के नये मण्डल ने कम्पनी की आमदनी बढ़ाने और खर्च कम करने के लिये उसका पुनर्संगठन कर सब प्रयास किये। दुर्भाग्यवश, 6 सितंबर, 1965 से भारत और पाकिस्तान के बीच युध्द छिड़ जाने से आसाम और कलकत्ता के बीच की सेवाओं को समाप्त करना पड़ा और इससे कम्पनी का काम्काज बिल्कुल प्प हो गया और कम्पनी की आमदनी को भारी हानि पहुंची। नदी कर्मीदल के अधिकांश लोग पाकिस्तानी राष्ट्रिक होने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई और आसाम की नदियों में चलने वाले पोतों पर काम करने के लिये भारतीय कर्मीदल रखना पड़ा। आसाम में छोड़े हुये यानों का पूरी सीमा तक उपयोग करने के लिये और बंगाल की नदियों में पोतों को काम में लाने के लिये कम्पनी पूरा प्रयास कर रही है।

[श्री राज बहादूर)]

राजाबागान डाकयार्ड

(2) राजाबागान डाकयार्ड में मरम्मत और देखरेख के काम में पर्याप्त कमी के कारण 1-11-9165 से डाकयार्ड के कर्मचारियों को प्रमाणित स्थायी आदेशों और 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जबरन छुट्टी दी गई। 1-11-1965 को स्थिति इस प्रकार थी :—

1. कर्मचारियों की सम्पूर्ण संख्या .		2,928
2. जबरन छुट्टी दिये गये कर्मचारियों की संपूर्ण संख्या	1,822	
3. आजकल काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या	918	
4. बगैर वेतन के छुट्टी दिये हुये अप्रेंटिस .	188	
	2,928	2,928

इस बीच सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर और प्राइवेट पार्टियों से काम के लिये आर्डर प्राप्त करने के हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं और नये कामों के लिये आर्डर प्राप्त हो जाने पर जिन आदमियों को जबरन छुट्टी दे दी गई है उन्हें धीरे धीरे वापस बुला लिया जायेगा। जबरन छुट्टी दिये जाने से पूर्व लगबग 400 आदमी जो अस्थायी थे नोकरी से हटा दिये गये थे और 134 स्थायी आदमियों को वार्धक्य निवर्त्तन कर दिया गया था। अभी तक डाकयार्ड में किसी स्थायी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

(3) प्रबन्ध ने दो घाटों को बन्द करने का निश्चय किया है, अर्थात् संख्या 4 कलकत्ता जेटी और आरमीनियनघाट किन्तु इसका प्रभाव कर्मचारियों पर तुरंत नहीं पड़ेगा क्योंकि फिलहाल कर्मचारी दूसरे घाटों पर लगा लिये जायेंगे। भारतीय क्षेत्र में कलकत्ता में स्थित कम्पनी के पोतों को लाभदायी काम में लगाने के लिये सब तरह के प्रयास किये जा रहे है। जैसे जैसे काम बढ़ता जायेगा छुट्टी दिये गये कर्मचारी वापस ले लिये जायेंगे।

आसाम और कछार

(4) आसाम में नोआमाटी और जोगीघोपा के बीच में कम्पनी एक छोटी आन्तरिक सेवा चला रही है। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इसकी क्षमता का और विकास किया जा रहा है किन्तु कम्पनी की सामान्य साधी सेवा बन्द हो जाने के कारण आसाम में सभी एजिन्सियों में फालतू आदमी हैं। कछार सेक्शन तो कतई बेकार है क्योंकि कछार से या वहां के लिये कोई यातायात नहीं है। प्रबन्ध विभिन्न एजिन्सियों में छुट्टी दिये जाने वाले कर्मचारियों के वर्गों की विस्तृत जांच कर रहा है। अभी तक आसाम सेक्शन में किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यदि वैकल्पिक मार्ग नहीं मिले और कलकत्ता के अन्य डाकयार्डों का इस्तेमाल न किया गया तो केवल पश्चिम बंगाल में ही आर० एस० एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लगभग 5,000 भारतीय कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे और क्या आर० एस० ए ण्ड कम्पनी कर्मचारी संघ की समन्वय समिति ने 26 अक्तूबर, 1965 को मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें 9 या 10 सुझाव दिये गये हैं जिनसे छंटनी को रोका जा सकता है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है और क्या उनको यह आश्वासन दिया गया था कि किसी की भी छंटनी नहीं की जायगी और उनको अन्य समवर्ती रोजगार दिया जायगा ?

श्री राज बहादुर : कर्मचारी संघ ने कुछ अभ्यावेदन दिये हैं और कतिपय सुझाव दिये हैं। मैंने भी उनसे बात की है। उनके लिये अन्य काम के बारे में विभिन्न सुझाव दिये गये हैं और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हमें कुछ श्रमिकों को जबरन छुट्टी देनी पड़ेगी और जैसे ही हमें नया काम मिल जायगा हम निश्चय ही उनको वापस काम पर लगाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या कर्मचारियों को इस बारे में कोई आश्वासन दिया गया है कि यदि उनको काम न होने के कारण अस्थायी तौर पर जबरन छुट्टी दी जाय, उनकी छंटनी नहीं की जायगी और किसी भी कर्मचारी की, जिसने छः महीने से अधिक काम किया हो, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, छंटनी नहीं की जायगी ? मैं इस बारे में आश्वासन चाहता हूं।

श्री राज बहादुर : अभी तक किसी भी स्थायी कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी है। जैसा मैंने बताया है जैसे ही हमें काम मिलेगा हम सभी जबरी छुट्टी दिये गये कर्मचारियों को वापस बुला लेंगे और जहां तक हो सकेगा हम छंटनी नहीं करेंगे।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्वी) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संघ ने वैकल्पिक स्टीमर मार्ग के लिये 9 या 10 सुझाव दिये हैं और उन्होंने इस बारे में मंत्री महोदय से बात भी की है और मंत्री महोदय ने उनको आश्वासन दिलाया है कि वह इन सुझावों पर गौर करेंगे और उन्हें यथा संभव क्रियान्वित कराने की कोशिश करेंगे, क्या मंत्री महोदय ने इन सुझावों पर गौर किया है ? इस पर मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री राज बहादुर : हम इन सुझावों की सराहना करते हैं। प्रबंधक स्वयं राजबागान डाकयार्ड के श्रमिकों के लिये वैकल्पिक रोजगार ढूंढने और स्टीमर कम्पनियों के उन कर्मचारियों को भारतीय जलयानों में अधिक से अधिक लगाने के लिये प्रयत्न कर रहा है। इन दोनों बातों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि हम इसमें जो भी हो सकेगा, करेंगे। जहां से भी काम मिल सकता है, जैसे प्रतिरक्षा, पत्तन, गैर-सरकारी अभिकरणों से बातचीत की जा रही है। मुझे आशा है कि हमें राजबागान के श्रमिकों के लिये कुछ काम मिल जायगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक अन्य ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है जो सिक्किम सीमा पर डोंगचुई ला क्षेत्र में हमारी सेना पर आक्रमण के बारे में है। मैंने इसको मंजूर कर लिया था और शाम को या अगले दिन इसे लेने के लिये रखा था क्योंकि एक पहले ही लिया जा चुका है। जब मैं यहां आया तो पता चला कि प्रतिरक्षा मंत्री वक्तव्य देने को तैयार हैं और इसलिये मैं इसकी अनुमति देता हूं। श्री राम सेवक यादव।

(2) सिक्किम सीमा के डोंग चुइ ला स्थान पर चीनी आक्रमण

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Sir, I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Chinese attack on our posts in the Dong Chui La area on Sikkim border on the 13th November, 1965."

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 13 नवम्बर, 1965 को 7 म० पू० लगभग 100 चीनी सैनिकों की एक कम्पनी सिक्कम-तिब्बत सीमा पर डोंगचुई ला क्षेत्र में हमारी दो चौकियों के निकट आ गई और उसने बिना किसी उत्तेजना के गम्भीर प्रकार की गोला-बारी शुरू कर दी। गोलाबारी

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

5 म० प० तक जारी रही। हमारी सेना ने गोलाबारी का उत्तर दिया। इस बात की पुष्टि हो गई है कि चीनी हमारी सीमा के अन्दर लगभग 50 गज तक आ गये थे। क्योंकि उस स्थान पर एक भारतीय सैनिक, जो की गोलाबारी में मारा गया था, के सब के साथ एक चीनी सैनिक का शव पड़ा मिला था। हमारे सैनिकों ने भारतीय सैनिक का शव प्राप्त करने का प्रयत्न किया परन्तु चीनियों ने सारा दिन गोलाबारी जारी रखी जिसके कारण ऐसा नहीं किया जा सका। सायंकाल को जब हमारे सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें मालूम हुआ कि चीनी अंधेरे में दुसरे चीनी सैनिक का शव तथा भारतीय सैनिक का शव भी घसीट कर ले गये थे।

यद्यपि हमारी चौकियों पर नियुक्त सैनिकों की तुलना में चीनियों की संख्या कई गुणा थी तथापि भारतीय मोर्चे पर अड़े रहे और अपने हताहत व्यक्तियों की तुलना में चीनियों को अधिक संख्या में हताहत किया। परन्तु यह बहुत ही खेद की बात है कि चीनी बिना किसी उत्तेजना के गोलाबारी जारी रखें और हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करते रहें। इन सभी बातो से अनावश्यक तनाव पैदा होता है। ऐसा दिखाई देता है कि सितम्बर में सीमा के निकट सेनायें लाने के समय से ही चीनियों से दृढ़ मोर्चाबन्दी कर रखी है। उन्होंने सिक्कम में सात बार घुसपैठ किया है। डांगचूई ला में यह तीसरी बार घुस पैठ हुई है। इससे पहले दो बार 20 सितम्बर और 26 सितम्बर को घुसपैठ हो चुकी हैं। पिछली बार चीनियों की बड़ी संख्या ने घुसपैठ की और सीमा के काफी अन्दर की ओर से तीन भारतीय सिपाहियों की एक छोटी सी गश्ती टुकड़ी का अपहरण कर लिया। चीनियों ने अभी इन अपहृत व्यक्तियों को नहीं लौटाया है जिनकी वापसी के लिये हमने मांग की है।

भारत सरकार ने सिक्कम सीमा के पार चीनी सेनाओं द्वारा बिना उत्तेजना के गोलाबारी की घटनाओं तथा जानबूझ कर की जा रही आक्रमण की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चीन सरकार से विरोध प्रकट किया है।

Shri Ram Sewak Yadav : The Hon. Minister has said that prior to this the Chinese soldiers had kidnapped three Indian soldiers and the Government have lodged a protest. It is not having any effect on them. I want to know as to what action is proposed to be taken and whether they are going to change their policy.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी नीति वही रहेगी, जो पहले थी, अर्थात् अपनी सीमाओं की दृढता से रक्षा करना।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : How many Chinese soldiers, dead or alive, have been taken into their custody by the Indian soldiers?

Shri Y. B. Chavan : None.

Shri Kishen Pattnayak ( ) : Even now some Indian land is in Chinese possession and after that they are indulging in such activities. I want to know whether this is a result of our policy that after their intrusion we lodge a protest and do not adopt the policy of taking back our territory by attacking on them in Tibet.....

Mr. Speaker : This question does not arise.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, सीमा पर हमारी निरीक्षण चौकियां हैं और हमारा इरादा वहां बने रहने और दृढ़ता से अपनी रक्षा करने का है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : When Pakistan attacked in Kutch, the Hon. Prime Minister had said that there is mud everywhere. Then they were shown the way to Lahore and Sialkot. Whether in this case they will see that there is a road which goes from Chumbi Valley to Lhasa. Do they propose to attack there?

अध्यक्ष महोदय : दोनों माननीय सदस्यों का प्रश्न है कि हम इस प्रकार रक्षा ही करते रहेंगे या कभी प्रत्याक्रमण भी करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सामान्यतः हमारी नीति अपनी एकता और अपने देश के प्रदेश की रक्षा करने की है लेकिन आक्रमण की कार्रवाई पर भी ध्यान रखा गया है । मैं नहीं कह सकता कि वह कार्यवाही क्या है और कैसे की जाएगी ।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir,.....

Mr. Speaker : There is no point of order now.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : As the Government is aware, India celebrates the birthday anniversary of her Prime Minister on the 13-14 November—and on this 13-14 November China always attacks on us. They also returned the dead bodies of our Jawans on November 13. What action Government is proposing to take for this national insult?

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि मैं सरकार का इरादा स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री पें० वैंकटासुब्बय्या (अडोनी) : क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि क्या चीनियों द्वारा ये आक्रमण केवल अपना मुँह और इज्जत बचाने के लिये किये जाते हैं अथवा इस बारे में वे गंभीर है और वे फिर भारत को अपने आक्रमण का शिकार बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह यह प्रश्न चीनियों से नहीं पूछना चाहेंगे ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : भारतीय प्रदेश में बारबार घुस जाने और फिर वापस चले जाने को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के गुप्त वार्ता विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी है कि क्या चीनी सेना अब हमारे ऊपर हमला करने के लिये किसी स्थान विशेष पर जमा हो रही हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : दूसरी ओर चीनी सैनिकों की गतिविधियों के बारे में हमें गुप्त सूत्रों से कुछ जानकारी है । किन्तु मैं इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकता ।

Shri Bade (Khargone) : Recently on 23rd and 26th September, the Chinese attacked Dongechula post and kidnapped our three Jawans and they have now attacked it again. In view of this, may I know whether our position has been strengthened at this post after their attack on this post or it continues as before?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कभी कभी हम अधिक सैनिक भेज देते हैं । यह बात जलवायु सम्बन्धी स्थिति तथा अन्य पहलुओं पर निर्भर करती है ।

श्री हेम बरुआ : चूकि अतिक्रमण, चाहे वह सैनिक हो अथवा अन्यथा, के पश्चात् हमेशा हमला होता है, इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार ने इस स्थिति का भलीभांति अनुमान लगा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बता सकती है कि वह चीनी चुनौती का प्रभावशाली ढंग से सामना करने में सफल होगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं 'हां' कहूंगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ऐसा लगता है कि इस मुठभेड में हमने कुछ चीनी सैनिकों का वध किया है । हम उनके शवों को एक बार भी अपने साथ क्यों नहीं ला सके ? लाशें हमेशा ही चीनियों के हाथ क्यों पड़ जाती हैं ?

श्री हेम बरुआ : खेद है कि इस प्रकार की घटना हो गई है ।

श्री नाथ पाई : चीन के मित्र पाकिस्तान के साथ हमारी सितम्बर में हुई मुठभेड में हमारे द्वारा पहल लिये जाने के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने पहले हमला करने की प्रवृत्ति का इस समय अस्थायी-रूप से त्याग कर दिया है । उपरोक्त प्राप्त अनुभव को दृष्टि में रखते हुए क्या मैं उन हिदायतों के बारे में जान सकता हूं जो सिक्किम तथा समूचे हिमालय सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे सिपाहियों को दिये गये हैं ? जब आक्रमण होता है तो उन्हें केवल जवाबी कार्यवाही ही नहीं अपितु आक्रमणकारी का पूरी बहादुरी से पीछा भी करना चाहिए ? वे सीमान्त क्षेत्र में पहुचने के पश्चात् क्यों रुक जाते हैं ? वे लाहौर तथा स्यालकोट की तरह वहां भी आगे क्यों नहीं बढ़ते ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सेना को दी गई हिदायतों के सम्बन्ध में मैं नहीं बताना चाहता हूं ।

श्री नाथ पाई : जहां तक सामरिक नीति के बारे में प्रकाश न डालने का सम्बन्ध है, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ । किन्तु हमसे सदैव यही कहा जाता है कि शत्रु हमारे राज्य-क्षेत्र में घुस आया, इतने सैनिक मारे गये तथा हमारे द्वारा जबाबी कार्यवाही किये जाने पर दुश्मन भाग खड़ा हुआ । मैं नहीं समझता कि मेरे प्रश्न का ऐसा स्वरुप है जिसके उत्तर के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्री को गोपनीयता बरतनी आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या चीन ने याक तथा भेड़ सम्बन्धी 'अल्टिमेटम' के पश्चात् इस सीमा पर सैनिक निर्माण-कार्य किये हैं और वहां अपनी सेनाएं भी बढ़ा दी हैं? क्या सरकार को कोई ऐसी गुप्त सूचना, भारतीय अथवा विदेशी, प्राप्त हुई है कि चीन तथा पाकिस्तान एक संयुक्त आक्रमण की योजना तैयार कर रहे हैं, यदि हां, तो क्या सरकार उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं गुप्त-सूचना के बारे में नहीं बता सकता, किन्तु ऐसा अनुमान लगाना गलत नहीं है । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether the Defence Minister is aware of the fact through his intelligence machinery that the Chinese troops are attacking not only Sikkim Side but they also want to capture Laddak by advancing through Pakistani territory on the pretex of their help?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें उनके इरादे की नहीं अपितु उनकी कार्य-क्षमता की ओर ध्यान देना है । इस सम्बन्ध में नित्य स्थिति का वास्तविक रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इस अतिक्रमण के पश्चात् जो गोलाबारी हुई, वह भारतीय राज्य-क्षेत्र में हुई है अथवा चीनी राज्यक्षेत्र में; यदि भारतीय राज्य-क्षेत्र में हुई है तो भारतीय सिपाही शवों को क्यों नही ला सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : चिनी सिपाही भारतीय भूमि में मारे गये, किन्तु जैसा कि विवरण में बताया गया है, उनके शवों पर कब्जा नहीं किया जा सका।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : May I know whether it is a fact that at the time of its agression on India, Pakistan was under the impression that her ally China would help them but it is altogether a different matter whether China betrayed Pakistan or acted wisely at that time. In view of the current hostile activities of China on the one hand and that of Pakistan on the other hand, may I know whether the Defence Minister will assure the House that whether it is China or Pakistan or both, we are fully prepared to meet the challenge?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि सभा को मैंने यह आश्वासन पहले भी दिया है।

Shri Rameshwara Nand : Sir, I would like to say one thing.....

Mr. Speaker : I cannct allow you at this moment.

Shri Rameshwara Nand : It is futile to say that I make allegations against you. But those who occupy front benches and ask questions in English are given an appoitunity even if their names do not appear in the question list and we the back benchers who put questions in Hindi are not allowed even to raise supplementaries.

Shri H. V. Kamath : The word "allegation" is not proper.

Mr. Speaker : The words used by Swamiji are very offending but because of my respect for him I do not take them to hot and thus do not get annoyed and forget them.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय औद्योगिक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमन् मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी के ओर से औद्योगिक वित्त अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड के 30 जून, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और निगम की आस्तियां तथा दायित्व और लाभहानि लेखा दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5140/65।]**

व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) अधिनियम तथा कोयला खान (दूसरा संशोधन) विनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : श्रीमन् मैं श्री संजीवय्या की ओर से व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) अधिनियम 1963 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) योजना, 1965 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3383 में प्रकाशित हुई थी।

[श्री र० कि० मालवीय]

(दो) व्यक्तिगत चोट (प्रतिकर बीमा) नियम, 1965 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3384 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5141/65।**]

(तीन) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत कोयला खान (दूसरा संशोधन) विनियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1580 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5142/65।**]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल) 1965-66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA) 1965-66

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : श्रीमन मैं 1965-66 के लिए केरल राज्य सम्बन्धी अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : श्रीमन, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 73 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री राने (बुलढाना) : श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 41 वें प्रतिवेदन से, जो 12 नवम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 41 वें प्रतिवेदन से, जो 12 नवम्बर, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/ *The motion was adopted.*

भारतीय राजकीय भेद (संशोधन) विधेयक

INDIAN OFFICIAL SECRETS (AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्रीमन् मैं श्री नन्दा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय राजकीय भेद अधिनियम, 1923 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय राजकीय भेद अधिनियम 1923 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक की पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री ल० ना० मिश्र : श्रीमन् मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : INTERNATIONAL SITUATION

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाए।"

हमारी स्वाधीनता के 18 वर्षों के दौरान जितने संकट हम पर आये हैं उनमें से सबसे गंभीर संकट से हम हाल में निकले है। पाकिस्तान ने हम पर अकारण हमला किया। चीनी-गण-राज्य ने पाकिस्तान से सांठगांठ करके हमें एल्टिमेटम दिया और जिस समय हमारी सेनाएं पाकिस्तानी हमले को पछाड़ने में युद्धरत थीं,—उस समय वह देश पर हमला करने के लिये तैयार था।

यह हमारे लिये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा समूचा राष्ट्र—सशस्त्र सेनाएं, पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, और भारतीय जनता—इस संकट का सामना करने में सफल रहें हैं।

प्रेसीडेन्ट अय्यूब खां के कथनानुसार छम्ब-जोड़ियां क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर आक्रमण का उद्देश्य जम्मू तथा काश्मीर के लोगों की, जो कि भारतीय सेनाओं के विरुद्ध तथाकथित संग्राम में जुटे हुए थे; सहायता करना था।

5 सितम्बर, 1965 को सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प स्वीकार किये जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव द्वारा भेजे गये एक तार के उत्तर में प्रेसीडेन्ट अय्यूब खां ने कहा था कि युद्ध-विराम तभी साभिप्राय हो सकता है जब कि उसके बाद स्वत: लागू होने वाला समझौता किया जाए।

तत्पश्चात्, जब महा सचिव ने भारत तथा पाकिस्तान का दौरा किया और दोनों देशों से युद्ध को तुरन्त बन्द करने तथा युद्ध विराम की अपील की तो प्रेसीडेंट अय्यूब खां ने युद्ध-विराम करने के सम्बन्ध में, पूर्ववर्ती शर्तों के रूप में तीन बातें कहीं (1) भारतीय तथा पाकिस्तानी सेनाओं का पूर्णतया वापस बुलाया जाना; (2) अफ्रीकी एशियाई सेना को वहां लगाना; और (3) निश्चित अवधि के अन्दर जनमत संग्रह कराया जाना।

[श्री स्वर्ण सिंह]

किन्तु पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् द्वारा 20 सितम्बर को पारित किये गये संकल्प को कभी स्वीकार नहीं किया है। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाकिस्तान विवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर सुरक्षा परिषद के संकल्प के प्रति कैसे अपना रवैया बदलता रहा है।

पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने राजनैतिक प्रश्न को उठाने का भरसक प्रयत्न किया था। उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर के आन्तरिक मामलों का भी उल्लेख किया और एक-प्रकरण में तो उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि जम्मू तथा काश्मीर में वास्तविक स्थिति का पता लगाने तथा उसकी जांच करने के लिये वहां एक प्रकार का आयोग भेजा जाए। पाकिस्तानी की ओर से रखे गये इन प्रस्तावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जब पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् का अधिवेशन बुलाने के लिये अभ्यावेदन दिया तो हमने भी अपनी ओर से राष्ट्रसंघ के विशेष सदस्य देशों तथा सुरक्षा परिषद के सभापति के समक्ष अपनी यह स्थिति स्पष्ट की कि जहां तक युद्ध विराम रेखा को सुदृढ बनाने, सशस्त्र सैनिकों को जिसमें घुसपैठिये भी शामिल है, को वापस बुलाने का सम्बन्ध है, भारत योजना बनाने के लिये तैयार है परन्तु इस स्थिति का सामना करने तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो कदम जम्मू तथा काश्मीर की सरकारने उठाये वे पाकिस्तान द्वारा किये गये हमले की प्रतिक्रिया रुप से उठाये गये थे और यह कि सुरक्षा परिषद में इस मामले पर चर्चा में भाग लेने से भारत इन्कार करेगा।

हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम जम्मू तथा काश्मीर में विधि और व्यवस्था के बारे में की जाने वाली आन्तरिक कार्यवाही के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् अथवा संयुक्त राष्ट्र के प्रति उत्तर दायी नहीं है। इस पर सुरक्षा परिषद के सभापति ने हमें यह बताया कि यह हमारे दृष्टिकोण से सहमत हैं और कहा कि इस प्रक्रम पर केवल मुख्य बात युद्ध विराम का स्थायीकरण तथा सेनाओं का वापस बुलाया जाना है।

जब सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा मना करने पर भी पाकिस्तानी विदेश मंत्री अपने भाषण में उन मामलों का वर्णन करते रहे जिन का संबंध जम्मू तथा काश्मीर के आन्तरिक क्षेत्राधिकार और विधि तथा व्यवस्था से था तो हमारे लिये वहां से उठ कर चले जाने के अतिरिक्त और कोई चारा न था। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों ने हमारी इस कार्यवाही की सराहना की है और हमारी अनौपचारिक बातचीत में किसी भी सदस्य ने इसकी आलोचना में एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे लिये न केवल यही एक मार्ग था परन्तु उन परिस्थितियों में यही एकमात्र सम्मानपूर्ण मार्ग था।

इसके पश्चात सुरक्षा परिषद में सामान्य वक्तव्य दिये गये और उन्होंने 5 नवम्बर को एक संकल्प पारित किया जिसका सारांश इस प्रकार था। 20 सितम्बर के संकल्प की पूर्णतया पुष्टि करना और भारत और पाकिस्तान से 20 सितम्बर के संकल्प की पूर्ण कार्यान्विति के लिये सहयोग करने की प्रार्थना करना। हमें कोई आश्चर्य होना चाहिये जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री यह घोषणा करते हैं कि वह 5 नवम्बर के संकल्प से संतुष्ट हैं जबकि पहले उन्होंने हर प्रकार की धमकियां दे डाली थी। वास्तव में हुआ यह कि जब सभी पाकिस्तानी चालें विफल हुईं और सुरक्षा परिषद तथा महा-सभा ने इन चालों में आने से इन्कार कर दिया तो पाकिस्तान के पास यह कहने के अतिरिक्त और कोई चारा न रहा कि वह इस संकल्प से संतुष्ट है। हमने युद्ध क्षेत्र तथा राजनितिक क्षेत्र में दृढ़ता की नीति अपना कर दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। हमें पाकिस्तान जैसे देश के साथ यही नीति अपनानी होगी। अन्य देश भी जो इस समय कई प्रकार से हम पर अनुचित दबाव डाल रहे है, कुछ समय पश्चात अपने आप समझ जायेंगे कि हमारी नीति तथा हमारा दृष्टिकोण ही ठीक है। हमें उनके इस दबाव के कारण अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

हम किसी देश को रुष्ट अथवा उससे लड़ना नहीं चाहते परन्तु हम स्पष्ट रुप से उनको यह बता देना चाहते हैं कि इन मामलों में कुछ लिया दिया नहीं जा सकता और नही कोई समझौता हो सकता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट रुप से समझा जाने लगेगा ।

चीन की पाकिस्तान के साथ सांठगांठ जो हाल के संघर्ष के दौरान चरम सीमा तक पहुंच गई है और यह कब इन दोनों देशों की विदेशी नीतियों का अभिन्न अंग बन गई है और 16 सितम्बर वाली चीनी धमकी इसी सांठगांठ का नंगा रुप है। इसलिये हमें इस दोहरे खतरे को सदा ध्यान में रखना होगा और भविष्य में इसीको ध्यान में रखकर कार्यवाही करनी होगी ।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती (बैरकपुर) : श्रीमान् खेद है कि इस समय स्वयं विदेश मंत्री को छोड़कर मंत्रिमण्डल का कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे ज्ञात हुआ है कि कल नेहरू जयंती समारोह में प्रधान मंत्री के अतिरिक्त मंत्रीमण्डल का एक भी मंत्री वहां उपस्थित नहीं था ।

श्री जी० मा० कृपलानी (अमरोहा) : हमारी सरकार की विदेश नीति के बारे में एक भी शब्द अब तक नहीं कहा गया ।

श्री स्वर्ण सिंह : ऐसा कोई भी निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा ।

रोडेशिया में श्वेत सरकार की एकपक्षीय घोषणा से जो स्थिति उत्पन्न हो गई है और जो चुनौति दी गई है हम उसका उत्तर देने के लिये एशियाई व अफ्रिकी जनता तथा रोडेशिया के 40 लाख लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में उनके साथ है । यद्यपि उपनिवेशवाद अन्तिम श्वास ले रहा है परन्तु लगता है यह उसका अन्तिम प्रयत्न है और शीघ्र ही विश्व इस से मुक्त हो जायेगा क्योंकि समय की लहर इसके विरुद्ध है ।

श्री हरि विष्णु कामत : चीन और अर्ध-उपनिवेशवाद को भी मत भूलिये ।

श्री स्वर्ण सिंह : अफ्रीका तथा एशिया में उपनिवेशवाद की बात कहते हुये मैं अंगोला, मोजम्बीक और अदन का विशेषरुप से वर्णन करना चाहता हूं । इन में से भी अदन में तो स्थिति गम्भीर होती जा रही है। हमें 25 सितम्बर. 1965 को अदन के संविधान को स्थगित करने और ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा सत्ता संभाल लेने के पश्चात हिन्सात्मक दंगों से उत्पन्न हुई स्थिति पर गहरी चिन्ता है। इस संबंध में भारत ने 1960 तथा 1963 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विभिन्न संकल्पो का समर्थन किया था और उस समिति का भी सदस्य था जिसने अदन में ब्रिटिश अड्डे को समाप्त करने और इस क्षेत्र को शीघ्र स्वतंत्रता देने के लिये कहा था। भारत 17 मई 1965 के संकल्प को पेश करने वाले 11 सदस्य देशों में से एक था जिसमें अदन की जनता के जनमत संग्रह के अधिकार को पुनः पुष्ट किया गया था और 5 नवम्बर, 1965 के संकल्प को प्रस्तुत करने वालों में से था । हमारी नीति सदा ही उपनिवेशवादी देशों के विरुद्ध लड़ने और उपनिवेशों तथा वहां जनता को स्वतंत्रता देने के सभी प्रस्तावों का समर्थन करते रहे हैं ।

[श्री स्वर्ण सिंह]

पिछले कुछ मास के हमारे अनुभव के कारण कुछ लोग हमारी वर्तमान नीति की आलोचना करने लगे है परन्तु मैं पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और गुटों से अलग रहने की नीति पर ही चलते रहेंगे। हम सदा ही देश के अन्दर और बाहर बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपनी नीति को परखते रहते है और ऐसा करने के पश्चात ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी नीति में किसी मूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

जब यह चर्चा पूर्ण होगी, उस समय मैं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कुछ और पहलुओं और माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये तर्कों का उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्संबधी नीती पर विचार किया जाये।" अब स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

श्री व० ब० गांधी (बम्बई : मध्य दक्षिण) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मधु लिमये (मुंघेर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I move my substitute motion No. 4.

Shri Prakash Vir Shashtri (Bijnour) : I move substitute motion No. 5.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I move substitute motion No. 6.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बड़े (खारगोन) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रे० सुब्रह्मण्यम (बेलारी) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लिंग रेड्डी (चिकबलपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती रेणुका चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 18 प्रस्तुत करती हूं।

डा० मा० श्री० अणे : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 21 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Bibhuti Mishra : I beg to move my substitute motion No. 22.

श्री मी० ह० मसानी (राजकोट) : श्रीमान् ऐसे अवसर पर हमें सभामें बड़ी ज़िम्मेदारी से अपनी बात कहनी चाहिए क्योंकि जो भी कुछ हम कहेंगे उसका हमारे राष्ट्रीय हितों पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान तथा चीन में हमें प्रतिद्वंद्वियों की उत्सुकता बनी रहगी कि हमारा लोकतंत्रीय समाज इस संकट का किस प्रकार सामना करेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*]

आरंभ में हम सभी को अपनी सशस्त्र सेनाओं की बहादूरी की सराहना करना आवश्यक है क्योंकि 1962 में जो उनकी तथा हमारी प्रतिष्ठा को धक्का पहूंचा था उसका उन्होंने अब निराकरण कर दिया है। हमारे विदेश मंत्री ने भी उनकी सराहना की तथा उन्होंने हमारी जनता की भी सराहना की हमें किस मुस्तैदी तथा एकता से उसने देशकी एकता कटिबद्ध होकर की तथा सामुदायिक तनाव आपस में नहीं आने दिया। मैं उनकी इन बातों से सहमत हूं परन्तु उन्होंने जो अपनी विदेशी नीति की सफलतां का उल्लेख किया है उससे मैं कुछ सहमत नहीं हूं यदि हम हाल की घटनाओं को देखे तो मालूम होता है कि केवल मलेशिया और सिंगापूर के अतिरिक्त और किसी ने हमारे पाकिस्तान के साथ संघर्ष का खुले आम समर्थन नही किया। दिनांक 23 अक्तूबर के हिन्दुस्तान टाइम्स में पी० टी० आई० की रिपोर्ट के अनुसार यह पता लगता है कि 63 राष्ट्र तटस्थ रहे। 19 राष्ट्र भारत के विरोधी थे इन 19 राष्ट्रों में से 11 अरब लीग के सदस्य थे। 3 राष्ट्रोंने केवल उल्लेख किया तथा 25 राष्ट्रों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 110 राष्ट्रों में से एक ने भी हमारा समर्थन नहीं किया। ऐसा किस कारण हुआ है। क्या यह हमारे राजनैतिक दूतावासों के कारण हुआ है अथवा हमारी ग़लत विदेश नीति के कारण हुआ है। मैं समझता हूं कि यह हमारी ग़लत विदेशी नीति के कारण हुआ है।

हमारी विदेश नीति में तीन कमियां हैं। पहली तो यह है कि इसमें दल का नाम नहीं है। यह निश्चय है उदाहरणत: हमने इसी के कारण तिब्बत चीन को सौंप दिया। सभी अरब राज्यों को पाकिस्तान के मुकाबले अपने खिलाफ कर लिया। मैं बता चुका हूं कि केवल इज़रायल के कारण 11 अरब राज्यों ने महा सभा में हमारे विरोध में मत दिया। सरदार स्वर्ण सिंह स्वयं जोर्डन का जिक्र पर आ चुके हैं: अल्जीयर के सम्मेलन में प्रेजीडेंट नस्सर ने भी सम्मेलन के निलम्बन के बारे में चीन का साथ दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि निष्फल नीति के कारण यह सब हुआ।

दूसरी कमी हमारी आत्मप्रशंसा है। हम सर्वदा अपनी विदेश नीति को अपनी आंखों से देखते हैं। यह नहीं सोचते कि दूसरा हमारी विदेश नीति को कैसा समझता है। संसार उसको किस रूप में देखता है।

तीसरी हमारी कमी अपने को दूसरों से अच्छा समझने की है। हम हमेशा अपने को ठीक तथा दूसरों को गलत समझते हैं। दूसरों को हमेशा पाठ पढने की कोशिश करते रहते हैं। इसका सबसे अन्तिम उदाहरण विएतनाम युद्ध है। हमें अपनी इन कमियों की ओर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा हमारी इसी प्रकार उपेक्षा होती रहेगी।

हमें वास्तविकता समझनी चाहिए। वास्तविकता यह है कि हमें सबसे बड़ा खतरा चीन से है तथा थोडासा खतरा उसके मित्र पाकिस्तान से है। मैंने पाकिस्तान स थोडा खतरा इसलिए बताया क्योंकि वह हमको कोई नुकसान नहीं पहूंचा सकता है। नुकसान तो हमें साम्यवादी चीन ही पहुंचा सकता है। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए की जो लोकतंत्रीय सिद्धांतों को मानने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनको चीन के विरोध में इकट्ठा करें

[श्री मी० रु० मसानी]

तथा उनके अगुवा बने जिससे साम्यवादी चीन का मुकाबला किया जा सके। यदि हम चाहते हैं कि हमको एक शक्तिवान देश माना जाये तो हमें उसी प्रकार व्यवहार भी करना चाहिए इसलिए हमें जापान के साथ मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे देशों की सहायता के लिए सदैव खडे रहना चाहिए। परन्तु पिछले 15 वर्षों में हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। बल्कि जब हमने चीन से पंचशील का समझौता किया था उस समय हमने पाकिस्तान अथवा बर्मा से सलाह नहीं की थी। यदि हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का परामर्ष लेने लगते उनको अपने साथ लाने का प्रयत्न करते तो निश्चित रूप से ये सभी देश हमारे साथ होते और हिमालय को हमारी सीमायों के बारे में हमारा समर्थन करते क्योंकि ये सभी देश इन पर्वत श्रृन्खलाहों को दक्षिण पूर्व एशिया की सीमायें समझते है।

प्रसन्नता की बात है कि हाल में ही दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जागृति आ गई है। गत मार्च अथवा अप्रैल में लंका साम्यवादी सरकार बनने में बाल बाल बचा। हालमें ही इण्डोनेशिया अपने को किसी तरह से बचा पाया। विएतनाम में लोकतंत्र की ओर युद्ध का पासा पल्टा। मलेशिया में भी ऐसा ही हुआ। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि हमें चीन के विरुद्ध जापान, आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर त्रिकोण बनना चाहिए। माननीय सदस्य कहेंगे कि आस्ट्रेलिया इसमें कैसे आता है तो उसके लिए मेरा उत्तर है कि आज विएतनाम तथा मलेशिया के जंगलों में आस्ट्रेलिया के जवान मर रहे हैं तो उनका भी उतनाही अधिकार है जितना औरों का। मैं समझता हूं कि यदि हम यह त्रिकोण बना पाये तो निश्चित रुप से चीन को रोक सकेंगे।

हमें तटस्थ तथा अतटस्थ राष्ट्रों के बीच भेदभाव का बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारा नुकसान इस कारण से भी हो रहा है। हमें इण्डोनेशिया को अपना मित्र बनाया क्योंकि वह तटस्थ था परन्तु उसने हमारे साथ जो व्यवहार किया वह स्पष्ट है। हमने जापान तथा मलेशिया को तटस्थ होने के कारण मित्र बनाया। हमने देख लिया कि उन्होंने हमारा कितना साथ निबाहा।

मेरा यह कहना है कि हमें साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश का समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अपने लिए स्वयं खाई खोदते हैं। हमें समझना चाहिए कि साम्यवादी चीन संयुक्तराष्ट्र का सदस्य होने के बाद सुरक्षा परिषद का सदस्य अवश्य बनेगा। और उसका सदस्य बनने के बाद वह पाकिस्तान से मिलकर हमारे विरुद्ध ऐसे प्रस्ताव पास करा सकेगा जो हमारे लिए हानिकारक रहेंगे। हमे हमेशा राष्ट्रवादी चीन का पक्ष लेना चाहिए क्यों कि हमें स्वतंत्रता दिलाने में इसका हाथ है। उसने चर्चिल को नाराज़ किया और हमारा समर्थन किया। हमें वह सभी बातें नहीं भूल जानी चाहिएं और प्रयत्न करना चाहिए जिससे साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य न बने।

यहि स्थिति हमारे तिब्बत के मित्रों के बारे में है। अब हमें अपना रवैया बदलना चाहिए और दलाई लामा को विदेश में तिब्बती सरकार मान लेना चाहिए। रोडेशिया के बारे में हमें ऐसी ही बात कह चुके हैं कि यदि आश्वेत लोग विदेश में कोई सरकार बनाते हैं तो हम उसका समर्थन करेंगे तो तिब्बत के बारे में हम ऐसा करते हुए क्यों डरते हैं।

पाकिस्तान के बारे में हमें दो नीतियां बनानी चाहिए। एक अल्पकालीन तथा दूसरी दीर्घकालीन। अल्पकालीन नीति के अन्तर्गत हमें पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करना चाहिए तथा आक्रमक को पाठ पढ़ाना चाहीए। परन्तु दीर्घकालीन नीति के अन्तर्गत मैत्री बनाने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही दोनों देशों को मित्र बनकर रहना होगा।

कश्मीर के बारे में मेरा विचार है कि हमें उसको छोड़ना नहीं है। वह हमारे देश का अंग है परन्तु फिरभी हमें इस समस्या का हल ढूँढ निकालना है तथा ऐसा हल ढूँढ निकालना है जो सर्व सम्मत हो। इसके साथ साथ कश्मीर की जनता को अपने साथ मिलाना चाहिए जिससे अवैध रूप से प्रवेश करने वालों से वहां की जनता स्वयं निपट सके।

अब मैं अपने अमरिका तथा रुस से भावी संबंधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि चीन तथा पाकिस्तान के हमलों से बचने के लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों देशों की सहायता लें। स्पष्ट है कि पिछले कुछ महीनों में युद्ध विराम भी इन्हीं बड़ी शक्तियों के कारण हुआ है। परन्तु हमें साथही साथ यह भी समझना है कि दोनों की अपनी सीमायें हैं तथा वह उन्हीं सीमाओं के अन्तर्गत अपने काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप साइप्रस को लिजिए। वहां पर तुर्की तथा ग्रीस आपस में लडे। दोनों ही अमरिका के मित्र थे तथा दोनों ही अमरिका के लिए एक समान थे। अमरिका ने किसीका भी साथ नहीं दिया परन्तु साथ ही साथ दोनों में समझौता करा दिया। हमें इन बातों को समझना चाहिए।

हम जानते हैं कि हमें अमरिका से सहायता चाहिए तथा इसके तीन कारण हैं पहला तो यह है कि आज अमरिका ही ऐसी शक्ति है जो चीन को भारत पर आक्रमण करने से रोक सकती है। 1962 में भी अमरीका चीन के विरोध में हमारी सहायता के लिए आया था। दूसरा कारण यह है कि हमें अनाज अमरीका के ही सहयोग से मिल सकता है। और कोई देश इस समेत इस स्थिति में नहीं है कि हमें अनाज दे सके। तीसरा कारण यह है कि भारत को आर्थिक सहायता तथा विदेशी पुँजी चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो सके। यदि हम विकास सहायता देखें तो मालूम होता है कि हमको 59 प्रतिशत सहायता अमरीका से तथा 51.2 प्रतिशत रूस से मिली थी। इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि यह सहायता भी हमें अमरीका से ही अधिकांश मिल सकती है।

मैं समझता हूं कि रूस के इस क्षेत्र में तीन उद्देश्य हैं। पहला तो यह है कि वह चीन से प्रत्यक्षत: उठमेड़ नही करना चाहता है। दूसरा यह है कि रूस चाहता है कि साम्यवादी चीन तथा अमरिका इस क्षेत्र में न आये तथा तीसरा यह है कि रूस चाहता है कि पाकिस्तान साम्यवादी चीन के हातों में कठपुतली न बने। इन सीमाओं में हर बारहीं रूस हमारी मदद कर सकता है।

1962 में जब चीन ने हमारी धरती पर आक्रमण किया तो हम जानते हैं कि हमारी सहायता करने के लिए कौन कौन से देश आए थे। हम जानते हैं कि वह अमरीका तथा ब्रिटेन हि थे। श्री रुश्चेव केवल बैठे देखते ही रहे। हमें इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए।

आज रूस तटस्थ है। केवल काश्मीर के मामले पर तटस्थ है परन्तु हम नहीं जानते कि भविष्य में उनका रुख क्या होगा। हम जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में काश्मीर के मामलों पर अब रूस ने वीटो का प्रयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रावदा में लेख में रुस ने काश्मीर के मामले पर हम को तथा पाकिस्तान को एक सतह पर रख दिया है। रूस का वह रवैया आज है। श्री हैरोल्ड विल्सन ने तो पाकिस्तान के लाहोर इलाकें पर हमारे हमले को बुरा कहा था परन्तु इसके साथ साथ मैं सभा का ध्यान 11 सितम्बर के हिन्दुस्तान टाइम्स मे प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें श्री कोसीजिन ने भी बिल्कुल यही बात को दोहरायी हैं। हमने श्री विल्सन को बहुत बुरा भला कहा परन्तु श्री कोसीजिन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। ऐसा करना ठीक नहीं था। इसलिए हमें इन रूसी बातो को समझना चाहिए तथा अपनी विदेश नीति में इसीके अनुसार परीवर्तन करना चाहिए जिससे हमारी कमियां दूर हो सकें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मसानी ने अपने भाषण में बताया कि रूसने हमें कोई अधिक सहायता नहीं दी क्या केवल अमरीका ने ही हमारी पर्याप्त की। मैं जानना चाहती हूं कि अमरीका ने केवल हमको कुछ परिवहन विमान, कुछ गरम कपडे आदि ही दिए थे परन्तु हमने बहुत दिनों से विरोध पाकिस्तानी को सैबर जैट विमान, पैटन टैंक आदि हथियार दिए थे। अमरीका ने हमको सुपरसानिक विमान, पनडुब्बिया आदि नहीं दी।

इन सब बातों में न जाकर इस समय केवल इस बात का जिक्र करना ठीक होगा कि वर्तमान युद्ध का क्या प्रभाव हमारे दिलों पर पड़ा है। एक प्रभाव तो हमारे उपर यह पडा था कि हमको अपने जवानों पर यकीन हो गया था की वह देश की रक्षा करने में समर्थ है दूसरा प्रभाव यह पड़ा था कि हमारे मित्र देशों, अमरिका तथा ब्रिटेन ने हमें नीचा दिखाने का कितना प्रयत्न किया था।

6, 7, 8 सितम्बर को मैं अमरिका में ही थी तथा मेरा अपना अनुभव यह है कि वहां यह कहा जाता था कि विएतनाम के बारेमें जब भारत का विचार हमारे विरोध में हैं तो काश्मीर के बारे में यदि हमारा विचार भारत के विरोध मे हैं तो उसमें कोई बुराई नही है। परन्तु इतना होने पर भी आज अमरीका को ही अपना मित्र समझते हैं तथा श्री पाटिल और श्री बिरला उनकी प्रशंसा करते हैं।

हमें बताया गया है कि प्रधान मंत्री अमरीका जा रहे हैं। प्रधान मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वहां पर अब जाना हमारे हित में है जब कि पहले हमारे साथ बडा सलूक किया गया है।

श्री पाटिल और श्री जी० डी० बिरला दोनों ने मिलते जुलते वक्तव्य दिये हैं। श्री पाटिलने कहा कि उनको अमरीका के प्रतिरक्षा सचिव ने आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को और सैनिक सहायता नहीं दी जायगी। यदि ऐसा है तो इस बारे में वक्तव्य क्यों नहीं दिया गया है। हम जानते है कि हतियारों को सिधे न भेज कर तुर्की के रास्ते भेजा जा रहा है और ईरान तेल दे रहा है। जब तक सीटो और सेन्टों संधियों का निराकरण नहीं किया जाता हम किसी आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकते।

काश्मीर के मामले में हम किसी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसका फैसला हम स्वयंम करेंगे। श्री शास्त्री श्री गोल्डबर्ग के इस कथन पर खुला हो गये कि युद्धविराम पर बातचीत समाप्त होने से पूर्व काश्मीर के राजनीतिक प्रश्न पर चर्चा नहीं की जायेगी। श्री गोल्डबर्ग ने यह कहीं भी नहीं कहा है कि काश्मीर के राजनीतिक प्रश्न को छोड़ दिया जायेगा।

काश्मीर के राजनीतिक प्रश्न के बारे में अमरीकाने अभी भी अपना रवैया नहीं बदला है। भारत जनमत संग्रह नही चाहता। क्या अमरीका ने कभी यह कहा है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? हम रूस का सहमत क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने खुले आम कहां था कि काश्मीर भारत का भाग है। शास्त्रीजी को अमरीका इसलिए बुलाया जा रहा है कि काश्मीर के मामले में उनपर दबाव डाला जाये। इसलिए शास्त्रीजी का वहां जाना देश की इज्जत को कम करना है।

श्री मसानी काश्मीर और वियतनाम के प्रश्नों को एक ही पलडे में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। काश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। क्या वियतनाम भी अमरीका का हिस्सा है? दक्षिण वियतनाम में अमरीका की कठपुतली सरकार है। भारत को वियतनाम में अमरिकी हस्तक्षेप के विरुद्ध तटस्थ देशों और अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ मिल कर आवाज उठानी चाहिये।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाले अनाज को उस समय रोक लिया गया था जब हमारे प्रधान मंत्री ने वियतनाम के प्रश्न पर वक्तव्य दिया था। हम तो यह चाहते हैं कि अमरीका वियतनाम में बमबारी बन्द करे और वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाये। चीन के भय से हमें वियतनाम के लोगों को उनके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। हम केवल सिद्धान्तों के बल पर ही एशिया में पुनः सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। हमें अफ्रीकी एशियाई देशों की एकता पर जोर देना चाहिए। हालही में जिन देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की है उनके महत्व की अवहेलना नहीं की जा सकती। अमरीका और रुस भी इन देशों की अवहेलना नहीं कर सकते। रोडेशिया के संबंध में हमने बिल्कुल सही बात कही है। जैसे हम भारत पर चीन के आक्रमण का समर्थन नहीं कर सकते इसी प्रकार हम वियतनाम में अमरीकी हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते। सिद्धान्तों के आधार पर ही हमें अफ्रीकी एशियाई देशों के संबंध में अपनी नीति बनानी चाहिए है न कि केवल इस आधार पर कि चीन हमारा शत्रु है।

हमारे मंत्री भिन्न भिन्न बातें कहते हैं। हाल ही में श्री मेहरचन्द खन्ना ने कहा कि परमाणु बम बनाना चाहीये। अगले ही दिन प्रधान मंत्री ने कहा कि यद्यपि भारत परमाणु बम बना सकता है परन्तु बनायेगा नहीं। श्री चागला के हाल के वक्तव्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी अब तक की नीति गलत रही है। क्या उनके कहने का यह अर्थ है कि हमारी गुटनिर्पेक्षता की नीति गलत रही है। श्री सी० डी० पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बाहर जानेवाला है। श्री पांडे हमारी गुटनिर्पेक्ष की नीति का समर्थन नहीं करते हैं। वह तो इसकी उलटा बहुत आलोचना करते हैं। इसीलिये हमें पता होना चाहिए कि हमारी नीति क्या है।

हम सीटो, सेन्टो और अमरीकी हथियारो की बात प्रायः करते हैं। हम यह तर्क देते है कि पास्किस्तान को अमरीका द्वारा सैनिक सहायता चीन के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये दी गई थी और इसलिए हमारे विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाना गलत चीज है। इसका तो यह अर्थ हुआ कि यदि यह साम्यवादियों के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाये तो ठीक बात है। क्या यह ही हमारी गुटनिर्पेक्ष की नीति है। हमें अफ्रीकी एशियाई देशों की भावना को समझना चाहीए और उनमें अपनी नीति का प्रचार करना चाहिए।

अल्जीयर्स सम्मेलन में 45 देश इस पक्ष में थे कि रूस को शामिल कर लिया जाना चाहिए और इससे पता चलता है कि वे चीन की नीति का समर्थन नहीं करते हैं। इससे हमें अफ्रीका के देशों की भावना का पता लगता है और इसी को हमें समझने की आवश्यकता है।

मैं अधिक जोर आत्मनिर्भरता पर देना चाहती हूं। पिछली लड़ाई से हमने यही सबक लिया है कि हमें अपने प्रयत्नों से ही अपनी प्रतिरक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है और यह हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। हमारे जवानों ने दिखा दिया है कि वे किस तरह लड़ सकते हैं। हमें उनको हथियार देने हैं जिनसे कि वे लड़ सकें। हथियार कहां से आयें? यहां हम कहते हैं कि क्या हमारे कोई मित्र नहीं हैं? यह तर्क हमारी गुटनिर्पेक्षता की नीती की निन्दा करने के लिये दिया जाता है। कौन हैं हमारे मित्र? केवल वही जो हमें तकनीकी ज्ञान और प्रतिरक्षा उद्योगों को स्थापित करने में सहायता देते हैं। रूस ने हमें सहायता दी है। उसने हमारा समर्थन किया है और उसीकी सहायता से हम आज अपना तेल उद्योग और मिग विमान बना रहे हैं। श्री मसानी ने कहा कि हमें ताइवान को मान्यता देनी चाहिये। क्या ताइवान मेक्मोहन रेखा को मानता है, क्या वहा की सरकार चीन के प्रादेशिक दावों का पूरी तरह समर्थन नहीं करती है?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The two Chinas should be recognised.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं अपने मित्र श्री मधु लिमये को बतादूं कि हमें प्रत्येक चीज को इस दृष्टिकोण से देखना है कि यह हमारे हित में है अथवा नहीं। और इस प्रकार तइवान को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता। हम पश्चिम जर्मनी से डरते हैं और इसलिए पूर्व जर्मनी को मान्यता नहीं दे रहे हैं यद्यपि पूर्वी जर्मनी ही सब से पहला साम्यवादी देश था जिसने यह कहा था कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया है।

जैसा कि हमने प्रधान मंत्री को बता दिया है हम चाहते हैं कि वह इस समय अमरीका न जायें क्योंकि अमरीका ने अभी तक इस बात पर खेद प्रकट नहीं किया है कि उसने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध अमरीकी हथियारों को प्रयोग करने दिया। हमें यह याद रखना चाहिए कि बन्धन हमेशा ही करार के खंडों में नहीं रखे जाते है। पी० एल० 480 करार के संबंध में सरकार ने बहुत गलत निर्णय किया है। यदि हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं तो हमें अपनी नीति को अपने रवैये को बदलना चाहिए। अमरिका हम से बहुत सारी बातें मनवाना चाहता है। अमरीका के टिप्पणीकार की बात हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा था आप कोई चीज़ बिना कुछ दिये नहीं ले सकते हैं। इस लिये मेरा कहना है कि हमें अपनी गुटनिर्पेक्षता की नीति पर दृढ रहना चाहिए। इस नीति पर चल कर ही हम अपने लिये मित्र पैदा कर सकते हैं। हम अपनी निशस्त्रीकरण की नीति पर टिके हुए हैं और हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिये भी खड़े हैं। चीन और अमरीका दोनों हमारी इस नीति का विरोध करते हैं। यदि हम अपनी गुटनिर्पेक्षता की नीति पर चलेंगे तो अवश्य ही हमारी जीत होगी।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : पाकिस्तान और उसके मित्र देशों का यह विश्वास था कि काश्मीर में विद्रोह फैल जायेगा और वहां के लोगों को भड़काने की दृष्टि से ही पाकिस्तान ने काश्मीर में घुसपैठियों को भेजा था। परन्तु अब यह सिद्ध हो गया है कि काश्मीर के लोग पहले भारतीय है और फिर कुछ और।

ठीक खतरे के समय भारत की एकता मज़बूती से बनी रही। इन बातों से बहुत से दावे गलत साबित हुए हैं। उनमें सब से महत्वपूर्ण तो यह था कि जनमत संग्रह से स्थिति बदल जायेगी। यदि जनमत-संग्रह भी होता तब भी काश्मीर के पाकिस्तान को जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। क्योंकि पाकिस्तान विद्रोह की आग भड़काने में बिल्कुल असफल रहा है। पाकिस्तान और उसके साथियों को पता चल गया है कि जनमत संग्रह का कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। राजनैतिक लोग कोई भी देश स्थायी रूप से मित्र या शत्रु नहीं होते हैं! सब का अपना अपना हित होता है और उसके अनुसार नीति बदलती रहती है और मित्र और शत्रु दोनों में भी परिवर्तन होता रहता है।

हम जानते हैं कि ब्रिटेन आज जनमत संग्रह क्यों चाहता है और वह स्वतन्त्र काश्मीर क्यों चाहता है। ब्रिटेन नीति हमेशा से ही यह रही है कि विभाजन करो और हकूमत चलाओ। क्या वह भारत के दो टुकड़े कर के भी खुश नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है। क्या वह अब भी संतुष्ट नहीं है? क्या वह यह समझता है कि वह भारत एक तीसरा अंग बना कर फिर से शासन कर लेगा? वह यह उसकी भूल है और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वह व्यापारियों का राष्ट्र है हम उनके इरादों को अच्छी तरह जानते हैं। हमें राष्ट्रमंडल से नहीं निकलना चाहिये। बहुत से अफ्रीकी और एशियाई देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल में रह कर हम उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं।

मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि हमें राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन का प्रभाव कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा यह सरकार से आग्रह है हमे इस बात का परीक्षण करना चाहिए कि हम और किन चीजों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह आसाम के चाय बागान के लोग गड़बड़ कर रहे है। हमें इस बात का पूरा प्रयास करना चाहिए कि यह काम उनके हाथ से ले लिया जाय।

माननीय सदस्यों ने रूस और अमरीका का उल्लेख किया है । उनकी बात सुनने से यह अहसास होता है कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र की दरारों को अभी समझा नहीं है। हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं । आज साम्यवादी और गैर साम्यवादी विचारधारायें काफी ढीली हो गयी हैं; अतः मेरा मत तो यह है कि हमारी गुटों से निरलेप रहने वाली नीति कायम रहनी चाहिए। समय आने पर सारा संसार उसी रास्ते पर चलेगा जिसे हमारे नेताओं ने निर्धारित किया था। अंग्रेजों ने लोकतंत्रीय परम्पराओं का निर्माण किया इसके लिए हम उनका आभार मानते हैं । परन्तु संकट के समय ब्रिटेन ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया है उसे हम नहीं भूल सकते ।

अमरीका में लोग हैरान है कि ये पेटन टैंक सेबर जट तो साम्यवादी देशों से रक्षा करने के लिए थे, परन्तु इन्हें तो भारत के विरुद्ध प्रयोग किया गया है। क्या उनको अभी तक पता नहीं चला कि स्थिति क्या है ? क्या उनकी नीति में कोई परिवर्तन हुआ है। यदि हुआ है तो हम उनके किसी प्रकार की सहायता स्वीकार नहीं कर सकते। यह सहायता चाहे खाद्य सहायता हो और चाहे कोई अन्य प्रकार की सहायता। यदि अमरीका के अखबार अमरीकी जनता के आगे तथ्य रखे तो सारी स्थिति प्रकट हो सकती है। क्या अमरीका की सरकार इस दिशा में ब्रिटेन से प्रेरणा लेकर चलेंगे ?

मेरा विचार भारत-पाक संघर्ष के उल्लेख को बहुत बढ़ाना नहीं है। परन्तु मेरा कहना यह है कि जहां तक ब्रिटिश सरकार का सम्बन्ध है उसने भारत-पाक संघर्ष में बहुत ही आपत्तिजनक रवैया अपनाया है। लार्ड एटली ने काश्मीर को स्वाधीनता प्रदान करने की बात करके कमाल ही कर दिया है। यह सब इस लिए किया जा रहा है कि खोया हुआ प्रभाव पुनःस्थापित कर लिया जाय। इस तरह के लोगों से किस प्रकार समझौता किया जा सकता है। ब्रिटेन के व्यापार सम्बन्धी कई स्वार्थ गुणा बढ़ गये है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि उसका क्या किया जा सकता है। स्पष्ट स्थिति है कि यदि हम ब्रिटेन पर कोई प्रभाव डालना चाहते हैं तो हमे राष्ट्रमंडल तुरन्त छोड़ देना चाहिये। साथ ही पटसन, चाय, और तेल पर भी कुछ नियन्त्रण करना चाहिए, क्योंकि इन उद्योगों में इनके हित बढ़ते ही जाते हैं।

आज जो स्थिति देश में चल रही है, उसे देखते हुए और तेजी से बदल रहे संसार पर दृष्टि रखते हुए, हम यह कह सकते है कि हमारी गुट निरपेक्षता की नीति ही देश के हित में है और लाभदायक है। भारत-पाकिस्तान संघर्ष से हमें एक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए वह यह कि हमें हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना है। जीवन के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के बारे में तो ऐसा करना ही है।

अब मैं रोडेशिया की ओर आती हूँ। वहां गोरों ने विद्रोह कर रखा है। परन्तु मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे मंत्री ने इस दिशा में बहुत अच्छा रवैया अपनाया है। उसके लिए वह बधाई के पात्र है। यह आश्चर्य की बात है कि इतने विशाल क्षेत्र में अफ्रीका के बहुमत को श्वेत बहुमत के नीचे रखने का प्रयास किया जा रहा है। और यह सब जानबूझ कर किया जा रहा है। मेरा मत यह है कि यह बात सारे संसार के लिए महत्वपूर्ण है। विल्सन सरकार इसके विरुद्ध फौजी कार्यवाही करने से संकोच कर रही है। हमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, और यह देखना चाहिए कि यह अत्याचार न होने पाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें केवल यह समझ कर ही नहीं बैठ जाना चाहिए कि क्योंकि हम सत्य पथ पर है, इस लिए विजय हमारी ही होगी। हमें अपने पक्ष का प्रचार करना होगा और अपना पक्ष संसार के समक्ष विस्तार से रखना होगा। मेरा मत तो यह है कि विदेशों में प्रचार के लिए अलग मंत्रालय होना चाहिए। विदेशों में हमारे प्रतिनिधियों को अपने पूरे साधनों से देश की सांस्कृतिक सम्पत्ति तथा आधुनिक सांसारिक प्रवृत्तियों की पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने कूटनीतिक सम्बन्धों दम्भ और आडम्बर का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।

[श्रीमती रेणुका राय]

हम अपनी देश की अखण्डता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमे अपने जीवन तत्व की भी रक्षा करनी है। मैं सरकार की नीति का समर्थन करती हूँ और आशा करती हूँ कि जिस प्रकार हमारे जवानों ने रणक्षेत्र में धीरता और वीरता का परिचय दिया हम अपने घरेलू मोर्चे पर भी वैसा ही करके दिखायेंगे।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : आज सारे विश्व में बड़ी महत्वपूर्ण घटनायें हो रही है। परन्तु हमें केवल उन्हीं बातों का विचार करना है, जिनका सम्बन्ध सीधे हमारें हितों के साथ है। कारण यह है कि आज हमें चीन और पाकिस्तान, इन दो शत्रुओं से हमें एक ही वक्त में दो चार होना पड़ रहा अतः हमें अपने दृष्टिकोण को अधिक व्यावहारिक बनाना चाहिए।

काश्मीर के मामले में हमने अपूर्व संगठन का परिचय दिया है। पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान सरकारी कार्यवाही का समर्थन सभी दलों ने एकमत से किया है। अब जब कि युद्ध समाप्त हो चुका है, तो ठंडी लड़ाई आरम्भ हो गई है। राजनीतिक और कूटनीतिक आधार पर हलचल आरम्भ हो गयी है। अतः आज की स्थिति में यह जरूरी है कि हमारा व्यवहार ऐसा ही हो जैसा युद्ध के दौरान में रहा है।

मैं इस भ्रांति को भी दूर करना चाहता हूँ कि काश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के पास है, वह उनके पास ही रहेगा। यह गलत दृष्टिकोण है। इससे हमारा पक्ष कमजोर पड़ता है। सारा जम्मू काश्मीर का राज्य हमारा है। कानूनी तौर पर राज्य का विलय भारत के साथ हुआ है, अतः वह सारा ही भारत का अंग है। जनमत का जहां तक प्रश्न है काश्मीर की जनता की राय काश्मीर विधान सभा के चुनावों से व्यक्त हो गयी है। वैसे भी जिन हालात में जनमत का आश्वासन दिया गया था, वे पैदा हुए ही नहीं। अतः आज जनमत का प्रश्न वहां उत्पन्न ही नहीं होता। जो भी भाग आज काश्मीर के पाकिस्तान के कबजे में है, वे कानून के अनुसार हमारे हैं।

सुरक्षा परिषद् ने विवादों पर जो भी रवैया अपनाया है, वह इस मामले के तथ्यों के आधार पर नहीं है। वह तो विशेष राष्ट्रों के हितों की अभिव्यक्ति है। हमें अपने हितों के प्रति जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए उसी तरह आग्रह करते रहना है, जिस तरह कि हमने गत दो तीन मास के समय में किया है। पाकिस्तान में अभी हाल शीघ्र ही तानाशाही समाप्त होती दिखाई नहीं देती। अतः मेरे विचार में हमें यह घोषणा कर देनी चाहिए कि पूर्वी पाकिस्तान को दास्ता से मुक्त कराने तथा पख्तूनिस्तान को आजाद कराने के आन्दोलनों का हम समर्थन करते हैं।

हमे पाकिस्तान और चीन के एक साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें बड़ी व्यावहारिक नीति अपनानी चाहिए। हमे केवल उन राष्ट्रों की सहायता करनी चाहिए और उनको अपना मित्र बनाना चाहिए जो संकट के समय हमारे काम आने को तत्पर हों। हमें रूस और मलयेशिया का आभार मानना चाहिए। यह भी अच्छा है कि यह घोषणा कर दे कि कौन हमारें शत्रु और कौन हमारे मित्र हैं। जो लोग हमारे शत्रु है, उनको हमें मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि देश से बाहर जाने वाले शिष्टमंडलों में शिक्षित तथा प्रतिभाशाली लोगों को रखा जाना चाहिए। उन्हें सभी प्रकार से मामलों की जानकारी होनी चाहिए। उन में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि देश का पक्ष योग्यता से प्रस्तुत कर सके।

चीन के साथ हमारा समझौता हो पाना सम्भव नहीं है। वह केवल उसी हालत में सम्भव है जब कि हम साम्यवादी हो जाय अथवा उनकी अभिभावकता स्वीकार कर ले। इन दोनों बातों का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। परन्तु हमें यह बात भी सामने रखनी चाहिए कि चीनी खतरा पाकिस्तान से भी अधिक भयंकर है। चीन के साथ युद्ध का मतलब तो सारी चीनी जनता से युद्ध करने वाली बात है। अतः इस धमकी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और हमें बडे क्रांतिकारी और व्यापक आधार पर उसके लिए तैयारी करनी है। इसके लिए हमे उसी तरह तैयारी करनी चाहिए जिस प्रकार की हमनें 1942 के आन्दोलन में की थी।

श्री अ० च० गुह (बरसात) : हमें अपने देश की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए अगस्त मास में पाकिस्तान से संघर्ष करना पड़ा । पाकिस्तान ने काश्मीर में अवैध रूप से घुसपैठियों भेजे । वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि काश्मीर के लोगों ने विद्रोह कर दिया है । और पाकिस्तान के लोग इस के लिए अपने भाइयों की सहायता करने वहां गये । वे पाकिस्तान के आत्मनिर्णय के हक के समर्थक हैं । यह बात बिल्कुल गलत है कि यह विद्रोह है और यह राजनीतिक असन्तोष है । वे लोग संसार के समक्ष अपने पक्ष का औचित्य सिद्ध नहीं कर पाये हैं । मेरा मत यह है कि इस बारे में हमारा वैदेशिक कार्य मंत्रालय भी उत्तरदायी है । उन्होंने अपने पक्ष का अपेक्षित प्रचार नहीं किया है ।

काश्मीर का कानूनी रूप से भारत से विलय हुआ है और इस सहमिलन का विधिवत निर्वाचित संविधान सभा तथा बाद में व्यस्क मताधिकार पर आधारित आम चुनाव से अनुमोदन किया गया था । फिर भी विश्व को अभी तक हमारे मामले के सही होने का विश्वास नहीं हुआ है । हमारी आरम्भिक गलती यह थी कि हमने पाकिस्तान की स्थापना के बारे में निहित अर्थों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया था तथा तत्पश्चात् हमने उन निहित अर्थों तथा इरादों का प्रतिकार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की । पाकिस्तान की स्थापना आंग्ल अमरीकी राष्ट्रों की चाल का परिणाम था और अपने स्थापकों के प्रति अपनी श्रद्धा के कारण यह उनके हाथों में खेलता रहा है । हमें पाकिस्तानी अतिक्रमण के विरुद्ध केवल रक्षात्मक उपाय करने पर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये ये उपाय पूर्वी क्षेत्र में हो अथवा पश्चिमी क्षेत्र में । हमारी सेनाओं को अतिक्रमकों का उनके क्षेत्र में भी पीछा करते रहना चाहिये । हमें अपने आस पास के देशों को विश्वास दिलाना चाहिये कि भारत का उद्देश्य शान्ति बनाये रखना है और कि एक शक्तिशाली भारत साम्राज्यवादी नहीं होगा क्योंकि वह देश अभी उस साम्राज्यवाद को नहीं भूल सके है जो ब्रिटिश शासन में भारत में स्थापित किया गया था ।

हम ने चीनियों को अपने मित्र समझकर तथा चीनी साम्राज्यवाद को तिब्बत देने से एक गलती की है । इण्डोनेशिया के मामले में भी हम ने गलती की है । हम ने पश्चिमी ईरियन पर इण्डोनेशिया के दावे का समर्थन किया है जिस पर कि वास्तव में उसका भूगोल, जाति, भाषा, अथवा संस्कृति के आधार पर कोई अधिकार नहीं है । पश्चिमी ईरियन को पापुआन द्वीप के अन्य भाग के साथ मिलाया जाना चाहिये था और उसे संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण के अधीन रख कर उसका स्वायत्तशाली देश के रूप में विकास किया जाना चाहिये । पाकिस्तान की तुलना में हमारा विदेशी प्रचार बहुत कम रहा है और उसमें कोई सफलता नहीं मिली है । इसे अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये । विदेशी प्रचार पर इस दृष्टि से पुनर्विचार किया जाना चाहिये कि क्या विदेशों में हमारा दृष्टिकोण ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान समय में, चीन की एशिया और अफ्रीका में स्थिति खराब हो रही है । भारत को इस बात का लाभ उठाना चाहिये और अफ्रीका के विकासशील देशों की ओर जहां भारत बहुत बड़ा कर्तव्य निभा सकता है ध्यान देना चाहिये । इसी प्रकार लैटिन अमरीका की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । हमें इन महाद्वीपों के साथ व्यापारिक तथा राजनतिक सम्बन्ध बढ़ाने चाहिये । इस देश की सारे विश्व भर में उपेक्षा हुई है । हमे तो वह कच्चे माल भी दे रहा है ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमे काफी समझदार लोगों को विदेश भेजना चाहिए विशेष रूप से लातीनी अमरीका में और अरब अफ्रीकी राष्ट्रों में । आज अफ्रीका की दास प्रथा सारे विश्व के लिए शर्म की बात है । उसकी ओर हम ध्यान देना चाहिए ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : गत कुछ वर्षों से इस तरह की प्रवृत्ति देश में रही है कि हम अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार राष्ट्र की नीति को नहीं बना पाये हैं । हम हमेशा इस दिशा में नीति निर्धारित करते हुए बाह्य देशों से डरते रहते हैं । एक बार ऐसा अवश्य हो गया कि हमने यह निश्चय किया कि हम पाकिस्तान के हमले का मुकाबला करेंगे । प्रश्न अवसर का था जब कि हमने दृढ़ निश्चय से बात की । इस दृढ़ निश्चय में राष्ट्र का हृदय धड़क रहा था । हमें स्मरण रखना चाहिये कि राष्ट्र की नीति निर्माण करते समय हमें हमेशा राष्ट्र के हितों का ही ध्यान रखना, यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्या कहेगा ।

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

हमने हाजी पीर और उरी में जिन चौकियों पर कब्जा किया है उनसे पीछे नहीं हटना चाहिये। काश्मीर भारत का भाग है और हमने उसके एक भाग को वापस लिया है। उसपर हमारा अधिकार है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हैं और पाकिस्तान को तैयारी करने का समय क्यों दे रहे हैं। हमें लड़ाई के मैदान में एक बार उतर कर पीछे नहीं हटना चाहिये और लड़ने के लिये हमें किसी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

पाकिस्तान ने युद्धविराम के पश्चात जैसलमेर क्षेत्र में 13 पुलिस चौकियों में से 11 को वापिस ले लिया है। हमने उनको वापस नहीं लिया है। हम किसी प्रतीक्षा कर रहें हैं उनको वापस लेने के लिये? हम जानते हैं कि अब बर्फ पड़ना आरम्भ हो गई है और चीन पाकिस्तान की सहायता नहीं कर सकता है फिर भी न जाने हम क्यों चुपचाप बैठे हैं।

श्री बडे (खारगोन) : परन्तु अब तो युद्धविराम हो गया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : युद्धविराम क्या है? आपको अंग्रेज़ों से राजनीति सीखनी चाहिये। एक साधारण अंग्रेज़ अपने व्यक्तिगत मामलों में बहुत ही ईमानदार है परन्तु जहां पर राष्ट्रीय हितों का प्रश्न आता है उससे अधिक बेईमान कोई नहीं होगा। जब हमारे राष्ट्रीय हितों का प्रश्न आता है तो हम अध्यात्मिकता की बातें करते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। इस 20 दिन की लड़ाई से हमने जो सबक लिया है उसके आधार पर हमें अपनी नीति बनानी चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTY *in the Chair*]

हमें अपने मित्रों और शत्रुओं का पता चल गया है। बहुत शर्म की बात है कि कुछ देशों को खुश करने के लिये हमने किसी खास धर्म के व्यक्तियों को राजदूत बना कर भेजा। हमने डा० जाकिर हुसेन और श्री मेनन को बाहर भेजा। उन्होंने इजराइल को नष्ट करने के बारे में वक्तव्य दिया। क्या किसी राष्ट्र को नष्ट करना हमारा काम है?

हमें अपने देश के हितों को ध्यान में रख कर अपनी नीति बनानी चाहिये और किसी बात को ध्यान में रख कर नहीं।

20 लाख की आबादी के छोटे से देश जोर्डन ने कहा कि वह पाकिस्तान का साथ देगा। और हमने उसका यहां तक समर्थन किया कि यदि इज़राइल ने जार्डन के पानी को रोका हो हम जार्डन की सहायता करेंगे। हमें ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी? क्या हम इजराइल को भूखा मारना चाहते थे? हमने तुर्की और ईरान और संयुक्त अरब गणराज्य की मित्रता को देख लिया है। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। जब तब आपके पास शक्ति नहीं होगी आप के सामने कोई नहीं झुकेगा।

तिब्बत के मामले में हमने जो बहुत बड़ी गलती की है उसके परिणामस्वरूप हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाना चाहते हैं। इस हिन्दी चीनी भाई भाई की नीति ने हमें बरबाद कर दिया है। हमने सारी दुनिया का ख्याल किया परन्तु तिब्बत का हमने कोई ख्याल नहीं किया। हम अल्जीरिया की सहायता करना चाहते थे। उसने उस सम्मेलन को नहीं बिठाया जिसके लिये हमने दो बार अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। उसने हमारा अपमान किया। चीन के इशारे को वह दूर से मान गया और हमें वहां से बाहर निकाल दिया।

राष्ट्रमंडल से बाहर निकलने की बात कही जाती है। हम क्यों निकल जायें? अंग्रेज़ों को ही उसमें से क्यों नहीं निकाल देते। क्या अपनी आंखें मुंद लेने से सचाई छिप जायेगी?

क्या कारण है कि पाकिस्तान का प्रचार सफल होता है और हमारा नहीं ? क्या आपने कभी इस इस बात पर गौर किया है कि विदेशों में हमारे उच्चायुक्तों का रवैया कैसा है ? ब्रिटेन में हमारे उप उच्चायुक्त की पत्नी अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं और किसी से बात भी करना पसन्द नहीं करती है। कैनेडा, न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया हमारे मित्र हैं परन्तु हमारे उच्चायुक्तों का रवैया ठीक नहीं है। वे लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं और अपना दृष्टिकोण उनके सामने नहीं रखते हैं।

मैंने सुना है कि हमारे आई० सी० एस० अधिकारी विदेश सेवा में इसलिये जाना चाहते हैं कि वे छोटे व्यक्तियों से झुकना पसन्द नहीं करते। छोटे व्यक्ति आप और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। उनको हमारी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है।

हमें अपनी नीति इस आधार पर बनानी चाहिये कि हमारी जनता क्या चाहती है न कि इस आधार पर कि अमरीका और रुस और अरब गणराज्य क्या चाहते हैं। हमें किसी से प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

हमें अपने मित्रों और शत्रु राष्ट्रों का पता चल गया है। जो तो हमारे मित्र हैं उनके साथ हमें अपनी मित्रता मजबूत करनी चाहिये और जो देश न इधर हैं और न उधर उनके सामने हमें अपना मामला रखना चाहिये और जब वे अच्छी तरह समझ जायेंगे तो वे हमारा पक्ष लेंगे और जो राष्ट्र स्पष्ट रुप से हमारे विरूद्ध हैं उनके साथ हमें बात भी नहीं करनी चाहिये और अपने देश का विकास करना चाहिये और समय आयेगा जब हमारा देश शक्तिशाली हो जायेगा तो वे भी हमारे आगे झुकेंगे।

सभापति महोदय : श्री मौर्य ने अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विशेष अनुमति मांगी है। मैं उनको यह अनुमति देती हूँ। यदि कोई और माननीय सदस्य ऐसा करना चाहे तो कर सकता है।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 19 प्रस्तुत करती हूं।

महाराज विजय आनन्द (विशाखापटनम) : जिसमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई छिड़ी मैं लन्दन में था। वहां मने देखा कि वहां के समाचार पत्रों में पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के विरुद्ध बहुत कुछ निकलता था। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का प्रचार बहुत तीव्र था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वहां पर भारत के सब से बड़े प्रतिनिधि के पास गया और उनसे कहा कि वह देखें कि भारत के विरूद्ध कितना प्रचार हो रहा है। मुझ से कहा गया कि अन्त में सच की ही जीत होगी और गांधीजी की नीति का पालन किया जायेगा। मैं मानता हूं कि सच की जीत होगी, परन्तु प्रचार और विज्ञापन के नाम की भी कोई चीज़ है। हमें बाहर ऐसे व्यक्तियों को चुन कर भेजना चाहिये जो जनता को अपनी तरफ जीत लें।

जिस समय श्री विल्सन न कहा कि हमारी सीमाएं हिमालय हैं मैं उस समय वहीं पर था। वे शब्द कितने अच्छे लगे थे। परन्तु लड़ाई छिड़ने के बाद से उनके रवैये में परिवर्तन आ गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि वहां की जो नई पीढ़ी है वह भारत के विरुद्ध नहीं है। केवल अधेड़ और वृद्ध आयु के लोग ही भारत के विरूद्ध हैं। वे यह समझते हैं कि हिन्दुओं ने ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है। वर्तमान लड़ाई ने उनकी कई धारणाओं को गलत सिद्ध कर दिया है। उनका विचार था कि लड़ाई छिड़ने से हिन्दु और मुसलमानों में दंगे शुरु हो जायेंगे और वही तमाशा फिर से होगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। संसार अब यह समझने लगा है कि भारत वास्तव में एक धर्मनिर्पेक्ष देश है।

[महाराज विजय आनन्द]

बाद में श्री चागला वहां गये । उन्होंने टेलीवीज़न पर अपने विचार व्यक्त किये और विश्वास कीजिये इसका इतना प्रभाव पड़ा कि वहां के लोग यह कहने लगे आपके चागला साहब ने काश्मीर का सही चित्र हमारे सामने रखा है । हमें ऐसे व्यक्तियों को भेजकर जो दूसरों का प्यार हमारे लिये जीत सकें विदेशों से संबंध सुधारने चाहिये । अफ्रीकी देशों में चीन की मित्रता बढ़ती जा रही है । पंडित नेहरू ने नासिर को संसार की नज़रों में उठाया परन्तु उस नासरने हमारे लिये सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा । हमारे पड़ोसी देशों में एक मलेशिया ही हमारा मित्र सिद्ध हुआ है ।

कुछ लोगों का कहना है कि हमारी आकाशवाणी ने लड़ाई के दौरान अच्छा कार्य नहीं किया । परन्तु मैंने लन्दन में अपनी आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुना वे बहुत ही प्रशंसनीय थे ।

जब मैं लन्दन में था तो मैं ने सुझाव दिया कि हमें संवाददाता सम्मेलन का प्रबन्ध करना चाहिये और उसमें संवाददाताओं के खाने पीने का भी प्रबन्ध हो । परन्तु इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया । मुझे कहा गया कि हम एक साप्ताहिक पत्र को पढ़ सकते हैं । मैंने कहा कि एक साप्ताहिक पत्र से क्या काम चलेगा जब कि पाकिस्तान का प्रचार इतना अधिक है कि उसे बताया नहीं जा सकता । इस बात को भी नहीं माना गया ।

रोडेशिया के मामले के बाद हो सकता है राष्ट्रमंडल टूट जाये । हम देखते हैं क्या होता है और रोडेशिया का फैसला होने के बाद ही हमें निश्चित करना चाहिये कि हमें ब्रिटेन के साथ संबंध बनाये रखना चाहिये अथवा नहीं । मेरा अपना विचार तो यह है कि हमें संबंध बनाये रखना चाहिये क्यों कि वहां की नई पीढ़ी में कोई पक्षपात की भावना नहीं है ।

हमें आखिर अपने पैरों पर खड़ा होना है । हमें अपनी नीति से पीछे नहीं हटना है ।

हमारे प्रधान मंत्री श्री शास्त्रीजी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । अमरीका और ब्रिटेन के लोग अब उनकी दृढ़ता की बातें करते हैं । कठिन परिस्थितियों में उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया है और उनका स्थान भारत के सब से बड़े प्रधान मंत्रियों में होगा ।

जनरल चौधरी विश्व के सब से बड़े जनरेलों में से एक हैं । उनको पद्मविभूषण दिया गया है । क्या भारत रत्न केवल राजनीतिज्ञों के लिये ही हैं ? जिस व्यक्ति ने हमें लड़ाई जीत कर दी है उसको सब से बड़ा पुरस्कार दिया जाना चाहिये था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : सभापति महोदय हमारी विदेश नीति कोई सफल नहीं रही है । इसको हमने दो तरीकों से आंकना है । एक तो यह कि हमारी विदेश नीति से हमारी सुरक्षा और अखंडता को जो भय है उसको दूर करने में कहां तक सहायता मिली है और दूसरे यह कि हम अपनी नीति के लिये कितने देशों का समर्थन प्राप्त कर सके हैं । जहां तक दूसरी बात का प्रश्न है इस आपात की स्थिति में भी हमने विदेशों में अपने प्रचार में कोई सुधार नहीं किया है । इसलिये संसार के लोग हमारे दृष्टिकोण को समझ नहीं सके हैं ।

दूसरा प्रश्न विदेशों में हमारे राजनीतिक कर्मचारियों का है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इसमें बहुत सी त्रुटिया है और हमारे समस्त राजनयिक कर्मचारिवर्ग और विदेश सेवा का पुनर्गठन होना चाहिये । इस क्षेत्र में असफल रहे हैं । हमने महत्वपूर्ण स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों को भेजा हुआ है जिन में न तो क्षमता है और न दिमाग है । वे हमारे देश की वास्तविक तस्वीर को वहां के लोगों के सामने

नहीं रखते हैं। वे "लंच" "डिनर" और पार्टियों में ही लगे रहते हैं। इस कार्य में हमें तब ही सफलता मिल सकती है जब हमारे मामले को वे सही ढंग से रखें। इस समय विदेशों में हमारे प्रतिनिधि परस्पर विरोधी वक्तव्य देते हैं और जिस देश में वे जाते हैं वहां के वातावरण के अनुकूल बात कह देते हैं। हमें वह बात कहनी चाहिये जिसे हम ठीक और उचित समझते हैं। वास्तव में हमारी कोई विदेश नीति नहीं है।

हम गुटनिर्पेक्षता और सहअस्तित्व की नीतिकी बात करते हैं। यह सिद्धान्त अच्छा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। परन्तु इसकी क्रियान्विति में हम गलती करते हैं। हमने इसी कारण तिब्बत को अपने हाथों से खो दिया है। हमने अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में नहीं रखा है। लड़ाई के बाद अब हमें अपनी विदेश नीति को फिर से सोच विचार कर के बनाना चाहिये और उस में राष्ट्रीय हित को सब से अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

पश्चिमी शक्तियां नहीं चाहतीं कि हम विकसित हो कर एक शक्ति में बदल जायें। माननीय विदेश मंत्री को बताना चाहिये कि कौन हमारे मित्र है और कौन हमारे शत्रु हैं। इन्डोनेशिया के विरुद्ध हमें मलेशिया की सहायता करनी चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

यह स्पष्ट है कि किसी भी अरब देश ने हमारा साथ नहीं दिया है। अफ्रीकी देशों ने भी तटस्थता का रवैया अपनाया है। हमे अरब देशों को बता देना चाहिये कि उनका रवैया मित्रता का नहीं रहा है। हमें इजराइल के साथ मित्रता बनानी चाहिये।

हमें सदा उन लोगों का साथ देना चाहिये जो युद्ध के समय हमारे साथ रहे हैं। हमें पड़ोसी देशों का समर्थन बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हमने उनके साथ मित्रता बढ़ाने और आने वाले खतरों से उन्हें सावधान करने का कभी प्रयास नहीं किया है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हमें अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, मलयेशिया, सिंगापुर और जापान जैसे पड़ौसी देशों के साथ न केवल राजनैतिक सम्बन्ध बल्कि परस्पर सहयोग और मत्री के आधार पर निकट आर्थिक सम्बन्ध भी स्थापित करने चाहिये।

यदि सरकार अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति जारी रखना चाहती है तो उसे अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा। यदि भारत राष्ट्रों में अपना उचित स्थान बनाना चाहता है और आत्म-सम्मान बनाये रखना चाहता है, तो उसे बहुत बड़ी शक्ति बनना होगा। हमें एक शक्तिशाली परमाणु शक्ति बनना चाहिये। हमें चीन से पहले परमाण शक्ति बनना चाहिये था। जब हमारे हितों का प्रश्न होता है, कोई राष्ट्र हमारी सहायता नहीं करता है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए तथा देश के लोगों की यह भावना बनाये रखने के लिए, कि उनके पास सुरक्षा की शक्ति है, परमाणु बम बनाना चाहिये। प्रधान मंत्री में पुराने विचारों की ओर झुकने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है। हमें परमाणु बम बनाने में रुकावट नहीं पड़ने देनी चाहिये।

संसद् ने देश में नई भावना उत्पन्न करने के लिए जवानों को कई बार श्रद्धान्जलि अर्पित की है। पाकिस्तानी आक्रमण के बाद हमने आत्म-निर्भरता और रक्षा में विश्वास रखने वाले नये राष्ट्र का रुप धारण कर लिया है। इस भावना को बनाये रखना होगा। हमें दूसरों को प्रसन्न करने की नीति त्याग देनी चाहिये और यदि आवश्यक हो तो अकेले आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिये। ऐसा डर होने लगा है कि पहले के दृढ़ संकल्प का स्थान भटकाव की नीति ने ले लिया है और हमारे पहले के दृष्टिकोण के कमज़ोर होने के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

हम काश्मीर के सम्बन्ध में किसी ब्रिटिश सरकार पर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वह "कनजर्वेटिव" सरकार हो या "लेबर" सरकार। राष्ट्रमण्डल को समाप्त कर दिया जाना चाहिये क्योंकि अंग्रेज़ों के प्रयोजन के अतिरिक्त वह कोई और प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। राष्ट्रमण्डल में रहने का कोई लाभ नहीं है। हमें अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के साथ निकट सहयोग और दूसरे यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक और दूसरे सम्बन्ध बढ़ा कर अपनी नीति का नवीकरण करना चाहिये। ब्रिटिश सरकार दोरुखा रवैय्या अपना रही है। वह रोडेशिया के सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती परन्तु अमन को दबाने के लिए दमनकारी कार्यवाहियां कर रही है। श्वेत राष्ट्र और श्वेत् अल्पसंख्यक वर्ग के मामल में वह शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहती। दक्षिण रोडेशिया की स्थिति से मलावी, टांगानीका और कांगो जैसे पड़ौसी देशों को खतरा हो गया है। बड़ी शक्तियों को हम बात की गारंटी देनी चाहिये कि श्री आयन स्मिथ ज़म्बिया को तांबे और विद्युत सम्भरण के लिए तारों के निर्यात में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

जहां तक अमरीकियों का सम्बन्ध है, अब यह स्पष्ट हो गया है कि उनका यह दावा झूठा है कि वे सदा लोक राज के हित में काम करते हैं। इस लिए, यह उचित नहीं है और यह बात हमारे आत्म-सम्मान के प्रतिकूल है कि हम अमरीका में केवल इस कारण अपना विशेष दूत भेजें कि वह प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति जानसन से मुलाकात का प्रबन्ध करे।

हम सोवियत रुस के हमें समय पर तथा बहुत ही महत्वपूर्ण समय में सहायता देने के लिए आभारी हैं। उसने काश्मीर के सम्बन्ध में सदा हमारी सहायता की है। हमें यह महत्वपूर्ण मैत्री बनाये रखनी है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रुस भी पाकिस्तान को प्रसन्न रखना चाहता है ताकि उसे चीन से दूर रखा जा सके।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि चाहे रुस हो, अमरीका हो या ब्रिटेन, वे सभी काश्मीर के सम्बन्ध में राजनैतिक समझौते के इच्छुक हैं। उन देशों पर सभी प्रकार के दाबाव डाले जा रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। हमें काश्मीर के सम्बन्ध में कोई आकर्षिक समझौता कराने के जाल में नहीं फंसना चाहिये। काश्मीर के बारे में किसी से बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं है और ऐसा प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। काश्मीर पूर्णतया हमारा अपना प्रश्न है और हमें इस सम्बन्ध में बार बार कुछ कहते नहीं रहना चाहिये। मैं प्रधान मंत्री को सभा और देश के समक्ष किया गया प्रण याद दिलाना चाहता हूं। हज़ारों जवानों ने इस प्रश्न पर अपना जीवन दे दिया है।

विदेश मंत्री के वक्तव्य यह स्पष्ट होता है कि हम काश्मीर के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिए तैयार हैं जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में है। यह बात बहुत खतरनाक है। इसका अर्थ यह है कि हम काश्मीर के सारे प्रश्न पर फिर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिये कि जब तक पाकिस्तान हमारे क्षेत्र के एक भाग पर अवैध कब्ज़ा बनाये रखेगा; समझौते की बातचीत का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यह देश के प्रति वचन है और यदि सरकार अपने वचन से हट गई तो लोग उसे पद से हटा देंगे।

हमें इस देश की एकता बनाये रखना चाहिये और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना चाहिये। देश की वर्तमान दशा और लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुये विदेश नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

श्री हरिचन्द्र माथुर (जालोर) : प्रजा-समाजवादी दल के नेता ने कहा है कि युद्ध-विराम के बाद भारत सरकार फिर कमज़ोरी की नीति अपना रही है। इस अधिवेशन के आरम्भ में प्रधान मंत्री ने नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया था। यदि सरकार कोई और नीति अपना रही होती तो प्रधान मंत्री वह वक्तव्य न देते।

उन्होंने विदेश प्रचार के बारे में भी कहा है। सच यह है कि इस सम्बन्ध में सारा दोष प्रचार का नहीं है।

पाकिस्तान पिछले दस वर्षों से युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब पाकिस्तान ने अपने आप को अस्त्र शस्त्रों से तैय्यार कर लिया है। भारत द्वारा आपत्ति किये जाने के बावजूद भी अमरीका ने पाकिस्तान को नवीनतम शस्त्रास्त्र दिये थे क्योंकि पाकिस्तान में अमरीका का हित था। जब ब्रिटेन और अमरीका पाकिस्तान को काश्मीर देने में असफल रहे तो पाकिस्तान ने घुसपैठिये भेजे और इस्लाम का नारा लगाया ताकि उन देशों को तटस्थ बनाया जाये जहां मुसलमानों का बहुमत है। इसके बाद उनका इरादा विश्व और सुरक्षा परिषद् के सामने काश्मीर की समस्या को एक "सम्पन्न कार्य" के रुप में पेश करने का था। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यह उन ताकतों के साथ, विशेषकर ब्रिटेन के साथ, कुछ साठगांठ कर के किया गया। परन्तु ब्रिटेन के अनुमान गलत निकले। उन्होंने पहला गलत अनुमान उस समय लगाया जब उन्होंने यह देश छोड़ा। पहले उन्होंने यह सोचा था कि विभाजन के बाद काश्मीर जैसी समस्याओं के कारण भारत एक कमज़ोर देश बना रहेगा। फिर उन्होंने यह सोचा कि पाकिस्तान काश्मीर को लेकर विश्व के समक्ष एक "सम्पन्न कार्य" प्रस्तुत करेगा।

मेरा विचार है कि अमरीका का काश्मीर में हित नहीं है। चाहे काश्मीर भारत में रहे या पाकिस्तान में, अमरीका को इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसका पाकिस्तान में हित इसलिए है क्योंकि वहां उसके अड्डे हैं।

हमारे लिए इस समय मुख्य बात यह है कि देश एक हो गया है। हमारे जवानों ने मोर्चे पर बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी दल के प्रत्येक संसद सदस्य ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण करें कि हाल ही में हम पर थोंपे गये युद्ध का अन्तिम निर्णय क्यों नहीं होने दिया गया है। शत्रु को पूरी तरह हटाना चाहिये था ताकि भविष्य में ऐसा कभी न होने पाये। युद्ध विराम के बाद पहला प्रश्न सेनाओं की वापसी का नहीं बल्कि यह है कि आक्रमणकारी कौन है। पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित किया जाना चाहिये। हमें पाकिस्तान को युद्ध-विराम क्षेत्र से परे खदेड़ देना चाहिये। प्रति दिन युद्ध-विराम का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान को युद्ध-विराम के बाद राजस्थान क्षेत्र में कब्ज़ा की गई चौकियों से खदेड़ देना चाहिये। हमें वहां अपनी प्रतिरक्षा व्यवस्था नवीनतम तरीके से चलानी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि पोकेरन से जैसलमेर तक रेलवे लाईन बनाई जाये।

हमें रुस द्वारा दी गई भारी सहायता के महत्व को कम नहीं करना चाहिये। न केवल इस मामले में बल्कि आर्थिक मामलों में भी रुस ने हमारा साथ दिया है। हमें उस देश के प्रति तथा उन समाजवादी देशों के प्रति, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, कृतज्ञ होना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने सफलता प्राप्त की है। यदि अब हम दृढ़ रवैय्या अपनायेंगे तो अमरीका हमारे सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य होगा। चीनी उद्देश्यों को रोकने के सम्बन्ध में अमरीकी नीति के लगभग विफल होने के कारण भारत ही इस सम्बन्ध में सफल हो सकता है। जितना शीघ्र अमरीका यह बात अनुभव कर लेगा, उतना ही अच्छा होगा।

मैं नहीं चाहता कि सरकार परमाणु बम बनाने की कोई नीति जल्दबाज़ी में बनाये परन्तु मैं प्रधान मंत्री की यह बात नहीं मानता कि हमें परमाणु बम के बारे में भूल जाना चाहिये। चूंकि चीन हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, इसलिए, हम परमाणु बम के निर्माण की बात कभी नहीं भूल सकते।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

हमारी विदेश नीति सह-अस्तित्व और गुट-निरपेक्षता की नीति है। विदेश नीति के मूल सिद्धान्तों के बारे में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि यह मूल सिद्धान्त बिल्कुल ठीक है।

श्री बाबर अली मिर्ज़ा (वारंगल) : मैं सरकार की विदेश नीतिका पूर्ण समर्थन करता हूं। पाकिस्तान के साथ हमारे हाल ही के संघर्ष से यह सिद्ध हो गया है कि न केवल हमारी विदेश नीति बल्कि हमारी गृहनीति भी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का आक्रमण कोई साधारण बात नहीं है। हमारी सरकार की विदेश नीति तथा गृह नीति ने हम में विश्वास उत्पन्न कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

---

*नागा विद्रोहियों के साथ शान्तिवार्ता

** PEACE TALKS WITH NAGA REBELS

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्रीमन्, सरकार द्वारा श्री फिज़ो के साथियों के साथ नागा समस्या के राजनैतिक दल के सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए हैं। नागा विद्रोहियों के दुराग्रह के कारण बातचीत विफल होकर रहेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि नागा विद्रोहियों ने 1953 में सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था और उस समय से उनकी गतिविधियां बढती जा रही हैं।

तथाकथित युद्ध-विराम 5–6 सितम्बर, 1964 की रात्रि को लागू हुआ था। जब एक और प्रस्ताव किया जा रहा है। भारत सरकार इस शान्तिवार्ता को मंत्रि मण्डलीय स्तर पर ला रही है। परंतु समस्या यह है कि नागा विद्रोही अपनी शर्तों पर समझौते के अतिरिक्त और कोई राजनैतिक समझौता नहीं चाहते। यदि उस बारे में वे वास्तव में गम्भीर होते तो वे निर्णय को एक अथवा दूसरे कारण से निलम्बित करने की बजाय शान्ति मिशन के पिछली जनवरी के नवीनतम प्रस्तावों को मान लेते। परन्तु नागा विद्रोही तथाकथित युद्ध-विराम की अवधि का प्रयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। उन्होंने नागा सैनिकों की संख्या 2,000 से बढ़ाकर अब 10,000 कर ली है, दूसरे, पाकिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद प्राप्त कर लिया है। तीसरे, पाकिस्तान में, और अब चीन के साथ दुर्भिसन्धि द्वारा, नागाओं को गोरीला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चोथे, उन्होंने अपनी गतिविधियां मणिपुर और त्वेनसांग क्षेत्र तक बढ़ा ली है।

मुझे तथाकथित शान्ति मिशन के सदस्यों की मनोवृति की समझ नहीं आती है। उन्होंने अपने नवीनतम प्रस्तावों में नागा संघीय सरकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दे दी है।

बातचीत का आधार क्या है। श्री फिज़ो के भाई, श्री केवी याली को उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए लन्दन भेजा गया था। सरकार नहीं जानती कि श्री फिज़ो ने अपने भाई के माध्यम से विद्रोही नागा नेताओं को क्या सन्देश भेजा है।

नवीनतम प्रस्ताव यह है कि शान्ति मिशन के तीन सदस्य श्री फिज़ो से विचार विमर्श के लिये मिलें। मुझे समझ नहीं आता कि इस प्रस्ताव के पीछे क्या तर्क है। श्री फिज़ो ने 1961 में ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर ली है और अब वह विदेशी नागरिक हैं। क्या यह बात नैतिक तथा

---

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-hour discussion

कानूनी दृष्टि से ठीक है कि किसी विदेशी से ऐसे क्षेत्र के लिए बातचीत की जाये, जो कि भारत का अंग है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करना ठीक है जिसने एक बार भी भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत कार्य करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। लन्दन से वापसी पर श्री फिज़ो के भाई ने कहा था कि नागालैंड सम्बन्धी श्री फिज़ो के विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पादरी माईकेल स्काट के बारे में जितना कम कहा जाये, उतना ही अच्छा है। उन्होंने भारतीय सुरक्षा सेनाओं के विद्रोही नागाओं पर किये गये तथाकथित अत्याचारों के बारे में बहुत बड़ा प्रतिवेदन तैयार किया है। यदि पादरी माईकल स्काट नागा विद्रोहियों द्वारा निर्दोष नागाओं पर किये गये अत्याचारों के बारे में भी एक प्रतिवेदन तैयार करते तो अच्छा होता। मैं यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति नागालैंड में शान्ति चाहता है परन्तु जिस प्रकार शान्ति मिशन तथा नागा फैडरल सरकार शान्ति चाहते हैं, उसका एक ही तरीका है तथा कथित आत्मनिर्णय।

प्रतिरक्षा की दृष्टि से अब समय आ गया है कि सरकार विद्रोही नागाओं के साथ निरर्थक बातचीत समाप्त करे और उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करे जैसा कि सभी सरकारें दुराग्राही नागरिकों के साथ करती हैं।

एक प्रस्ताव यह भी है कि एक नागा प्रतिनिधि-मण्डल प्रधान मंत्री से मिले। नागा विद्रोहियों के प्रधान मंत्री को मिलने से पहले उन्हें यह बता दिया जाना चाहिये कि वे इस बात का विश्वास दिलायें कि वे भारतीय संविधान के ढांचे के अन्दर रह कर काम करने के लिये तैयार हैं, प्रधान मंत्री केवल तब ही उन्हें मिल सकते हैं। अन्यथा नहीं मिल सकते।

अब समय आ गया है कि सरकार नागा फैडरल सरकार को यह आदेश दे कि वह अपनी सरकार को यथासंभव शीघ्र समाप्त कर दें क्योंकि भारत के किसी भी भाग में दो सरकारें नहीं हो सकतीं।

शान्ति मिशन को यह भी बता दिया जाना चाहिये कि फिज़ो को कोलम्बो या बर्मा में मिलने सम्बन्धी उनके प्रस्तावों को कार्यरूप नहीं दिया जा सकता। यदि ज़रूरी हो तो सरकार को उन्हें यह भी बताना चाहिये कि यदि वे उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो उन्हें नागालैंड से निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : यह बात ध्यान में रखते हुये कि श्री फिज़ो ने भारत को अपनी भूमि नहीं माना है, भारत सरकार को उन से बातचीत नहीं करनी चाहिये। इस मामले को सीधे विद्रोहियों के साथ हल क्यों न किया जाये।

Shri Kishan Pattnayak (सम्बलपूर) : Have the Government come to know that the Nagaland problem is an offshoot of British diplomacy.

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : ऐसा मालूम हुआ है कि नागा विद्रोहियों के दो गुट हैं। क्या फिज़ो का भारत आना उनके दोनों गुटों को स्वीकार होगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या सरकार यह जानती है कि पादरी माईकल स्काट नागालैंड के बारे में फिज़ो के विचारों को ही क्रियान्वित कर रहे हैं। यदि हां, तो क्या सरकार शान्ति मिशन से उन्हें निकाल रही है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : मूल भाषण देने वाले माननीय सदस्य ने शान्ति मिशन तथा नागालैण्ड की स्थिति का विस्तृत ब्योरा दिया है। मैं यह मानती हूं कि शान्ति वार्ता में नागाओं के शत्रुतापूर्ण रवैय्ये के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है। परन्तु यह ठीक नहीं है कि शान्ति मिशन एक निश्चित कार्य प्रणाली अपनाने में असफल रहा है। विद्रोही नागाओं को आरम्भ में ही यह बता दिया गया था कि जो कोई भी समझौता होगा, वह भारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत होगा। शान्ति मिशन के 20 दिसम्बर, 1964 के प्रस्ताव के बारे में बहुत गलतफहमी दिखाई देती है। समझौते के बारे में भारत सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। नागा फैडरल सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार हो सकते हैं परन्तु भारत सरकार किसी ऐसी बात से बाध्य नहीं है जो सरकारी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के अनुरूप नहीं है।

विराम सन्धि के उल्लंघन किये गये हैं। सरकार यह जानती है और हम यह सुनिश्चित करने के उपाय कर रहे हैं कि यह उल्लंघन फैलने न पाये। कुछ क्षत्रों में कर लिये जा रहे हैं। हम विद्रोही नागाओं की गतिविधियों की सावधानी से देख रख कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं कि विराम सन्धि का उल्लंघन न हो।

जहां तक शान्ति मिशन का सम्बन्ध है, उसका गठन भारत सरकार ने नहीं किया है। भारत सरकार इस मिशन पर खर्च नहीं कर रही है। भारत सरकार का सम्बन्ध तो केवल इस बात से है कि नागालैण्ड के हमारे सीमावर्ती राज्य में शान्ति पुनः स्थापित की जाये। इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है कि वहां पर शान्ति पुनः स्थापित करने के लिए प्रत्येक संभव अवसर दिये जाये।

श्री बसुमतारी ने ठीक कहा है कि नागा विद्रोहियों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग के लोग शान्ति का महत्व समझ गये हैं। व उन लोगों की नीतियों को जारी नहीं रखना चाहते जो युद्ध जारी रखने के पक्ष में हैं।

यदि श्री फिज़ो बातचीत करना चाहते ह तो उन्हें भारत आना होगा। भारत सरकार ने केवल उन्हें अच्छे आचरण का वचन दिया है। यह ठीक है कि एक एसा प्रस्ताव हैं कि विद्रोही नेता प्रधान मंत्री से मिलें परन्तु इसके लिये कोई समय निश्चित नहीं किया गया है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 16 नवम्बर, 1965/25 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Tuesday, November 16, 1965/Kartika 25, 1887 (Saka).

GIPN—S4—50 Lok Sabh/65—22-8-66